VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स

Workbook

जून 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

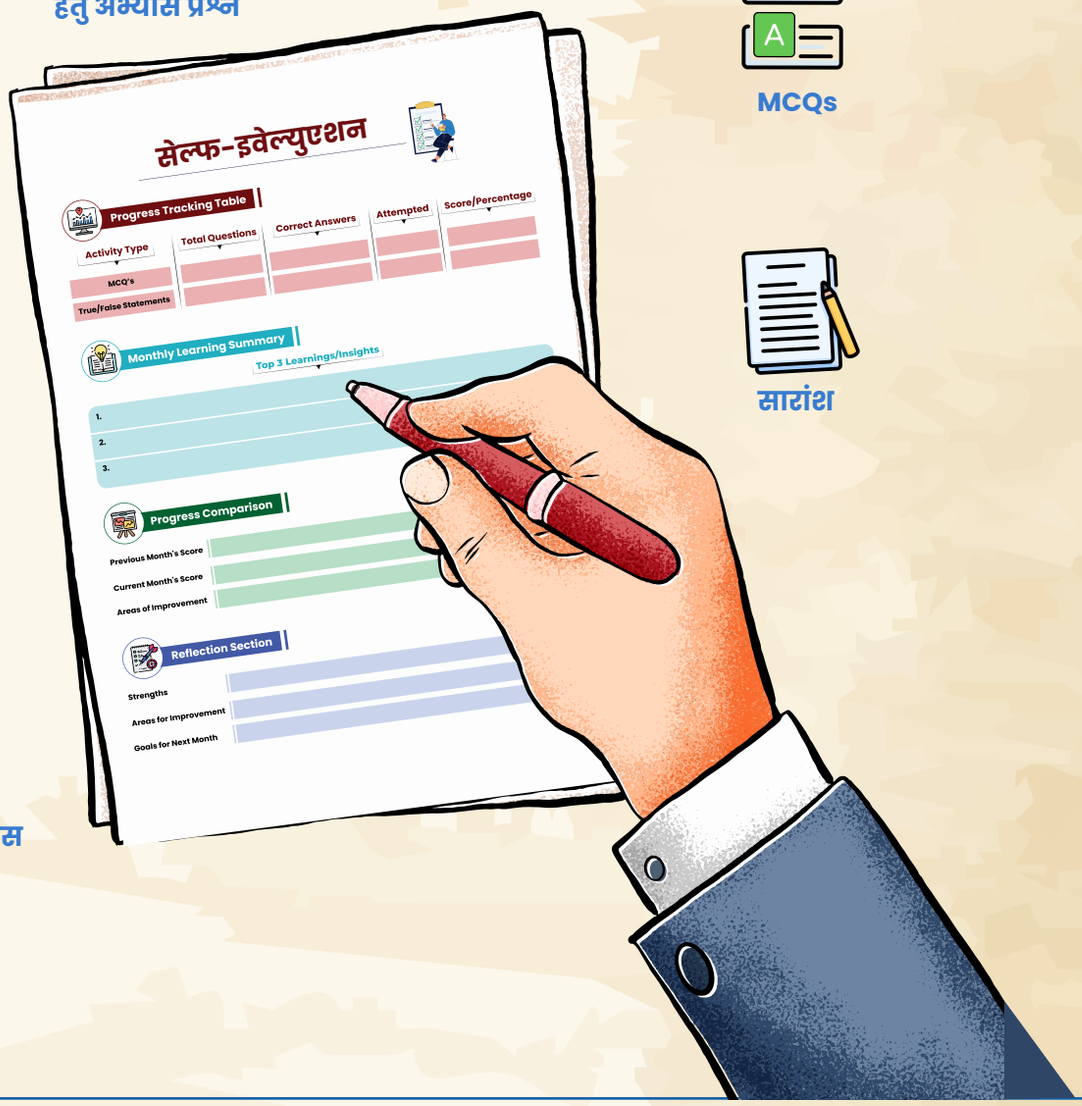

सारांश

स्मरणीय तथ्य

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

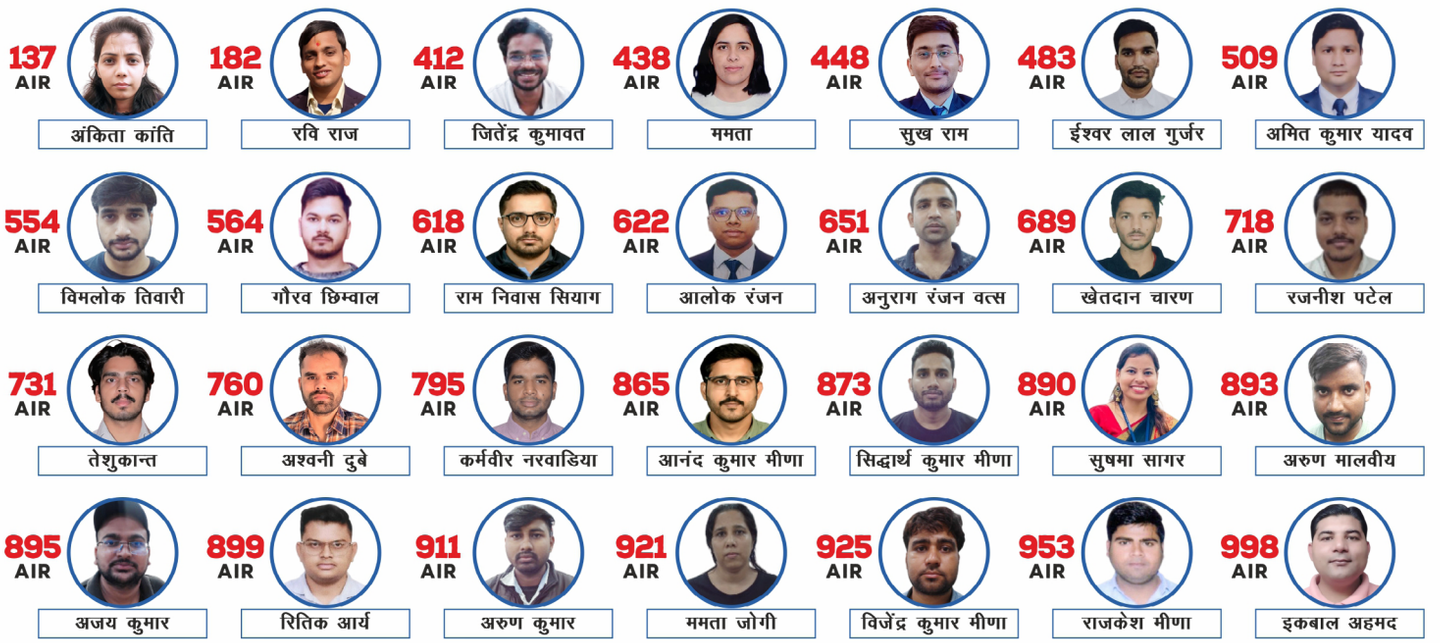

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

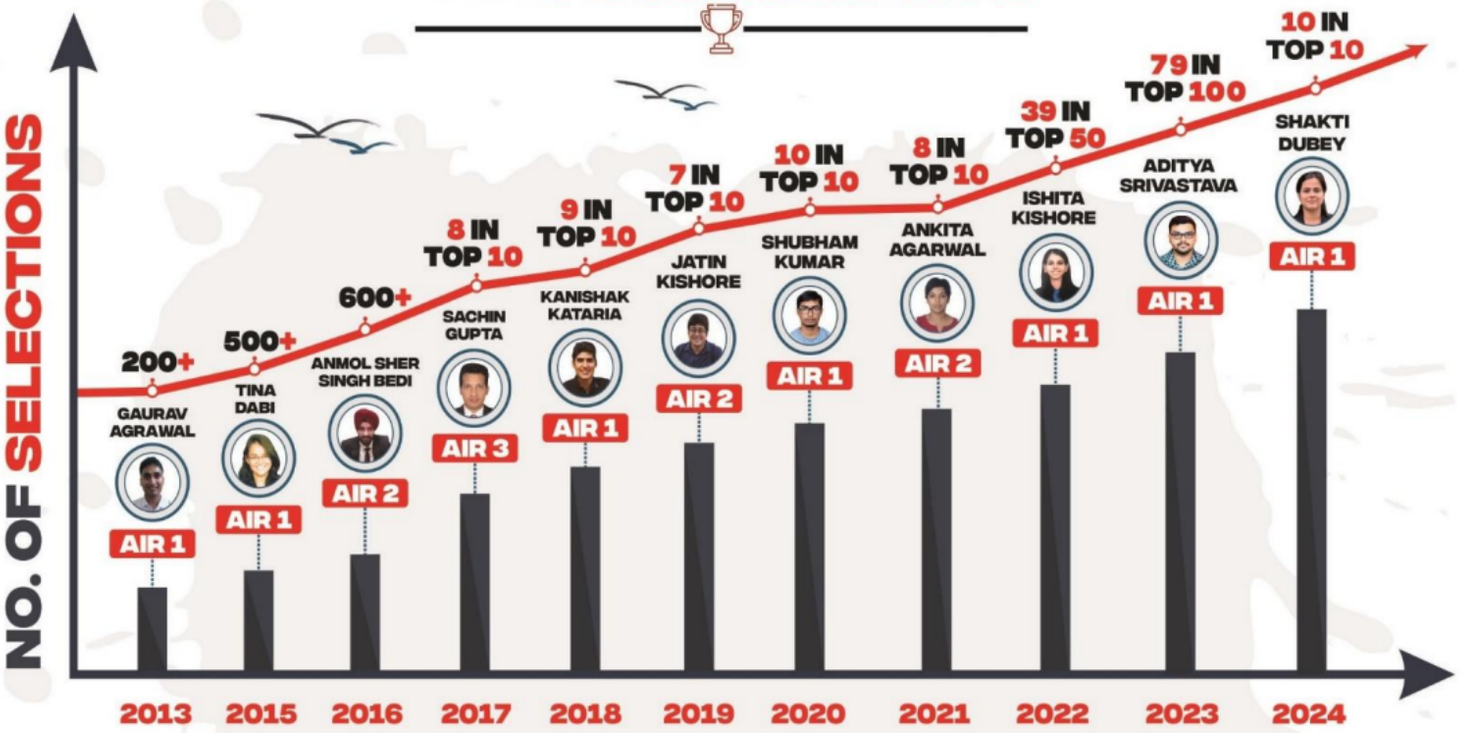

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE)

1.1. आपातकाल के 50 साल (50 YEARS OF EMERGENCY) 6

1.2. व्यक्तित्व अधिकार (PERSONALITY RIGHTS) 7

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 8

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भारत और शंघाई सहयोग संगठन {INDIA AND SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)} . 9

2.2. चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ (CHINA-LED TRILATERAL NEXUS) 10

2.3. इजरायल-अमेरिका-ईरान संघर्ष (ISRAEL-US-IRAN CONFLICT) 10

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) (GROUP OF SEVEN: G-7) . . 11

2.5. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार {WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) REFORMS} 12

2.6. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES: ECOWAS) 13

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 14

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन (RURAL INDIA: THE NEW ENGINE OF INDIA'S CONSUMER MARKET) 18

3.2. भारत में क्विक कॉमर्स (QUICK COMMERCE IN INDIA) 18

3.3. विमानन सुरक्षा (AVIATION SAFETY) 19

3.4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (ASSET MONETIZATION) . . . 20

3.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FOREIGN DIRECT INVESTMENT: FDI) 21

3.6. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (FINANCING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 22

3.7. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) {ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION (AMRUT)} 24

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 24

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA (FIFTH-GENERATION FIGHTER JET AMCA) 27

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 28

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. कृषि वानिकी (AGROFORESTRY) 29

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISASTER RESILIENT INFRASTRUCTURE 2025) 30

5.3. समुद्री आपदाएं (MARITIME DISASTERS) 32

5.4. भीड़ आपदा प्रबंधन (CROWD DISASTER MANAGEMENT) 33

5.5. भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BHARAT FORECAST SYSTEM) 34

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 35

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. सांस्कृतिक विनियोग (CULTURAL APPROPRIATION) 40

6.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं (TIER-2 INFLUENCERS REDEFINING CULTURAL CAPITAL IN DIGITAL INDIA) . 41

6.3. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधार (IMPROVEMENT IN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS) 41

6.4. मैनोस्फीयर (MANOSPHERE) 42

6.5. सशस्त्र बलों में महिलाएं (WOMEN IN ARMED FORCE) 43

6.6. वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 (GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC 2025) 44

6.7. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 (GLOBAL GENDER GAP 2025) 44

6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 45

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. एक्सिओम-4 मिशन (AXIOM-4 MISSION) 47

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 48

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि (INS KAUNDINYA AND TANKAI) 51

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS) 52

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य (VALUES OF MAHATMA GANDHI AND SREE NARAYANA GURU) 53

9.2. एकात्म मानववाद (INTEGRAL HUMANISM) 53

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1 भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF ELECTRIC PASSENGER CARS IN INDIA) 55

11. क्विक फैक्ट्स

12. एक्टिविटी (Activities)

12.1. MCQS 60

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (TRUE/FALSE STATEMENTS) 63

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (MAINS PRACTICE QUESTIONS) 63

13. उत्तर और व्याख्या (Answers and Explanation)

13.1. MCQ के उत्तर और व्याख्या (MCQS ANSWER AND EXPLANTION) 65

13.2 ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स के उत्तर (TRUE/FALSE ANSWERS) 67

13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण . . 67

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

वर्कबुक का जून संस्करण आपकी UPSC तैयारी में सहायक बनने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है। इसमें सुनियोजित, विश्लेषणात्मक और परीक्षा-केंद्रित करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन के बाद वर्कबुक पर काम करने से आपकी जटिल मुद्दों को याद रखने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता मजबूत होगी, जो परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल हैं।

इस माह की वर्कबुक में भारत और विश्व को आकार देने वाले कई प्रमुख विषयों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। **राजव्यवस्था खंड** में, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदत्त आर्टिकल भारत के संवैधानिक इतिहास के एक निर्णायक अध्याय की याद दिलाता है। व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और नार्को-विश्लेषण की वैधता जैसे वर्तमान मुद्दे, डिजिटल युग में कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बदलते संबंधों को उजागर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड में, अशांत वैश्विक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक संतुलन साधने की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही, इसमें चीन की विस्तारित त्रिपक्षीय कूटनीति से निपटने से लेकर G7 और WTO सुधार वार्ताओं में सहभागिता आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक आर्टिकल यह रेखांकित करता है कि भारत कैसे अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए वैश्विक मानदंडों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।

अर्थव्यवस्था खंड में भारत के उपभोग रुझानों में हो रहे अहम बदलावों को रेखांकित किया गया है, जिन पर ग्रामीण विकास की गति, क्विक कॉमर्स का विस्तार, परिसंपत्ति मुद्रीकरण की जटिलताएँ और FDI अंतर्वाह का प्रभाव है। ये रुझान बदलते बाजार व्यवहार को तो दर्शाते ही हैं, साथ ही स्थिरता, समानता और नीतिगत प्रतिक्रिया से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हमने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरणीय चुनौतियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रही ऐसी प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

1. **मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्ख़ियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इस खंड का उद्देश्य एक्टिविटी में गहराई से जाने से पहले आपकी समझ की आधारशिला तैयार करना है।
2. **स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक:**

MCQs: महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।

ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स: मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।

एथिक्स केस स्टडी: हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।

उत्तर और व्याख्या: इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रू/फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

4. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, और इसे अपनी UPSC तैयारी की यात्रा में एक भरोसेमंद माध्यम बनाएं। एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और सही साधनों के साथ आप न केवल करेंट अफेयर्स में दक्षता हासिल करेंगे, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास भी विकसित करेंगे।

हार्दिक शुभकामनाएं
करेंट अफेयर्स टीम
VisionIAS

"इतिहास हमें इस बात से परखेगा कि हमने बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में कितना सार्थक परिवर्तन किया।"

– नेल्सन मंडेला

1.1. आपातकाल के 50 साल (50 YEARS OF EMERGENCY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

25 जून, 1975 को भारत में **राष्ट्रीय आपातकाल** की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च, 1977 तक प्रभावी रहा था। इस वर्ष (2025) इस घटना को **50 साल** पूरे हुए हैं।

1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था?

- **सामाजिक अशांति:** सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और आंदोलन हो रहे थे। इनमें **जयप्रकाश नारायण** के नेतृत्व में हुआ **जेपी आंदोलन** विशेष था।
- **आर्थिक संकट:** 1971 के युद्ध के पश्चात्।
- **राजनीतिक कारण:** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने **'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण'** वाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया।

आपातकाल के दौरान प्रमुख संवैधानिक संशोधन:

- **38वां संशोधन (1975):** इस संशोधन ने **राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर** कर दिया। इसके तहत राष्ट्रपति का निर्णय **'अंतिम एवं निर्णायक'** होगा।
- **39वां संशोधन (1975):** इसने **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों** को तय करने के तरीके में बदलाव किया।
  - अब ये विवाद संसद द्वारा निर्धारित किसी **प्राधिकरण** द्वारा तय किए जाने थे।
- **42वां संशोधन (1976):**
  - **अनुच्छेद 31C** के तहत **राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता** दी गई।
  - **सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स** की शक्तियों को कई तरह से कम किया गया:
    - **संविधान में अनुच्छेद 32A** जोड़ा गया, जिसने **सुप्रीम कोर्ट** को राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया। (हालांकि, इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था)
    - **अनुच्छेद 131A और 226A** के तहत **हाई कोर्ट्स** को केंद्र सरकार के कानूनों की समीक्षा से वंचित किया गया था।
  - **लोक सभा** का कार्यकाल **5 साल से बढ़ाकर 6 साल** कर दिया गया था।

आपातकाल के बाद के सुधार

- **शाह आयोग 1977:** बंध्याकरण, सरकारी कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने आदि जैसी दुर्व्यवहारों की जांच करना।
- **44वां संशोधन अधिनियम (1978)** :
  - **अनुच्छेद 352 के अंतर्गत परिवर्तन:**
    - दुरुपयोग को रोकने के लिए "आंतरिक अशांति" के बजाय "सशस्त्र विद्रोह" पर आधारित आपातकाल लागू किया गया।
    - राष्ट्रपति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सहमती अनिवार्य कर दी गई।
    - एक माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया।
- **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहेंगे।
  - **संपत्ति के अधिकार** को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर **अनुच्छेद 300A** के तहत एक सामान्य **संवैधानिक अधिकार** बना दिया गया
- **अनुच्छेद 257A का निरसन:** राज्यों में सेना तैनात करने की केंद्र की शक्ति समाप्त की गई।
- **लोक सभा का कार्यकाल:** 6 साल से घटाकर वापस **5 साल** कर दिया गया।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की **समीक्षा करने की न्यायिक शक्ति बहाल की गई**।

निष्कर्ष

- आपातकाल हमें याद दिलाता है कि सत्ता अधिकारों का दमन कर सकती है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है, ताकि संवैधानिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताएं बनी रहें।

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के बारे में

- **आधार:** युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह।
- **उद्घोषणा:** केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है।
- **अनुमोदन:** दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर।
- **बहुमत:** दोनों सदनों में विशेष बहुमत अनिवार्य है।
- **अवधि:** छह महीने, हर 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे **अनिश्चितकाल तक बढ़ाया** जा सकता है।
- **निरसन:** राष्ट्रपति या लोक द्वारा सभा का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव

- **केंद्र-राज्य संबंधों पर:**
  - केन्द्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है।
  - संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है।
  - राजस्व वितरण में राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- **विशायिकाओं पर:** लोक सभा /राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसे आपातकाल के बाद **6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया** जा सकता है।
- **मौलिक अधिकारों पर:**
  - अनुच्छेद 19 केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण के दौरान निलंबित हो जाता है (अनुच्छेद 358)।
  - अन् य अधिकार (20, 21 को छोड़कर) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है(अनुच्छेद 359)।

1.2. व्यक्तित्व अधिकार (PERSONALITY RIGHTS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से **सद्गुरु जग्गी वासुदेव** के व्यक्तित्व अधिकारों को **AI** के जरिए वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया।

व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में

- व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे **नाम, छवि, आवाज़, शक्ल-सूरत, और विशिष्ट हाव-भाव या लक्षणों** के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में **वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक** दोनों पहलू शामिल हैं।
- **भारत में किसी भी कानून में** व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
- **व्यक्तित्व अधिकारों के घटक:**
  - **पब्लिसिटी का अधिकार:** किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग से बचाना; आंशिक रूप से ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अधिनियमों द्वारा शासित होता है।
  - **निजता का अधिकार:** अनधिकृत सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को रोकता है; अनुच्छेद 21 और पुट्टस्वामी निर्णय के तहत बरकरार रखा गया।
- **भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार:** कोई विशिष्ट वैधानिक मान्यता नहीं है।
  - हालांकि, **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950** महात्मा गांधी और प्रधान मंत्री की छवियों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **दीपा जयकुमार बनाम ए. एल. विजय मामला (2019):** व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता जीवनकाल के बाद समाप्त हो जाती है।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएं

- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामला, 2011 (दिल्ली हाई कोर्ट):** इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी।
- **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस (मद्रास हाईकोर्ट, 2015):** प्रसिद्धि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह एक समान है।

निष्कर्ष

AI द्वारा निर्मित फेक कंटेंट की सक्रिय निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा और सरकारी एजेंसियों का सशक्तीकरण समय की मांग है।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला (2011):** दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी।
- **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस (मद्रास हाईकोर्ट, 2015):** किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके **व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन** है।

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

1.3.1. नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता (CONSTITUTIONAL VALIDITY OF NARCO TESTS)

सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें **सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को-टेस्ट की अनुमति** दी गई थी।

नार्को-एनालिसिस टेस्ट के बारे में

- यह **पूछताछ का एक तरीका** है जिसमें किसी अपराध के **संदिग्ध को साइकोएक्टिव दवा** दी जाती है, ताकि उसकी सोचने-समझने की शक्ति या अपने भले-बुरे का निर्णय करने की क्षमता को दबाया जा सके।
- **सोडियम पेंटोथॉल** नामक यह दवा आम तौर पर सर्जरी में सामान्य एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

- **अनैच्छिक नार्को टेस्ट: अनुच्छेद 20(3)** (आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध अधिकार) और **21** (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन, **बलपूर्वक नार्को-टेस्ट कराना गैरकानूनी**।
- **स्वैच्छिक नार्को-टेस्ट दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता:**
  - हालांकि, यदि टेस्ट से कोई **नई जानकारी प्राप्त होती है**, तो उसे **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** के तहत स्वीकार किया जा सकता है।
- **नार्को -टेस्ट कराने का सीमित अधिकार:** आरोपी को नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने का **आत्यंतिक (पूर्ण) अधिकार नहीं** है।

1.3.2. भारतीय गुणवत्ता परिषद (QUALITY COUNCIL OF INDIA: QCI)

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने **नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर** में **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के नए एकीकृत मुख्यालय** का उद्घाटन किया।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में

- **स्थापना:** 1996 में एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के रूप में स्थापित।
- **मिशन:** भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अभियान का नेतृत्व करना।
- **गैर-लाभकारी संगठन (NPO): यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के** तहत पंजीकृत एक NPO है ।
- **PPP मॉडल:** इसे **भारत सरकार तथा तीन प्रमुख उद्योग संघों - एसोचैम, CII, और फिक्की (FICCI) - का समर्थन** प्राप्त है।
  - **गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों** के लिए **DPIIT** (वाणिज्य मंत्रालय) को **नोडल एजेंसी बनाया गया।**
- **अध्यक्ष:** QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत की सिफारिश पर **प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।**
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) में भूमिका: स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।**

QCI के प्रमुख उद्देश्य

- राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान का नेतृत्व करना।
- सरकारों, संस्थानों और उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमताओं का विकास करना।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों का विकास, स्थापना एवं संचालन करना।
- स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT) को दूर करने की क्षमताओं का विकास करना।

1.3.3. ECINET ऐप (ECINET APP)

निर्वाचन आयोग (ECI) ने **केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल** उपचुनावों के दौरान नए **ECINET डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** का उपयोग किया।

फॉर्म 17C के बारे में

- इसका पहला भाग निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है: मतदान केंद्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता पंजी (फॉर्म 17A) में दर्ज कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, आदि।
- इसका दूसरा भाग **उम्मीदवारों के नाम और उन्हें प्राप्त कुल मतों जैसी जानकारी** प्रदान करता है।
- **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961** के तहत, पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को **फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य** होता है।

ECINET ऐप के बारे में

- **ECINET समय पर मतदाता मतदान की रिपोर्टिंग के लिए एक नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है।**
- **मुख्य विशेषताएं: लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा, सटीक डेटा सुनिश्चित करना, इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना।**
  - **इंडेक्स कार्ड** मतदान के बाद जारी की जाने वाली **गैर-सांविधिक** प्रकृति की रिपोर्ट है जो निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय विस्तृत चुनावी डेटा प्रदान करती है।

1.3.4. आदि कर्मयोगी कार्यक्रम (ADI KARMYOGI PROGRAMME)

केंद्रीय **जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम का शुभारंभ** किया।

'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम के बारे में

- **लक्ष्य:** ऐसे प्रेरित **अधिकारियों और चेंजमेकर्स का एक समूह तैयार करना,** जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हों।
- **उद्देश्य:** राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षकों और **मास्टर-ट्रेनर्स** का एक बैच बनाकर लगभग **20 लाख फील्ड-स्तरीय हितधारकों की क्षमता का निर्माण** करना।
- इसमें नागरिक-केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
- **टारगेट:** 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुँचना।

2.1. भारत और शंघाई सहयोग संगठन {INDIA AND SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार** कर दिया।

भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया?

- **आतंकवाद पर दोहरा मापदंड:** दस्तावेज में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का कोई ज़िक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुई उग्रवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था।
- **मुख्य सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं:** भारत हमेशा से मानता आया है कि **शांति** और **आतंकवाद** साथ-साथ नहीं रह सकते, और यह सिद्धांत **बहुपक्षीय मंचों पर भी किसी भी हाल में बदलने योग्य नहीं** है।

SCO फ्रेमवर्क के तहत भारत के लिए रणनीतिक अवसर

- **मध्य एशिया से जुड़ाव:** कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के साथ मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ संबंधों को मजबूत करना।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** कजाकिस्तान से यूरेनियम प्राप्त करना।
- **कनेक्टिविटी में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) को समर्थन।
- **कूटनीतिक चैनल:** चीन और पाकिस्तान के साथ संवाद।

SCO को लेकर भारत की चिंताएं

- **चीन का प्रभुत्व:** चीन SCO को BRI जैसे अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए संचालित करने का प्रयास कर रहा है।
- **विस्तार को लेकर दुविधा:** बेलारूस जैसे नए सदस्य मध्य एशियाई फोकस को कमजोर करते हैं।
- **कमजोर कार्यान्वयन:** जरूरी कार्यकारी गारंटी का अभाव, विचार रखने और मतों की घोषणाएं करने का मंच।
- **पश्चिम विरोधी छवि:** चीन-रूस-ईरान तनाव के बीच पश्चिम-विरोधी समूह के रूप में माना जाता है।

SCO में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग के बीच कैसे संतुलन बनाता है?

- **राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता:** चीन की BRI का विरोध किया।
- **सिद्धांत आधारित भागीदारी:** रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) में सक्रिय।
- **विकासोन्मुखी फोकस:** उदाहरण के लिए- पारंपरिक चिकित्सा और स्टार्ट-अप्स व नवाचार पर सहयोग के लिए SCO का उप-समूह।
- **रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए- भारत और रूस, SCO के मुख्य एजेंडा पर मिलकर काम करते हैं।

वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को नया आकार देने में SCO की भूमिका

- **सामरिक उपस्थिति:** यूरेशिया के 80% तथा वैश्विक जनसंख्या के 42% का प्रतिनिधित्व।
- **आर्थिक ताकत:** वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% का योगदान।
- **पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती:** पश्चिमी नेतृत्व वाले मंचों के सापेक्ष उभरता विकल्प।
- **सुरक्षा संबंधी भूमिका:** अफगानिस्तान साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए **2005 में अफगानिस्तान संपर्क समूह (ACG)** का गठन किया था।

निष्कर्ष

भारत **मध्य एशियाई जुड़ाव के लिए SCO के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है,** तथा अपने मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के प्रभाव से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है।

2.2. चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गठजोड़ (CHINA-LED TRILATERAL NEXUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने छठे 'चीन-दक्षिण एशिया सहयोग मंच' के दौरान अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक** आयोजित की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह चीन द्वारा भारत के पड़ोस में शुरू की गई दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता है। इससे पहले चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच भी इसी तरह की बैठक हुई थी।
- इसके अलावा, कई विश्लेषण **चीन, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच उभरते रणनीतिक गठजोड़ की ओर भी इशारा** कर रहे हैं, जैसा कि पहलगाम संकट के दौरान उनकी समन्वित प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है।
- ये गतिविधियां इस क्षेत्र में **भारत के पारंपरिक प्रभाव** को चुनौती देती हैं। चीन का उद्देश्य **अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक व सामरिक प्रभाव क्षेत्र** बनाना है।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

- **पाकिस्तान:** पाकिस्तान अपने अधिकांश रक्षा आयात के लिए चीन पर निर्भर है।
- **मालदीव:** चीन-मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज और आवास परियोजनाएं।
- **श्रीलंका:** चीन ने हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण किया है और उसे 99 साल के लिए लीज पर लिया है।
- **बांग्लादेश:** चीन बांग्लादेश के लिए रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- **नेपाल:** उदाहरणार्थ, पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित ट्रांस-हिमालयी कनेक्टिविटी परियोजनाएं।

इन त्रिपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले कारक

- **ऐतिहासिक:** पाकिस्तान और चीन दोनों के भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहे हैं।
- **चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति: क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल करने के लिए दक्षिण एशिया में सक्रिय रूप से भू-राजनीतिक मौजूदगी का विस्तार करना।**
- **भारत के विरुद्ध रणनीतिक संतुलन:** बांग्लादेश जैसे देश भारत के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए **चीन के साथ संबंधों का लाभ उठाते हैं।**
- **अवसंरचना कूटनीति:** चीन **भारत के पड़ोसियों को तीव्र गति से और बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास हेतु धन उपलब्ध करा रहा है।**

भारत के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी चिंताएं/ निहितार्थ

- **भू-रणनीतिक घेराबंदी: चीन ने पहले ही 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति के तहत कई सामरिक बंदरगाहों पर पहले ही अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली है।
- **भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय मंचों को कमजोर करना: इससे बिम्सटेक** जैसे भारत समर्थित समूहों का प्रभाव कमजोर हो सकता है।
- **घटता क्षेत्रीय प्रभाव: बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना** में चीन को शामिल करने में रुचि व्यक्त की है।
- **भारत की कनेक्टिविटी संबंधी पहलों पर प्रभाव:** BRI परियोजनाओं को बढ़ावा देने से भारत के नेतृत्व वाले विकल्प जैसे **BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) पहल** और **भारत–मध्य पूर्व –यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है**।

भारत द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति

- **रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से संतुलन: क्वाड** के माध्यम से जापान और अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।
- **विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन:** पड़ोसी देशों के साथ परियोजनाओं के समन्वय के लिए समर्पित विदेश मंत्रालय प्रकोष्ठ की स्थापना।
- **डेवलपमेंट फंड:** बिम्सटेक के अंतर्गत कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए **क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना करना।**
- **RIC के माध्यम से जुड़ाव:** 1990 के दशक के अंत में शुरू हुए **RIC (रूस-भारत-चीन) को फिर से सक्रिय करना।**

निष्कर्ष

त्रिपक्षीय बैठक **दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक अहम घटनाक्रम** है। भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी विदेश नीति को **सक्रिय, समावेशी और संतुलित** बनाए।

2.3. इजरायल-अमेरिका-ईरान संघर्ष (ISRAEL-US-IRAN CONFLICT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने **"ऑपरेशन राइजिंग लायन"** की शुरुआत की। इसके तहत ईरान के परमाणु ढांचे और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर एक बड़ा हमला किया गया।

संघर्ष के प्रमुख घटनाएं

- **इजरायल के हमले:** यह हमला **IAEA के शासी बोर्ड (35 सदस्य देशों)** के उस मतदान के बाद हुआ, जिसमें ईरान को **1974 के समझौते का उल्लंघनकर्ता** घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह 2006 के बाद ऐसा पहला निष्कर्ष था।
- **ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई:** ईरान ने **'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3' शुरू किया**।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी:** अमेरिका ने **"ऑपरेशन मिडनाइट हैमर"** शुरू किया, जिसमें ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों—**नतांज, इस्फ़हान और फोर्डो** पर सटीक हवाई हमले किए गए।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने दोनों पक्षों से अपील की कि **वे कोई उकसाने वाला कदम न उठाएं और फिर से वार्ता की राह पर लौटें।**

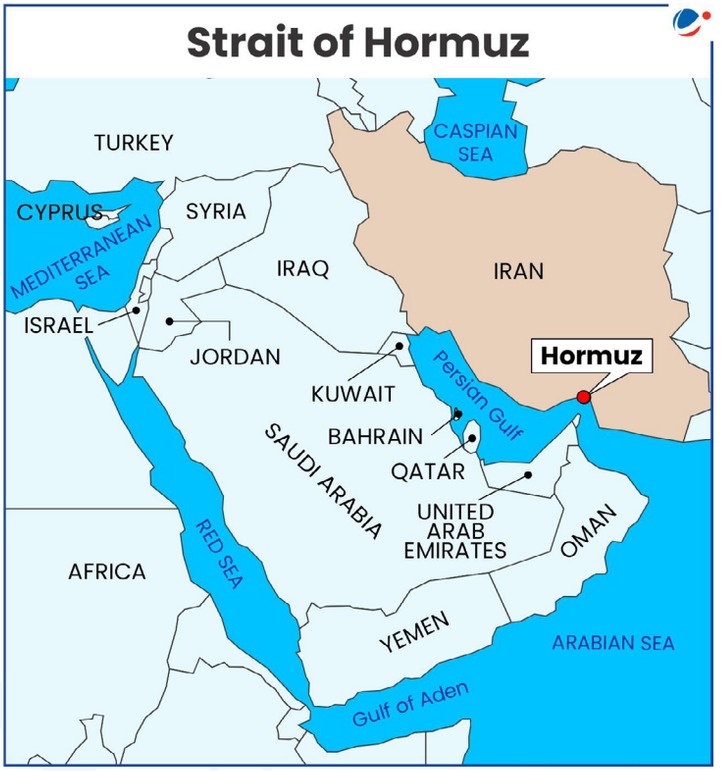

'बराक मागेन' या 'लाइटनिंग शील्ड' के बारे में

- यह **बराक एमएक्स (Barak MX) मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक विशेष संस्करण** है, जिए नौसेना के जहाजों को विभिन्न हवाई खतरों जैसे **ड्रोन** से बचाने के लिए बनाया गया है।
- यह इजरायल की मौजूदा प्रणालियों **आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और भविष्य की लेज़र प्रणाली 'आयरन बीम'** की संपूरक है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव

वैश्विक प्रभाव

- **परमाणु तनाव:** ईरान NPT से बाहर निकल सकता है।
- **व्यापार जोखिम:** होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल, LNG आपूर्ति को खतरा।
- **समुद्र के नीचे बिछी केबल अवसंरचना में बाधा:** डिजिटल अवसंरचना को प्रभावित करता है।
- **शक्ति शून्यता:** पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है।

भारत पर प्रभाव

- **व्यापार में गिरावट:** प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव के कारण ईरान एवं इजरायल के साथ भारत का व्यापार काफी कम हो गया है।
  - **ईरान:** अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ने **ईरान से तेल आयात** रोक दिया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, जो 2017 में **14 बिलियन डॉलर** था, वह 2024 में घटकर **1.4 बिलियन डॉलर** रह गया था।
  - **इज़राइल:** क्षेत्रीय तनाव के कारण **11 बिलियन डॉलर (2022) से घटकर 3.75 बिलियन डॉलर (2024) रह गया है।**
- **भू-राजनीतिक पुनर्संरचना:** यदि ईरान का पतन होता है, तो पश्चिम एशिया **बहुध्रुवीय** से बदलकर **अमेरिका के नेतृत्व वाले एकध्रुवीय** ढांचे में जा सकता है। इससे भारत जैसे गैर-पश्चिमी देशों का इस क्षेत्र में महत्त्व कम हो जाएगा।
  - **इजरायल और ईरान दोनों** के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन की जरूरी है।
- **रणनीतिक संतुलन:** भारत को ऊर्जा, रक्षा और यूरेशियाई कनेक्टिविटी के लिए दोनों देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना होगा।
- **परियोजना में व्यवधान:** चाबहार बंदरगाह, INSTC और IMEC परियोजनाओं पर असर पड़ा।
- **विदेश में भारतीयों की सुरक्षा:** संघर्ष क्षेत्रों में 28,000 से अधिक भारतीय; संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है।

निष्कर्ष

भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** के लिए ईरान और इजरायल दोनों के साथ संबंध बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे बढ़ते तनाव के बीच **मध्यस्थता के संभावित अवसर उपलब्ध होंगे।**

2.4. ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) (GROUP OF SEVEN: G-7)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **कनाडा के कनानस्किस** में आयोजित **51वें G-7 शिखर सम्मेलन (2025)** में एक **आउटरीच देश** के रूप में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर, **भारत-कनाडा ने उच्चायुक्तों को जल्द वापस भेजने पर सहमति** तथा **अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट (EPTA) पर वार्ता पुनः शुरू करने का** निर्णय लेकर द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई है।
- **51वें G-7 शिखर सम्मेलन (2025) की मुख्य घोषणाएं:**
  - **कनानसकीस वाइल्डफायर चार्टर: इसमें पारंपरिक ज्ञान, संधारणीय वन प्रबंधन** सहित "होल ऑफ सोसाइटी" दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
  - **G-7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान: क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को संधारणीय** और भरोसेमंद बनाना ।
  - **AI पर प्रमुख पहलें:** G-7 GovAI ग्रैंड चैलेंज और साझा G-7 AI नेटवर्क (GAIN)।

ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1975 में ऊर्जा संकट के चलते में आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित।
- **विकसित लोकतांत्रिक देशों** का एक अनौपचारिक समूह: फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा।
  - **रूस** 1998-2014 तक इसका सदस्य था (तब इसे **G8 कहा जाता है**), **क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे समूह से निलंबित कर दिया गया था।**
- **उद्देश्य: आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** और **ऊर्जा नीति** जैसे वैश्विक मुद्दों पर वार्षिक बैठकें।

- **वैश्विक सुरक्षा और संघर्षों पर प्रतिक्रिया**
  - **यूक्रेन संकट:** G-7 देशों ने आपस में मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाए और रूस की फ्रीज की हुई परिसंपत्तियों से यूक्रेन को आर्थिक सहायता प्रदान की।
  - **चीन नीति:** G-7 ने ताइवान पर चीन के दबाव की निंदा की, **'वन चाइना पॉलिसी'** काको संदर्भित नहीं किया, BRI को प्रतिसंतुलित करने के लिए PGII की शुरुआत की।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एजेंडों को प्रभावित करता है**: जैसे **संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक**।
  - **टैक्स गवर्नेंस:** न्यायपूर्ण वैश्विक कर नियमों को सुनिश्चित करने के लिए **OECD/G20 समावेशी फ्रेमवर्क का समर्थन करता है।**
  - **मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की स्थापना 1989** में की गई थी।
- **सतत और डिजिटल गवर्नेंस**: **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)** और **हिरोशिमा AI प्रोसेस** नैतिक AI और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है। **G-7 क्लाइमेट क्लब 2050 तक नेट-ज़ीरो को पाने हेतु वैश्विक सहयोग को** बढ़ावा दे रहा है।
- **ग्लोबल साउथ के साथ संलग्नता: भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे** गैर-सदस्यों तक पहुंच के माध्यम से।
- **"लोकतंत्रों का समूह" के रूप में कार्य करता है: 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था'** का समर्थन करने और **चीन और रूस** जैसे सत्तावादी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक साझे प्रतिरोध के रूप में कार्य करने **वाला मुख्य गठबंधन**।

G-7 के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **आर्थिक प्रभुत्व में गिरावट:** 1980 के दशक में G-7 की वैश्विक GDP में लगभग 70% हिस्सेदारी थी, लेकिन 2021 तक यह घटकर लगभग 44% रह गई है। अब उभरती अर्थव्यवस्थाएं विकास का नेतृत्व कर रही हैं।
- **आम सहमति-आधारित निर्णय: निर्णायक कार्रवाई में बाधा आना; उदाहरण के लिए, 51वें** G-7 ने यूक्रेन युद्ध पर ठोस वक्तव्य जारी नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था।
- **कानूनी प्राधिकार का अभाव: स्थायी सचिवालय** या **बाध्यकारी क़ानूनी फ्रेमवर्क के** बिना अनौपचारिक मंच प्रवर्तनीयता को सीमित करता है।
- **ग्लोबल साउथ का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: इसमें भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया** और **अफ्रीकी संघ** जैसी प्रमुख उभरती शक्तियां शामिल नहीं हैं।
- **वैकल्पिक समूहों से प्रतिस्पर्धा: ब्रिक्स प्लस** बेहतर प्रतिनिधित्व का विकल्प प्रदान करता है।

G-7 में भारत के रणनीतिक हित

- **रणनीतिक संतुलन: विकसित पश्चिमी देशों** और **विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के बीच सेतु के रूप में।**
- **आर्थिक सहयोग:** विकासशील देशों में अवसंरचना में निवेश के लिए **G-7 की PGII** का प्रबल समर्थक।
- **लोकतांत्रिक पहचान**: भारत का लोकतंत्र और **चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का** दर्जा इसकी आवाज को प्रभावशाली बनाता है।
- **द्विपक्षीय वार्ताओं का मंच:** भारतीय प्रधान मंत्री ने कनाडा के प्रधान मंत्री से भेंट कर बिगड़ते संबंधों को सुधारने की कोशिश की।

निष्कर्ष

G-7 देशों को आज की वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रासंगिक अधिक समावेशी एजेंडा तय करना चाहिए। यह भारत के लिए एक **अवसर** है, जिसमें वह अधिक **न्यायपूर्ण और समावेशी निर्णय प्रक्रिया** का समर्थन कर सकता है, और **ग्लोबल साउथ** और **विकसित देशों** के बीच एक **सेतु** की भूमिका निभा सकता है।

2.5. विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार {WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) REFORMS}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **2026 में कैमरून** में होने वाले **14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** से पहले **पेरिस** में हुई एक **उच्च स्तरीय लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक** के दौरान विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों की मांग की।

विश्व व्यापार संगठन के बारे में

सचिवालय: जिनेवा

उत्पत्ति :
- 1995 में **मारकेश समझौते के बाद** स्थापित।
- **इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) का स्थान लिया है।**
- **1986 से 1994 तक चली उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामस्वरूप WTO का गठन हुआ।**

कार्य: व्यापार समझौतों का प्रशासन, व्यापार वार्ता के लिए मंच, व्यापार विवादों का निपटारा, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना।

सदस्य: 166, जिनका **वैश्विक व्यापार में 98% हिस्सेदारी है।** भारत 1995 से इसका सदस्य है।

निर्णय प्रक्रिया: **आम सहमति** पर आधारित।

सचिवालय: जिनेवा .

WTO के प्रमुख समझौते		
वस्तुएं	**सेवाएं**	**बौद्धिक संपदा**
➲ **समझौता**: प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) ➲ **विषय**: वस्तुओं के लिए प्रशुल्क और कुछ कृषि वस्तुओं हेतु प्रशुल्क एवं कोटा पर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं। ➲ **अतिरिक्त जानकारी/ मार्गदर्शक सिद्धांत:** ➜ कृषि पर समझौता ➜ सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी उपायों पर समझौता ➜ एंटी-डंपिंग समझौता ➜ व्यापार-संबंधी निवेश उपाय (TRIMs)	➲ **समझौता**: सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) ➲ **विषय:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली सभी सेवाएं (जैसे, बैंकिंग, पर्यटन, दूरसंचार) शामिल हैं। ➲ **अतिरिक्त जानकारी/ मार्गदर्शक सिद्धांत:** ➜ सर्वाधिक-तरजीही राष्ट्र (MFN) व्यवहार ➜ बाजार पहुंच ➜ राष्ट्रीय व्यवहार	➲ **समझौता**: ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता) ➲ **विषय:** कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक संकेत आदि शामिल हैं। ➲ **अतिरिक्त जानकारी/मार्गदर्शक सिद्धांत:** ➜ राष्ट्रीय व्यवहार ➜ MFN व्यवहार

WTO के लिए भारत के सुधार एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत का त्रि-आयामी सुधार एजेंडा:**
  - **बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाली गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs) से निपटना।**
  - **गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न विकृतियों का समाधान।**
  - WTO के विवाद निपटान तंत्र को फिर से सक्रिय करना।
- **JSIs (जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्स) या प्लूरिलेट्रल समझौते:** कुछ देश चाहते हैं कि JSIs को WTO के व्यापक बहुपक्षीय ढांचे में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि इससे WTO की एकता और बहुपक्षीय प्रणाली कमजोर हो सकती है।
- **खाद्यान्न भंडारण के लिए स्थायी समाधान:** भारत 2013 के **"पीस क्लॉज"** से परे एक स्थायी WTO समाधान चाहता है। पीस क्लॉज सार्वजनिक भंडारण के तहत सब्सिडी को कानूनी चुनौतियों से बचाता है।
- **अत्यधिक मछली पकड़ने के समझौते पर चिंताएँ**
  - WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति के अभाव में विश्व व्यापार संगठन मात्स्यिकी पर समझौता (2022) अभी तक लागू नहीं हो पाया है।
  - भारत **इस समझौते का हिस्सा नहीं है, जिससे निम्नलिखित चिंताएं उत्पन्न होती हैं: 'विशेष और विभेदित व्यवहार' (SDT)** के तहत विकासशील देशों के **लिए 25 वर्ष की संक्रमण अवधि।**

WTO में विद्यमान कुछ और विवादित मुद्दे:

- **'विकास की स्थिति' का कोई वस्तुनिष्ठ मापदण्ड नहीं:** भारत **SDT किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करता है**, जबकि अमेरिका चीन के विकासशील देश होने के दावों का विरोध करता है।
- **नए उभरते मुद्दे** :
  - **विनियामक बदलाव:** यूरोपीय संघ का **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र** निम्न-मध्यम आय वाले देशों पर असमान रूप से प्रभाव डालेगा।
  - **भू-राजनीतिक बदलाव:** अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध।
  - **नवीन अवधारणाएँ:** डेटा गोपनीयता, सीमा पार डेटा प्रवाह, डिजिटल सेवाओं पर कराधान, जलवायु परिवर्तन।

आगे की राह

- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **NTBs** पर निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और दुरुपयोग कम हो।
- **बहुपक्षीय समझौतों** के कारण होने वाले विखंडन को रोकने के लिए स्पष्ट नियम विकसित करना।
- वैकल्पिक अंतरिम **विवाद समाधान मॉडल तैयार करना।**
- **राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों** और औद्योगिक सब्सिडी से होने उत्पन्न वाली व्यापार विकृतियों का समाधान करना।
- **"साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" जैसे सिद्धांतों को अपनाना** चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर अनुचित व्यापार नियमों का दबाव न पड़े।

2.6. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES: ECOWAS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ECOWAS ने इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई।

ECOWAS के बारे में

- **स्थापना: 28 मई 1975 को लागोस की संधि** के माध्यम से **15 पश्चिम अफ्रीकी देशों** द्वारा स्थापित।
- **मुख्यालय: अबुजा, नाइजीरिया**।
- **क्षेत्रीय समूह:** ECOWAS में **12 पश्चिम अफ्रीकी देश शामिल हैं** (जून 2025)। इसके सदस्य देशों में बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो शामिल हैं।
- **उद्देश्य: पश्चिम अफ्रीका में** एक आर्थिक संघ के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना। ECOWAS ने **1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और जनवरी 2015 में एक साझी बाह्य प्रशुल्क व्यवस्था अपनाई थी।**

भारत-ECOWAS संबंध

- **राजनयिक संबंध: भारत 2004** में ECOWAS का **पर्यवेक्षक** बना था। ECOWAS **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी** सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत, ECOWAS सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बीच समझौता ज्ञापन** के माध्यम से पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है ।
- **आर्थिक सहयोग: 2006 में** भारत ने इस समूह को **2002-03** से शुरू किए गए **फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के** पूरक के रूप में **250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) दिया था**।

निष्कर्ष

ECOWAS अपने छठे दशक में प्रवेश कर रहा है, जहां वह एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। एकीकरण, शांति स्थापना और मानव विकास में इसकी उपलब्धियां सराहनीय हैं, लेकिन आंतरिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों से जुड़ाव की कमी इसकी भावी प्रासंगिकता को चुनौती दे रहे हैं।

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

2.7.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN SECURITY COUNCIL: UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है।

- ये देश हैं: **बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया।**

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

- **स्थापना**: इसकी स्थापना **1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से** हुई है। यह **संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक** है।
- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
- **सदस्य: 5 स्थायी** सदस्य (P5) और **10 अस्थायी** सदस्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रस्ताव (2024)

- **प्रस्तावित करने वाले: G4 राष्ट्र – भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान।**
- **आवश्यकता क्यों:** वीटो शक्ति का दुरुपयोग, सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और मौजूदा स्थायी सदस्यता प्रणाली वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
- **प्रस्तावित सुधारों के प्रमुख प्रावधान: अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोप** के लिए **6 नई स्थायी सीटों** के माध्यम से सभी क्षेत्रों के **समान प्रतिनिधित्व के साथ 11 स्थायी** और **14-15 अस्थायी** सदस्य। **नए स्थायी सदस्यों के लिए शुरुआत में कोई वीटो नहीं होगा, 15 वर्षों** के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

स्थायी सदस्य, वीटो अधिकार (5)

- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका

अस्थायी सदस्य (10), दो वर्षों का कार्यकाल

- अफ्रीका (3)
- एशिया (2)
- लैटिन अमेरिका (2)
- पश्चिमी यूरोप व अन्य देश (2)
- पूर्वी यूरोप (1)

प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।

यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है, जो ऐसे निर्णय ले सकती है, जिसे सभी सदस्य देशों को मानना अनिवार्य होता है।

अन्य संबंधित सुर्खियां

- पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति (CTC) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

तालिबान प्रतिबंध समिति (TSC) के बारे में

- **उत्पत्ति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1988 (2011)** के तहत स्थापित।
- **मुख्य कार्य: अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा को** खतरा पहुंचाने वाले **तालिबान से जुड़े** व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ **प्रतिबंधों की निगरानी और उन्हें लागू करना।**

आतंकवाद-रोधी समिति (CTC)

- **उत्पत्ति: 9/11 हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (2001)** के माध्यम से स्थापित, **सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी**।
- **सदस्य: सुरक्षा परिषद के** सभी 15 सदस्य।
- **प्रमुख कार्य:** देशों के **आतंकवाद-रोधी प्रयासों की निगरानी करना**, यह सुनिश्चित करना कि वे **आतंकवाद के वित्त-पोषण को अपराध घोषित करें**, **आतंकवादियों से जुड़े फंड को फ्रीज़ करें**, तथा **खुफिया जानकारी साझा करें**।

2.7.2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL: ECOSOC)

भारत को **2026-28 कार्यकाल** के लिए **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का सदस्य चुना गया।

- सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क (USA)।
- **उत्पत्ति: 1945 में** संयुक्त राष्ट्र के **छह मुख्य अंगों** में से एक के रूप में स्थापित।
- **सदस्य: 54** (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित**)।

प्रमुख भूमिका:

- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में **सतत विकास को आगे बढ़ाना।**
- संयुक्त राष्ट्र निकायों और विशेष एजेंसियों के कार्य का **समन्वय करना।**
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को **नीतिगत सिफारिशें** जारी करना।

UN ECOSOC के 8 कार्यात्मक आयोग

सांख्यिकीय आयोग	महिलाओं की स्थिति पर आयोग	विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग
जनसंख्या और विकास आयोग	मादक द्रव्य (नारकोटिक ड्रग्स) आयोग	वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच आयोग
सामाजिक विकास आयोग	अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग	

2.7.3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने गावी, द वैक्सीन अलायंस के वित्त-पोषण पर रोक लगाई (US PULLS FUNDING FROM GAVI, THE VACCINE ALLIANCE)

अमेरिका ने गावी (Gavi) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर यह आरोप लगाया है कि वे टीकों की सुरक्षा पर उठने वाले वैध सवालों एवं असहमति को दबा रहे हैं

- अमेरिका लंबे समय से गावी का **सबसे बड़ा समर्थक रहा है**।
- हाल के वर्षों में, **संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन**, **पेरिस जलवायु समझौते**, **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** और **UNRWA** जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों से खुद को अलग कर लिया है।

गावी (Gavi) के बारे में (2000)

- **प्रकृति:** यह एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** है।
- **मुख्य भागीदार:** इसके मुख्य भागीदारों में **विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक और गेट्स फाउंडेशन** शामिल हैं।
- **मिशन:** टीकों के **न्यायसंगत और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देकर** लोगों के जीवन को बचाना तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- **उपलब्धियां:** इसने सबसे गरीब देशों में **एक बिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण** किया है।
- **वैश्विक भूमिका:** यह **WHO** के नेतृत्व में संचालित **वैक्सीन सेफ्टी नेट (VSN) प्रोजेक्ट** का हिस्सा है।
- **सचिवालय:** जेनेवा (स्विट्जरलैंड)

वैश्विक गठबंधनों से अमेरिका के हटने के प्रभाव

- **बहुपक्षवाद/नियम-आधारित व्यवस्था का कमजोर होना:** उदाहरणार्थ, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी भागीदारी खत्म कर दी है।
- **जलवायु परिवर्तन कार्यवाहियों पर प्रभाव: 2024 को सबसे गर्म वर्ष** के रूप में दर्ज किया गया है और अमेरिका, चीन के बाद दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है।**
- **स्वास्थ्य के लिए धन की कमी:** अमेरिका के बाहर निकलने से संस्थानों को **धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए,** 2024 में **WHO के कुल वित्त-पोषण का लगभग 15%** अमेरिका द्वारा वित्त पोषित किया गया।
- **अन्य:** अमेरिका के हटने से वैश्विक नेतृत्व में खालीपन पैदा होता है, जिसे चीन भर सकता है। इससे **भारत की वैश्विक संगठनों में प्रभावशीलता कम** हो सकती है।

2.7.4. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन (INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MEDIATION: IOMed)

चीन ने **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन** जैसी पारंपरिक संस्थाओं के वैश्विक विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से **IOMed** की स्थापना की।

IOMed के बारे में

- **उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता करना।**
  - **सदस्य: इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बेलारूस** सहित 30 से अधिक **देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए**।

- अधिकांश संस्थापक सदस्य **एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन क्षेत्र से हैं**, जो इस नई संस्था के गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

- **कार्य क्षेत्र: देशों** के बीच विवाद समाधान, **सी राष्ट्र और दूसरे देश के नागरिकों के बीच विवाद का समाधान**, **अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद का समाधान।**

2.7.5. भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि {INDIA-KYRGYZSTAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT)}

जून 2019 में हस्ताक्षरित भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) **5 जून, 2025 से लागू** हो गई है।

- इसने वर्ष 2000 में लागू हुई संधि की जगह ली है तथा यह निवेश की सुरक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।
- यह निवेशकों के अधिकारों और दोनों देशों की अपनी-अपनी संप्रभु विनियामक शक्तियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है और इसका उद्देश्य **पारदर्शी निवेश परिवेश को बढ़ावा देना है**।

भारत-किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में

- **परिसंपत्ति परिभाषा:** इसमें उद्यम-आधारित परिभाषा को अपनाया गया है। साथ ही, इसमें किन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा और किन्हें बाहर रखा जाएगा, उन्हें भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इसमें निवेश की प्रकृति भी स्पष्ट की गई है – जैसे लाभ की अपेक्षा, जोखिम वहन करना, आदि।
- **नीतिगत दायरे से बाहर रखना:** कराधान, स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- **MFN खंड को हटा दिया गया है:** अनुकूल संधि शर्तों को चुनिंदा रूप से अपनाने से रोकने के लिए **सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र खंड को समाप्त कर दिया गया है।**
- **सामान्य एवं सुरक्षा अपवाद:** पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय।
- **विवाद समाधान:** अंतर्राष्ट्रीय पंचाट के पहले स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का प्रावधान।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

परिभाषा:
इसे **अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौता (IIA)** भी कहा जाता है। यह विदेशी निवेशकों को यह आश्वासन प्रदान करती है कि उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उपायों से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही राष्ट्रों को **संप्रभु नीति-निर्माण की स्वतंत्रता** भी प्राप्त होती है अर्थात वे स्वतंत्र रूप से नीतियां बना सकते हैं।

विवाद समाधान:
ये समझौते **निवेशक या उनके देश को होस्ट देश (जहां निवेश किया गया है) के खिलाफ निवेश विवादों को लेकर मुकदमा दायर करने का अधिकार** भी देते हैं।

नीतिगत अपडेट:
भारत ने **2015 में द्विपक्षीय निवेश संधि का नया मॉडल टेक्स्ट** स्वीकृत किया था। यह **मॉडल 1993** के मॉडल के स्थान पर लागू किया गया है।

2015 से भारत ने इन देशों के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए हैं:
उज्बेकिस्तान (2024), संयुक्त अरब अमीरात (2024), ब्राजील (2020), बेलारूस (2018) आदि।

2.7.6. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MARINE AIDS TO NAVIGATION: IALA)

भारत ने **IALA के उपाध्यक्ष के रूप में**, **फ्रांस के नीस में आयोजित IALA परिषद के दूसरे सत्र में सक्रिय रूप से भाग** लिया।

- भारत दिसंबर 2025 में **तीसरी IALA महासभा** और 2027 में **21वें IALA** सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। दोनों ही **मुंबई (महाराष्ट्र) में आयोजित** किए जाएंगे।

IALA के बारे में

- **उत्पत्ति: 1957 में** एक **गैर सरकारी संगठन** के तौर पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA) के रूप में स्थापित।
  - **2024** में, IALA **समुद्री सुरक्षा** में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए एक **अंतर-सरकारी संगठन (IGO) बन गया।**
- **उद्देश्य:** विश्व भर में **नेविगेशन संबंधी सहायता** में सुधार और सामंजस्य के माध्यम से **जहाजों की सुरक्षित, किफायती और कुशल आवाजाही को** बढ़ावा देना।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - **वैश्विक समुद्री नेविगेशन प्रणालियों को** सुसंगत बनाना।
  - **समुद्री सुरक्षा पहल को** बढ़ावा देना।
  - **समुद्री सुरक्षा** और **पर्यावरण संरक्षण** में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

2.7.7. जंगेजुर कॉरिडोर (ZANGEZUR CORRIDOR)

तुर्किये ने आर्मेनिया और अजरबैजान से जंगेज़ुर कॉरिडोर खोलने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया।

- आर्मेनिया और अजरबैजान 1917 से नागोर्नो-काराबाख (आर्टाख/Artsakh) क्षेत्र को लेकर संघर्षरत हैं। यह क्षेत्र **अंतरराष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान का हिस्सा** माना जाता है, लेकिन यहां मुख्यतः **आर्मीनियाई नृजातीय समुदाय** निवास करते हैं।

ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर के बारे में

- **अवस्थिति:** यह आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित 43 किलोमीटर लंबा परिवहन मार्ग है।
- **उद्देश्य: कैस्पियन सागर में अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नखचिवन** स्वायत्त **क्षेत्र** और आगे **तुर्किये से** जोड़ना।
- **भारत की चिंताएं: यह प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करके **चाबहार बंदरगाह** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर (INSTC)** में भारत के निवेश को प्रभावित कर सकता है, तथा भारत के **क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर सकता है**।

2.7.8. ई-पासपोर्ट (E-PASSPORT)

भारत के **विदेश मंत्रालय ने ई-पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0** को शुरू किया है।

ई-पासपोर्ट के बारे में

- ई-पासपोर्ट वास्तव में **पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का मिश्रित रूप** है। इसमें एक **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)** चिप और एक **एंटीना** पासपोर्ट के कवर में इनले के रूप में लगाया गया होता है।
  - इसकी सुरक्षा प्रणाली का आधार पब्लिक-की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI) तकनीक है।
- यह **पासपोर्ट को जालसाजी** और **धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाता है** तथा **सीमा नियंत्रण पर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करता है**।

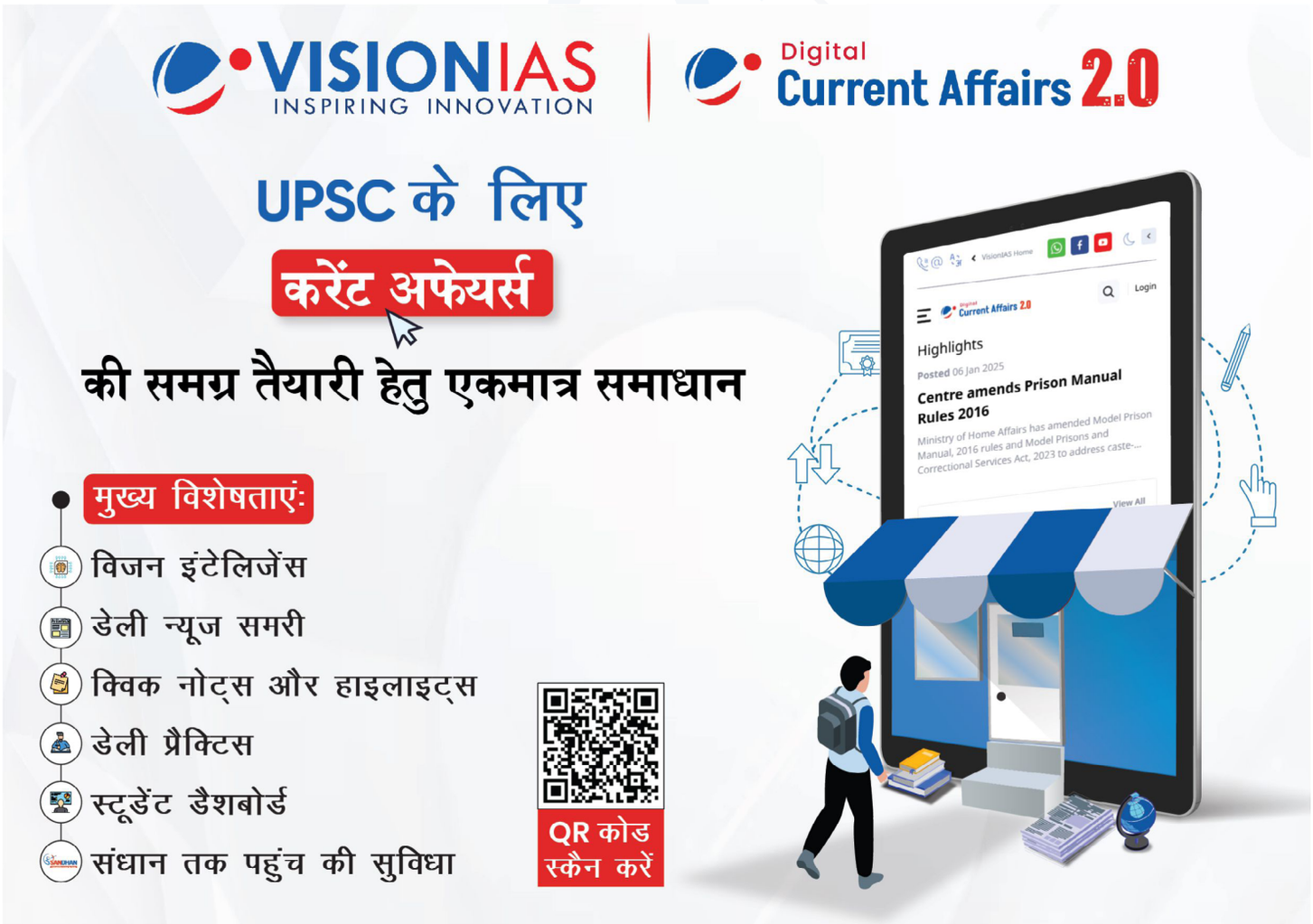

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन (RURAL INDIA: THE NEW ENGINE OF INDIA'S CONSUMER MARKET)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में मजबूत संवृद्धि को देखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से आग्रह किया है कि उन्हें **ग्रामीण भारत** को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं, बल्कि **'नए बाजार सृजित'** करने के एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए।

ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन

- **बढ़ती मांग:** ग्रामीण उपभोग शहरी उपभोग को पीछे छोड़ रहा है; FMCG (जैसे डाबर) की ग्रोथ गांव में तेज़ी से बढ़ रही है। 2023–24 में ग्रामीण MPCE 9.2% बढ़ा था, जो शहर के 8.3% से ज़्यादा है (HCES 2023–24)।
- **घटता अंतराल:** शहरी और ग्रामीण MPCE के बीच का अंतर 71.2% से घटकर 69.7% हो गया है।
- **शहरों के जैसा खर्च:** अब ग्रामीण खर्च में गैर-खाद्य वस्तुएं, शिक्षा, संचार और स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य हो गए हैं।

संवृद्धि के मुख्य चालक

- **खर्च करने योग्य आय में वृद्धि:** ग़ैर-कृषि कार्य, मनरेगा, और विप्रेषण के कारण आय बढ़ी है।
- **गरीबी में कमी:** ग्रामीण गरीबी 25.7% (2011–12 में) से घटकर 5% से कम हो गई है।
- **सरकारी पहलें:** DBT और PM-KISAN जैसी योजनाओं ने तरलता को बढ़ाया है।
- **अवसंरचना पर बल:** सड़कों (PMGSY) और डिजिटल संवृद्धि (भारतनेट) के कारण ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में 200% की वृद्धि हुई है।
- **वित्तीय समावेशन:** UPI, PMJDY जैसी योजनाओं से ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 67% और महिलाओं द्वारा 55% खाते खोले गए हैं।

निष्कर्ष

सरकार को असमानता कम करनी चाहिए, कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए और मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। वहीं, निजी क्षेत्रक को HUL के 'प्रोजेक्ट शक्ति' जैसे कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचना चाहिए; सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए और स्थानीय भाषा में तकनीक का उपयोग करना चाहिए।

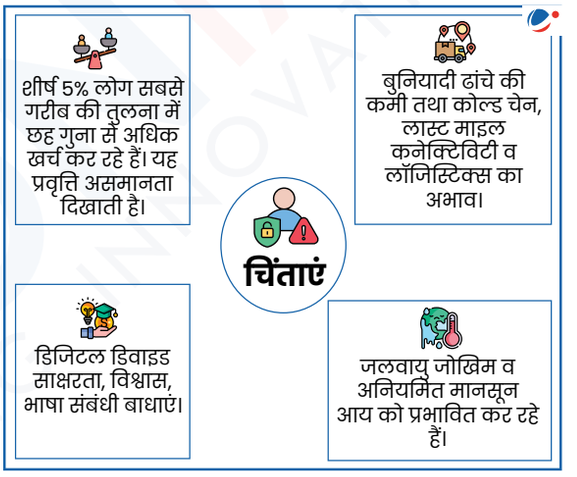

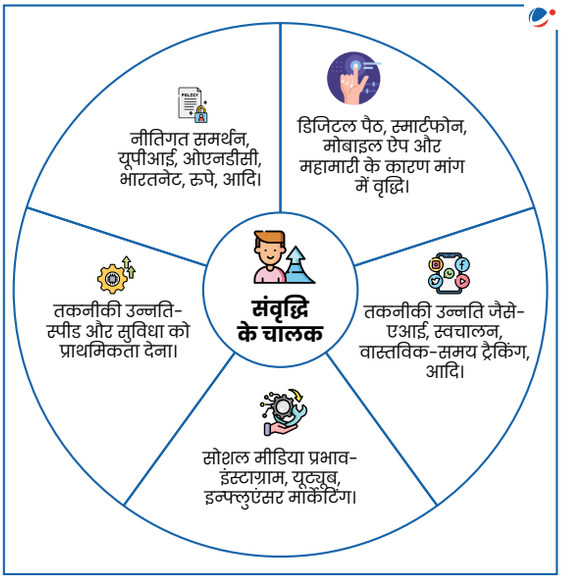

3.2. भारत में क्विक कॉमर्स (QUICK COMMERCE IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का **क्विक कॉमर्स क्षेत्रक** आने वाले समय में तीव्र गति से वृद्धि करेगा, हालांकि यह उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी बदलाव ला सकता है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

- यह लगभग **एक घंटे के भीतर** वस्तुओं और सेवाओं की बहुत तेज डिलीवरी है।
- सेवाएं 24×7 उपलब्ध होती हैं, बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है, उपभोक्ता के आस-पास से ही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, आपूर्ति श्रृंखला काफी दक्ष हो जाती है आदि।

क्विक कॉमर्स की वर्तमान स्थिति

- **विकास:** क्विक कॉमर्स के हर साल 75-100% तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **बाजार का आकार:** इसका बाजार 2025 तक $5 बिलियन और 2029 तक $9.94 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- **प्रमुख अभिकर्ता:** जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, आदि।

चिंताएं

- **तत्काल संतुष्टि:** व्यवहार-आधारित टार्गेटिंग के जरिये यह आवेगपूर्ण खरीदारी को बढ़ावा देता है।
- **गिग वर्कर्स की सुरक्षा:** 10-मिनट की डिलीवरी नैतिक समस्याएं पैदा करती है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** ज़्यादा वाहनों का मतलब है, ज़्यादा उत्सर्जन।
- **खाद्य सुरक्षा:** खराब होने वाली चीज़ों की ख़राब हैंडलिंग से स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
- **खुदरा क्षेत्र में व्यवधान:** किराना स्टोर और मॉल में ग्राहकों की संख्या घट रही है।

संतुलन बनाना

- डिलीवरी पार्टनर्स के कल्याण और दुर्घटना बीमा को सुनिश्चित करना।
- स्वच्छता को मज़बूत करना, जैसे FSSAI के खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन।
- बेहतर पहुंच के लिए किराना स्टोर को इसमें शामिल करना।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, डेटा और श्रम सुरक्षा के लिए नियम बनाना।
- ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना: इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और मोबाइल वेयरहाउस।

निष्कर्ष

क्विक कॉमर्स ने सुविधा को तो बढ़ाया है, लेकिन इसने अस्थिर उपभोग को भी बढ़ावा दिया है और गिग वर्कर्स के कल्याण से समझौता किया है। हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो गिग वर्कर्स की सुरक्षा करें और उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ावा दें, ताकि आवेगपूर्ण खरीदारी को कम किया जा सके।

3.3. विमानन सुरक्षा (AVIATION SAFETY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) ने अहमदाबाद की दुखद विमान दुर्घटना** की जांच की **प्रारंभिक रिपोर्ट** सौंप दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट में, मेडे (MAYDAY) कॉल के समय का विवरण दिया गया है—यह कॉल जीवन-घातक आपात स्थितियों में उपयोग की जाती है—इसे आपातकालीन आवृत्तियों 121.5 मेगाहर्ट्ज और 243 मेगाहर्ट्ज पर किया गया था।
- **ब्लैक बॉक्स** बरामद कर लिए गए थे और AAIB लैब द्वारा उनका विश्लेषण किया गया।
  - **ब्लैक बॉक्स में दो प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइसेज** होते हैं:
    - **फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर**- जो गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन जैसे मापदंड रिकॉर्ड करता है; तथा
    - **कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर।**
  - यह **चमकीले नारंगी** रंग का होता है। इसे स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत सामग्री से बनाया जाता है।

भारत में विमानन सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था

- **DGCA:** नागर विमानन सुरक्षा व विमान की एयरवर्दीनेस (उड़ान लायक स्थिति) को विनियमित करता है और ICAO के साथ समन्वय करता है।
- **AERA:** प्रमुख हवाई अड्डों पर शुल्क और सेवा मानकों को नियंत्रित करता है।
- **BCAS:** अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए ICAO के एनेक्स 17 के तहत विमानन सुरक्षा मानदंड निर्धारित करता है।
- **AAIB:** 2250 किलोग्राम से अधिक कुल भार वाले विमान या टर्बोजेट की दुर्घटनाओं की जांच AAIB करता है। 2017 के नियमों के तहत इसे साक्ष्य तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त है।
  - DGCA छोटे विमानों (≤2250 किलोग्राम) से जुड़ी गंभीर घटनाओं की जांच करता है।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विमानन सुरक्षा के मुद्दे और सिफारिशें

विषय	चुनौतियां	सिफारिशें
बजटीय आवंटन	DGCA को 30 करोड़ रुपये (**विमानन पूंजीगत बजट का 50%**) ही मिलता है। इसी सुरक्षा और जांच की इसकी क्षमताएं प्रभावित होती है।	महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के लिए संतुलित निधि आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।
मानव संसाधन की कमी	DGCA, BCAS और AAI में क्रमशः 53.8%, 34.7% और 17% पद रिक्त हैं।	भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और दीर्घकालिक मानव संसाधन योजना अपनानी चाहिए।
उड़ान	विस्तार की आवश्यकता के बावजूद 32% निधि कटौती।	क्षेत्रीय अवसंरचना की मांगों के अनुरूप वित्त-पोषण की समीक्षा करनी चाहिए।
निगरानी	सामान्य बजट पर निर्भरता; स्थायी वित्त-पोषण का अभाव।	समन्वित निगरानी के लिए एकीकृत सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए।
नेविगेशन	धुंध की वजह दृश्यता कम हो जाती है।	सभी हवाई अड्डों पर **इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS)** की स्थापना करनी चाहिए।
केबिन सुरक्षा	घटिया सामग्री और पुरानी तकनीक	मानक प्रवर्तन के लिए एविएशन इंटीरियर क्वालिटी कमीशन की स्थापना करनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत ने अपनी विमानन सुरक्षा प्रणाली को ICAO के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है, जिसे ICAO की सुरक्षा ऑडिट में सराहा भी गया है। दिल्ली घोषणा-पत्र (2024) को अपनाना भारत की ओपन स्काई नीति और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालिया विमान दुर्घटनाओं की पूरी पारदर्शिता और गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

3.4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (ASSET MONETIZATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण के माध्यम से उसका मूल्य प्राप्त करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इस रणनीति में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और सिक्योरिटाइजेशन जैसे मॉडल्स को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 6,100 किलोमीटर से अधिक हिस्से के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

- यह पूरी तरह उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक (सरकारी) परिसंपत्तियों के **आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के द्वारा राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की नई या वैकल्पिक प्रक्रिया** है। इसे **'पूंजी पुनर्चक्रण'** यानी **कैपिटल रीसाइक्लिंग** भी कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया से **परिसंपत्ति का विनिवेश** हो।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता

- **निवेश की कमी को पूरा करना:** यह गैर-कर राजस्व के माध्यम से धन की कमी को दूर करता है।
- **दक्षता बढ़ाना:** बेहतर संचालन के लिए निजी क्षेत्रक की विशेषज्ञता लाता है।
- **ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का उपयोग:** यह स्थिर रिटर्न के साथ कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों को लक्षित करता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** यह FDI को आकर्षित करता है और भारत के वैश्विक एकीकरण को मज़बूत करता है।
- **प्रमुख संस्थाएं:** वैकल्पिक तंत्र, सचिवों का मुख्य समूह, अंतर-मंत्रालयी समूह, DIPAM, और नीति आयोग।

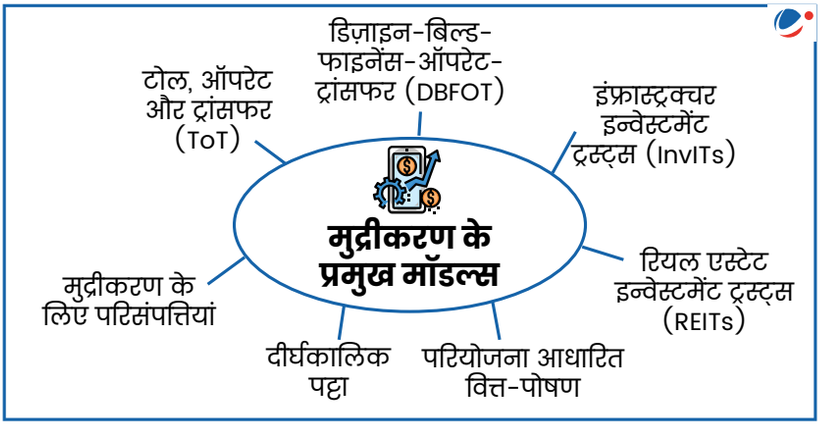

प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन;
- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC);
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड, आदि।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण: बाधाएं बनाम रणनीतिक हस्तक्षेप

विषय (क्षेत्र)	परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बाधाएं	आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप
पारदर्शिता और शासन	पक्षपात के प्रति संवेदनशील; अग्रिम प्रकटीकरण का अभाव, आदि।	भावी मुद्रीकरण पाइपलाइन का सार्वजनिक प्रकटीकरण; पारदर्शी बोली आदि।
क्षेत्रक विशेष की समस्याएं	संकेन्द्रित बनी हुआ है; शहरी अवसंरचना व रेलवे उपेक्षित है।	व्यापक एवं बंडल मुद्रीकरण (गैर-निवेशित क्षेत्रों में छोटी परिसंपत्तियां)।
परिसंपत्ति के मूल्य का पता लगाना और प्रतिस्पर्धी बोली	कम मूल्यांकन का जोखिम; पूंजी गहन प्रकृति के कारण सीमित भागीदारी।	जोखिम-रहित मॉडल अपनाएं (TOT, InvITs, आदि)
राज्य-स्तरीय तत्परता	राज्य अवसंरचना क्षेत्रकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी नगण्य है और वित्तीय प्रोत्साहन की कमी है।	राज्य परिसंपत्तियों की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए; राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए।
उपभोक्ता एवं जनहित	निजी कंपनियों द्वारा परिसंपत्ति के अधिक दोहन से मूल्य वृद्धि की आशंका बनी रहती है।	"स्वामित्व नहीं, मुद्रीकरण का अधिकार" मॉडल अपनाया जाना चाहिए। अनुबंध के दायित्वों का कठोर पालन करना चाहिए।
कई संस्थाओं के शामिल होने से समस्या	कई मंत्रालयों का शामिल होना; खराब समन्वय; केंद्रीकृत योजना का अभाव।	एक अलग **अवसंरचना मंत्रालय** गठित करना चाहिए।
विनियामकीय व्यवस्था में अनिश्चितता	**स्पष्टता** का अभाव (जैसे दूरसंचार)	क्षेत्र-विशिष्ट दिशा-निर्देश विकसित करना; स्वतंत्र मूल्यांकन करना आदि।
राजकोषीय प्रबंधन में उपयोग और जन-विश्वास	राजकोषीय घाटे के लिए विनिवेश आय का दुरुपयोग।	PSUs के पुनर्गठन के लिए धन; पट्टे/ किराये के मॉडल का अन्वेषण करना।
निगरानी और प्रदर्शन की ट्रैकिंग	मुद्रीकरण के बाद उचित निगरानी न होना।	**मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs)** को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

निष्कर्ष

परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करता है और इसे नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश करता है। इससे भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि और सतत विकास का समर्थन करने के लिए मज़बूत अवसंरचना तैयार होती है।

3.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FOREIGN DIRECT INVESTMENT: FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जून 2025 में जारी RBI बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निवल FDI में 96% की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि सकल FDI में वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के बारे में

- **परिभाषा:** यह किसी विदेशी कंपनी द्वारा किसी गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में किया गया निवेश या किसी सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक की इक्विटी हिस्सेदारी है।
- **विनियमन:** इसे समेकित FDI नीति (2020) और FEMA (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 द्वारा शासित किया जाता है।
- **सकल बनाम निवल FDI:**
  - **सकल FDI:** यह भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

भारत में निवल FDI में गिरावट के कारण

- **भारत से बाह्य (आउटवर्ड) निवेश में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2025 में 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
- उदारीकृत ODI दिशा-निर्देश (2022)।
- रिटर्न में वृद्धि एक परिपक्व बाजार का संकेत देती है।
- **वैश्विक जोखिम:** व्यापार तनाव, कमजोर मांग, 2024 में वैश्विक FDI में 11% की गिरावट (UNCTAD), आदि।
- पुराने FDI का अंतिम चरण और निर्यात संकुचन।

- **निवल FDI:** यह भारत में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से भारत से बाहर जाने वाली FDI घटाने के बाद बचा हुआ निवेश है।

- **प्रवेश मार्ग:**
  - **स्वचालित मार्ग:** इसमें किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती (जैसे कृषि, दूरसंचार)।
  - **सरकारी मार्ग:** इसमें सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना ज़रूरी होता है।
- **निषिद्ध क्षेत्र:** लॉटरी, जुआ, चिट फंड, परमाणु ऊर्जा, रेलवे संचालन, आदि।

बढ़ते FDI का महत्त्व

- **पूंजी निर्माण:** यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रणनीतिक विकास को सक्षम बनाता है। UNCTAD WIR 2025 के अनुसार, ग्रीनफ़ील्ड निवेश 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **विदेशी मुद्रा स्थिरता:** विदेशी मुद्रा भंडार 11+ महीनों के आयात और कुल बाहरी ऋण के 96% को कवर करता है (RBI, मई 2025)।
- **सतत वित्त-पोषण:** भारत कार्बन क्रेडिट जारी करने में अग्रणी है (वेरा रजिस्ट्री)।
- **नवाचार और रोजगार:** यह प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

FDI को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **क्षेत्रकवार सुधार:** विभिन्न क्षेत्रकों में सुधार किए गए हैं, जैसे बीमा क्षेत्रक में FDI की सीमा को बढ़ाकर 100% करना।
- **जन विश्वास अधिनियम (2023):** इस अधिनियम ने अनुपालन को आसान बनाया है।
- **नए निवेश समझौते:** EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के साथ TEPA (व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता) जैसे नए निवेश समझौते किए गए हैं।
- **BRAP और LEADS रैंकिंग:** ये रैंकिंग राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं।
- **PDCs और प्रमुख योजनाएं:** उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI), मेक इन इंडिया और गति शक्ति जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

आगे की राह

- **नीति में स्थिरता और न्यायिक सुधार:** नीतियों में स्थिरता और न्यायिक प्रणाली में सुधार आवश्यक है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास:** डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना।
- **निवेश प्रोत्साहन:** निवेशकों को प्रोत्साहन देना, जैसे कर में छूट।
- **निष्पक्ष निवेश प्रणालियों पर वैश्विक सहयोग को मज़बूत करना:** निष्पक्ष निवेश प्रणालियों के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना।

3.6. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (FINANCING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विकास के लिए वित्त-पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) में अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज़ "कम्प्रोमिसो डी सेविले" (सेविले प्रतिबद्धता) को अपनाया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के दिशा में विद्यमान वित्त-पोषण की कमी को दूर करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सेविले प्रतिबद्धता को सर्वसम्मति (अमेरिका को छोड़कर) से अपनाया गया। यह $4 ट्रिलियन के वार्षिक SDG वित्त-पोषण अंतराल को खत्म करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है।
- यह मॉन्टेरी कंसेंसस, दोहा घोषणा-पत्र, और अदीस अबाबा कार्य एजेंडा जैसे मौजूदा फ्रेमवर्क्स पर आधारित है।
- भारत ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सात-सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव पेश किया। इसमें बहुपक्षीय बैंकों को मजबूत करना, क्रेडिट रेटिंग में सुधार करना, घरेलू बाजारों को विकसित करना और मिश्रित वित्त (blended finance) को बढ़ाना शामिल है।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है?

- **वित्त-पोषण में कमी:** SDG के वित्त-पोषण में सालाना $4 ट्रिलियन की कमी है।
- **जलवायु निवेश:** 2030 तक ऊर्जा निवेश में 40% की वृद्धि होनी चाहिए (OECD, 2025)।
- **धन की असमानता:** शीर्ष 1% लोगों के पास 95% आबादी की तुलना में ज़्यादा संपत्ति है (Oxfam, 2024)।
- **कर में असमानता:** अरबपति केवल 0.3% वास्तविक कर का भुगतान करते हैं (Oxfam, 2025)।
- **ऋण का बोझ:** 40% अत्यधिक गरीब लोग क़र्ज़ में फंसे देशों में रहते हैं (FSDR 2023)।

बाधाएं

- घटता राजकोषीय व्यय; 46 देश स्वास्थ्य/ शिक्षा की तुलना में ब्याज पर अधिक खर्च करते हैं।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण का क्रम-विकास

- **2002** → मॉन्टेरी कंसेंसस (2002)
- **2008** → दोहा घोषणा-पत्र (2008)
- **2015** → अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015)

- SDR का असमान आवंटन: अल्पविकसित देशों (LDCs) को केवल 2.5% मिलता है।
- बढ़ता भू-आर्थिक विखंडन और अवैध वित्त प्रवाह।
- रोजगार और पारिश्रमिक में लैंगिक असमानता।

सेविले प्रतिबद्धता के तहत उठाए गए कदम

- **ऋण समाधान:**
  - विकास के लिए ऋण-विनिमय, पॉज़ क्लॉज़ अलायंस और ऋण पर सेविले फोरम।
- **निवेश को बढ़ावा देना:**
  - मिश्रित वित्त-पोषण (SCALED), उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों (HNWIs) पर प्रभावी कराधान और ग्लोबल सॉलिडैरिटी लेवी।
- **ढांचागत सुधार:**
  - स्थानीय मुद्रा ऋण प्लेटफॉर्म्स और यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व-व्यवस्थित वित्त-पोषण गठबंधन।

निष्कर्ष

वित्त को SDG के साथ संरेखित करने के लिए निजी निवेश हेतु अनुकूल माहौल बनाना; सार्वजनिक विकास बैंकों को मजबूत करना तथा राजकोषीय प्रोत्साहन, दीर्घकालिक वित्त-पोषण और WTO के अपडेटेड नियमों एवं निवेश संधियों के माध्यम से बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार करना आवश्यक है।

3.6.1. सतत विकास रिपोर्ट (2025) {SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT (2025)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सतत विकास रिपोर्ट (2025) में पहली बार भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर आकर SDG सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने 2021 के 120वें स्थान से सुधार करते हुए 2025 में 99वां स्थान हासिल किया। भारत का स्कोर 100 में से 67 है।
- सूचकांक में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान है।
- सूचकांक में भूटान 74वें, नेपाल 85वें, मालदीव 53वें, श्रीलंका 93वें, बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान पर हैं।
- बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता नामक एक नए संकेतक को SDG-2 के तहत शामिल किया गया।
- 2030 तक कोई भी SDG पूरी तरह से हासिल होने की राह पर नहीं है।

SDG सूचकांक के बारे में

- इसे 2016 से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा जारी किया जा रहा है।
- 0-100 के पैमाने पर 17 SDGs की ओर प्रगति को मापता है।

भारत के प्रदर्शन के प्रमुख संकेतक (2025 SDR के अनुसार)	
SDG1	कुल आबादी का **5.5%** हिस्सा ऐसा है, जो प्रतिदिन **$3.65 से कम** पर जीवन यापन कर रहा है।
SDG2	कुपोषण का प्रसार- **13.7%**
SDG3	मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म पर) **80.5** है।
SDG4	निवल प्राथमिक नामांकन दर- **99.9%**
SDG5	महिला-पुरुष श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात - **43%** संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटें - **14%**
SDG6	न्यूनतम बुनियादी पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाली आबादी- **93%**
SDG7	बिजली तक पहुंच वाली जनसंख्या- **99%** खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाली जनसंख्या- **74%**
SDG9	सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़कों तक पहुंच वाली ग्रामीण जनसंख्या- **99%** इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी- **56%**
SDG10	भारत में गिनी गुणांक **34.8**

3.7. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) {ATAL MISSION FOR REJUVENATION AND URBAN TRANSFORMATION (AMRUT)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) योजना को शुरू हुए एक दशक पूरा हो गया है।

अमृत (AMRUT) के बारे में

- **मंत्रालय:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **विवरण:** इसकी शुरुआत चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में की गई थी। इसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थल और पार्क, और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना है।
- **AMRUT 2.0 (2021):** जल एवं सीवरेज सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना, जिसका लक्ष्य सभी वैधानिक शहरों में नल से जल उपलब्ध कराना है।

AMRUT 2.0 के प्रमुख घटक

- पेय जल सर्वेक्षण; व्यवहार परिवर्तन संचार; तथा प्रौद्योगिकी उप-मिशन।
- इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में PPP पर ज़ोर दिया गया है। सामुदायिक भागीदारी (विशेषकर महिला SHGs की) और जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सर्वोच्च समिति (राष्ट्रीय) और SHPSC (राज्य स्तर) द्वारा निगरानी की जाती है।

उपलब्धियां

- 2.03 करोड़ नल और 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन दिए गए।
- 99 लाख LED स्ट्रीटलाइट्स लगाई गईं।
- 6,800+ एकड़ हरित स्थान और 3,000 पार्क विकसित किए गए।
- **कमियां:** स्वास्थ्य के खराब परिणाम, कार्यान्वयन में देरी, पर्यावरणीय मुद्दे, सीमित कवरेज, और योजनाओं का आपस में ओवरलैप होना।

निष्कर्ष

एक दशक पूरा कर चुके AMRUT ने शहरी बुनियादी ढांचे, विशेषकर जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार किया है। इससे ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समग्र और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, नगरीय निकायों (ULBs) की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा, छोटे शहरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, एवं जलवायु-संवेदनशील व प्रकृति-आधारित समाधानों को एकीकृत करके सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

3.8.1. डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (Digital Payment Intelligence Platform: DPIP)

DPIP को बैंकिंग में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी और मार्गदर्शन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित किया जाएगा।

DPIP के बारे में

- इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बैंकों के बीच वास्तविक समय में खुफ़िया जानकारी साझा करने और समन्वय को सुविधाजनक बनाना है।
- RBIH 5-10 सार्वजनिक और निजी बैंकों के परामर्श से इसका प्रोटोटाइप बनाएगा।
- **श्री ए.पी. होता** की अध्यक्षता वाली एक समिति DPIP की स्थापना की जांच करेगी।
- **आवश्यकता:** वित्त वर्ष 2025 में बैंकिंग धोखाधड़ी बढ़कर ₹36,014 करोड़ हो गई है (वित्त वर्ष 2024 में यह ₹12,230 करोड़ थी)।

RBI की अन्य पहलें

- अनिवार्य मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण।
- ग्राहकों के लिए शून्य देयता।
- आधिकारिक बैंकिंग वेबसाइटों को सत्यापित करने के लिए bank.in और fin.in डोमेन।

3.8.2. लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) मानदंड {Priority Sector Lending (PSL) Norms For Small Finance Banks (SFBs)}

बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत, RBI ने लघु वित्त बैंकों (SFB) के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) मानदंडों में संशोधन करते हुए नए नियम जारी किए।

PSL आवश्यकताओं में प्रमुख बदलाव

- **पहले:** SFBs को ANBC का 75% ऋण देना होता था (जिसमें 40% PSL क्षेत्रकों के लिए अनिवार्य था, और 35% फ्लेक्सिबल था)।

- **नया नियम (वित्त वर्ष 2025-26 से):** कुल PSL को ANBC के 60% तक कम कर दिया गया है (जिसमें 40% PSL के लिए अनिवार्य है, और 20% सुरक्षित गैर-PSL ऋणों के लिए फ्लेक्सिबल है)।

PSL के बारे में

- इसे 1970 के दशक में कृषि, MSMEs, शिक्षा, आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रकों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।
- यह वाणिज्यिक बैंकों, SFBs, RRBs, LABs और UCBs पर लागू होता है।

SFBs के बारे में

- इन्हें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
- इनकी न्यूनतम नेट वर्थ ₹200 करोड़ होनी चाहिए (UCBs से परिवर्तित होने वालों के लिए ₹100 करोड़)।

3.8.3. सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (Sagarmala Finance Corporation Limited: SMFCL)

सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL), **सामुद्रिक क्षेत्रक में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** है। अब यह RBI में पंजीकृत हो गई।

SMFCL के बारे में

- SMFCL का पहले नाम **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड** था। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक **मिनी रत्न, श्रेणी-I CPSE** है।
- अब यह एक **NBFC** है, जो बंदरगाह प्राधिकरणों और शिपिंग कंपनियों जैसे हितधारकों को कस्टमाइज़्ड वित्तीय उत्पाद प्रदान करेगी।
- यह जहाज़ निर्माण, क्रूज़ पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, और समुद्री शिक्षा जैसे क्षेत्रकों को भी समर्थन प्रदान करेगी।

समुद्री क्षेत्रक के लिए भारत में शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **DCoE:** AI, IoT, ब्लॉकचेन के माध्यम से नवाचार।
- **सागर सेतु (SAGAR SETU):** EXIM से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है।
- **दृष्टि (DRISHTI):** यह मैरीटाइम इंडिया विज़न का समर्थन करता है।
- **स्केल ऑफ रेट्स (SOR):** एक समान शुल्क संरचना प्रदान करती है।
- **गेटवे टू ग्रीन:** भारत के पत्तनों का ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में रूपांतरण करना।

3.8.4. स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत {INDIGENOUS POLAR RESEARCH VESSEL (PRV)}

भारत अपने पहले स्वदेशी पोलर रिसर्च व्हीकल (PRV) का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए GRSE ने नॉर्वे की कंपनी कोंगसबर्ग ओस्लो के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

PRV के बारे में

- यह एक **विशेष पोत है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए बनाया गया है। यह समुद्र की गहराई और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र का पता लगाने** के लिए उन्नत उपकरणों से लैस होगा।

भारत के लिए इसका महत्त्व

- यह NCOPR के **अंटार्कटिका (मैत्री, भारती) और आर्कटिक (हिमाद्री)** में चल रहे अनुसंधान मिशनों में सहायता करेगा।
- यह ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की **भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक उपस्थिति** को मज़बूत करेगा।
- यह स्वदेशी जहाज़ निर्माण और समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए **मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के तहत SAGAR, MAHASAGAR, और सागरमाला 2.0** जैसी पहलों के साथ संरेखित है।
- यह **जलवायु अनुसंधान, समुद्र विज्ञान और लॉजिस्टिक्स** के लिए महत्वपूर्ण है।

3.8.5. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से प्राप्त उत्पादन के मूल्य पर रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24) {REPORT ON VALUE OF OUTPUT FROM AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS (2011 12 TO 2023-24)}

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्रक के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **GVA (सकल मूल्य वर्धित)** कृषि में **~225%** बढ़ा (वर्तमान कीमतों पर); जबकि 2011-12 से 2023-24 तक **GVO (सकल उत्पादन मूल्य)** 54.6% बढ़ा (स्थिर कीमतों पर)।
- 2023-24 में, **फसल क्षेत्रक** का कुल GVO में **54.1%** का योगदान था; जिसमें सभी अनाजों में धान और गेहूं का GVO में 85% हिस्सा था।
- **फूलों की खेती** का **GVO** लगभग दोगुना होकर ₹28,100 करोड़ हो गया।
- **मात्स्यिकी और जलीय कृषि** का हिस्सा बढ़कर 7% हो गया है।
- **मध्य प्रदेश मसालों और मसालों के GVO** में अग्रणी है।

पहलें

- कृषि अवसंरचना कोष, डिजिटल कृषि मिशन, पीएम मत्स्य संपदा योजना, MIDH, PMFBY, RKVY, आदि।

महत्त्व

- कृषि का GDP में लगभग **16%** का योगदान है।
- यह क्षेत्रक देश की लगभग **46.1% आबादी** को आजीविका प्रदान करता है।
- यह उत्पादकता, आय और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करता है।

3.8.6. संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme: MISS)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए **संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS)** के तहत **ब्याज छूट (IS) घटक** को जारी रखने को मंजूरी दी है।

संशोधित ब्याज छूट योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से **3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7% की रियायती ब्याज दर** पर उपलब्ध कराया जाता है। पात्र **ऋण-दाता संस्थानों को 1.5% की ब्याज** छूट दी जाती है।

- **3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन** किसानों के लिए ब्याज़ दर को घटाकर **4%** कर देता है, बशर्ते वे समय पर क़र्ज़ चुकाएं।
- केवल **पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज छूट का लाभ 2 लाख रुपये तक के ऋण** पर ही मिलता है।

महत्त्व

- यह क़रीब **5.9 करोड़ किसानों** को सहारा देता है (फ़रवरी 2025 तक के आँकड़े)।
- यह किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराता है।
- यह किसानों को संकट की स्थिति में अपनी उपज की संकट के समय बिक्री से रोकता है।
- यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराता है।

KCC के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **1998** में लॉन्च किया गया था। **2019** में इसका संबद्ध क्षेत्रकों तक भी विस्तार कर दिया गया था।
- **उद्देश्य:** यह खेती, फसल कटाई के बाद की गतिविधियों, विपणन और उपभोग की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करता है।
- **जारीकर्ता:** यह विभिन्न सार्वजनिक/ निजी/ ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किया जाता है और इसकी वैधता **5 साल** की होती है।
- **ऋण सीमा:** इसकी ऋण सीमा फसल चक्र और उद्देश्य पर आधारित होती है, और इसे **किसान ऋण पोर्टल** के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।

3.8.7. अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics: ICRISAT)

ICRISAT ने RIS के साथ साझेदारी में, **ग्लोबल साउथ** के देशों के बीच कृषि नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए **ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (ISSCA)** लॉन्च किया।

- ICRISAT ने भारत की विकास साझेदारी पहल **DAKSHIN** के साथ भी एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- RIS नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।
- **ISSCA:** कृषि में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करने के लिए भारत की 'DAKSHIN' पहल के साथ जुड़ा एक प्रमुख मंच।

ICRISAT के बारे में

- **मुख्यालय:** हैदराबाद।
- **स्थापना:** 1970 के दशक में CGIAR के तहत।
- **उपलब्धियां:** अफ्रीका खाद्य पुरस्कार (2021) प्राप्त किया और दुनिया की पहली अरहर की हाइब्रिड किस्म विकसित की।

3.8.8. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board)

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन निज़ामाबाद, तेलंगाना में किया गया।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- **मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **लक्ष्य:** यह मसाला बोर्ड और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर हल्दी क्षेत्रक के विकास का नेतृत्व एवं समन्वय करेगा।
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष**: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
  - **सदस्य:** आयुष मंत्रालय और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि;
    - तीन राज्यों से (रोटेशन आधार पर) राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी;
    - अनुसंधान में शामिल चयनित राष्ट्रीय/ राज्य संस्थान और हल्दी किसानों व निर्यातकों के प्रतिनिधि।
  - वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक **सचिव।**
- **भूमिकाएं:** यह अनुसंधान और विकास (R&D), निर्यात, मूल्य संवर्धन, जागरूकता, उपज और बाजार के विस्तार को बढ़ावा देगा।

हल्दी के बारे में

- हल्दी को **"गोल्डन स्पाइस"** के रूप में भी जाना जाता है। यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है।
- यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है।
- **भारत:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है (वैश्विक उत्पादन का 70%)।
- **प्रमुख राज्य:** तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
- **GI-टैग प्राप्त किस्में:** इरोड, सांगली, वैगाँव और लाकाडोंग।

3.8.9. नैनो उर्वरक (Nano Fertilizers)

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ब्राजील में अपना **पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र** स्थापित करेगा।

- इफ्को ने 2021 में दुनिया का पहला **'नैनो लिक्विड यूरिया'** उर्वरक लॉन्च किया था और फिर बाद में **2023 में नैनो-DAP लॉन्च** किया।

नैनो उर्वरकों के बारे में

- **नैनो उर्वरक** ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें **नैनो आकार की सामग्री** (100 नैनोमीटर या उससे कम) में **लपेटा या कोट** किया जाता है।
- इससे **पोषक तत्व धीरे-धीरे और नियंत्रित रूप से मिट्टी** में घुलते हैं।

लाभ

- **संधारणीय कृषि को बढ़ावा देता है:** यह मृदा और जल के प्रदूषण को कम करता है।
- **लागत में किफायती:**
  - पौधों द्वारा **पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण** होता है।
  - **उर्वरकों की बर्बादी कम** होती है।
  - **बार-बार उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं** पड़ती है।

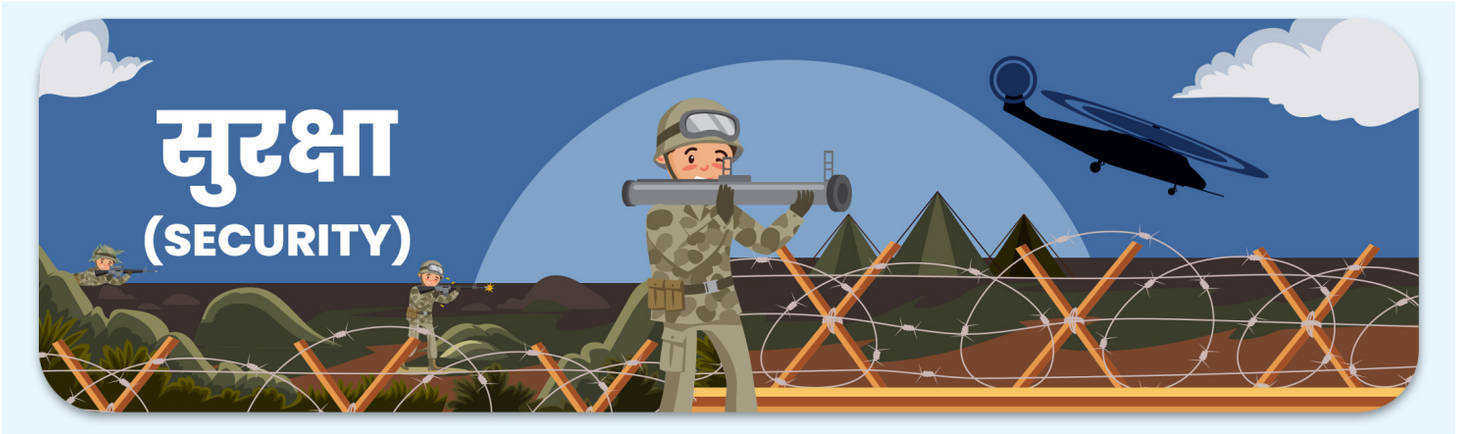

4.1. पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA (FIFTH-GENERATION FIGHTER JET AMCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्री ने **एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)** नामक स्वदेशी **5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए एक एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है।**

AMCA कार्यक्रम का विवरण

- **पृष्ठभूमि:** 2024 में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) द्वारा अनुमोदित।
- **उद्देश्य:** 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट AMCA का स्वदेशी रूप से विकास।
- **समय-सीमा:** 2028-29 तक प्रोटोटाइप; 2034-35 तक भारतीय वायु सेना में शामिल।
- **वेरिएंट:** GE-F414 इंजन के साथ AMCA Mk1; स्वदेशी इंजन के साथ Mk2
- **अग्रणी एजेंसी:** DRDO के तहत ADA
- **उद्योगों के साथ टाई-अप:**
  - उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
  - HAL लड़ाकू विमानों का प्रमुख उत्पादक रहा है।
  - सार्वजनिक और निजी कंपनियां स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यमों के रूप में बोली लगा सकती हैं।
  - केवल भारतीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने वाली कंपनियां ही पात्र हैं।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में

- **लड़ाकू जेट पीढ़ियाँ 1990 के दशक में** प्रमुख तकनीकी प्रगति को वर्गीकृत करने के लिए यह प्रणाली उभर कर सामने आई।
- 5वीं पीढ़ी के जेट विमान सबसे उन्नत हैं, जिनमें **ट्विन इंजन, स्टील्थ क्षमताएं, सुपरक्रूज, उन्नत एवियोनिक्स और 360° युद्धक्षेत्र जागरूकता के लिए एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं।**
- इनका विकास और रखरखाव महंगा है।
  - उदाहरण: F-22 और F-35 (अमेरिका); Su-57 (रूस); J-20 (चीन)।
- **अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन** जैसे कई देश **AI, हाइपरसोनिक और मानवरहित क्षमताओं वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान** विकसित कर रहे हैं।

पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA का सामरिक महत्त्व

- यह पुराने जेट विमानों को प्रतिस्थापित करके तथा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाकर **भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में सहायता करता है।**
- चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C जैसे **क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करता है।**
- आत्मनिर्भर भारत के तहत **रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है** और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

भूमि Aअधिग्रहण मानदंडों में ढील देकर, रक्षा-विशिष्ट औद्योगिक अवसंरचना में निवेश करके, HAL के अनुभव का लाभ उठाकर तथा निजी क्षेत्रक की क्षमता का समर्थन, निवेश की रूपरेखा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए IPR कानून सहित एक **बहुआयामी रणनीति आवश्यक है।**

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

4.2.1. सिल्वर नोटिस (SILVER NOTICE)

भारत के अनुरोध पर **इंटरपोल** ने **भारत के लिए पहला सिल्वर नोटिस** जारी किया। इंटरपोल ने **वीज़ा धोखाधड़ी मामले में वांछित पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शौकीन की वैश्विक परिसंपत्तियों का पता लगाने** के लिए यह नोटिस जारी किया है।

सिल्वर नोटिस के बारे में

- यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए इंटरपोल के कलर-कोडेड नोटिस में एक नया नोटिस है।
- **उद्देश्य:** भगोड़े अपराधियों और मुख्य आरोपियों की संपत्तियों का पता लगाने और जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है, भले ही वे संपत्तियां अन्य देशों में ही क्यों न हों।
- **वैश्विक सहयोग:** पायलट चरण में 51 देशों में भारत भी शामिल (नवंबर 2025 तक)।
- **पहला प्रयोग:** जनवरी में इटली की ओर से जारी किया गया था।
- **सीमा:** प्रत्येक देश पायलट चरण के दौरान अधिकतम 9 नोटिस का अनुरोध कर सकता है।

इंटरपोल के बारे में

- **मुख्यालय:** ल्योन, फ्रांस।
- **उत्पत्ति: 1923** में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस के दौरान **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC)** के रूप में स्थापित और **1956 में इसका नाम इंटरपोल कर दिया गया।**
- **सदस्य:** 196 देश (भारत एक संस्थापक सदस्य)।
- **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB): सदस्य देशों द्वारा इंटरपोल के साथ संपर्क बनाने के लिए पहुंच बिंदु।**
  - भारत ने CBI को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) घोषित किया है **और इसने बेहतर समन्वय के लिए भारतपोल पोर्टल भी विकसित किया है।**
- **शासी निकाय:** महासभा और कार्यकारी समिति।

4.2.2. राजस्थान के पोखरण में 'रुद्रास्त्र' का सफल परीक्षण (SUCCESSFUL TRIAL RUDRASTRA CONDUCTED AT POKHRAN, RAJASTHAN)

इस परीक्षण में हाइब्रिड मानवरहित हवाई वाहन (UAV) रुद्रास्त्र ने अपनी **वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग (VTOL) क्षमताओं, विस्तारित उड़ान रेंज, रियल-टाइम निगरानी और 50 किलोमीटर की दूरी पर सटीक लक्ष्य को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया।**

रुद्रास्त्र के बारे में

- यह सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) UAV है।
- **विशेषताएँ:**
  - **इसकी कुल रेंज** (लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित) **170 किलोमीटर** है। यह **लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान** भर सकता है।
  - इसमें **सटीक दिशा निर्देशित एंटी-पर्सनेल वारहेड्स** लगे हैं, जिन्हें **मध्यम ऊंचाई** से छोड़ा जा सकता है।
  - यह **लाइव वीडियो भेज** सकता है और **स्वचालित मोड में लॉन्च स्थान पर वापस लौट** सकता है।

4.2.3. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (EXERCISES IN NEWS)

खान क्वेस्ट अभ्यास (Exercise Khaan Quest)	**भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी 22वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट' में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलानबटोर पहुंची है।** **शुरुआत:** 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में। → पहला बहुपक्षीय खान क्वेस्ट अभ्यास साल 2006 में शुरू हुआ।
पासेक्स/ PASSEX	भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास PASSEX** उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया।

पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. कृषि वानिकी (AGROFORESTRY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए **कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम 2025 जारी किए हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- मॉडल **नियमों में शामिल हैं** :
  - कृषि वानिकी के लिए भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया।
  - कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की कटाई।
  - कृषि वानिकी से उत्पादित इमारती लकड़ी का प्रमाणीकरण/ट्रांजिट।

भारत में कृषि वानिकी के बारे में

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति-2014 के अनुसार, "कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो खेतों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ और झाड़ियाँ को एकीकृत करके उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की संधारणीयता को बढ़ाती है।"
- इसका **उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है,** जो **फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक हो।**
- भारत के कृषि वानिकी वृक्षारोपण **भारत के भौगोलिक भू-क्षेत्र के लगभग 8% भाग पर फैले हुए हैं।**

कृषि वानिकी का महत्त्व (कृषि वानिकी पर EAC-PM वर्किंग पेपर)

- **कृषि विकास**: यह **कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकता है** ।
- **विविध प्रभाव**: इससे 50% ईंधन की लकड़ी, 60% कागज की लुगदी और 9-11% चारे की जरूरतें पूरी होती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** यह **कृषि उत्पादन को बढ़ाता है (औसतन 51 प्रतिशत**) और फसल की विफलता को रोकता है।
- **संधारणीय विकास:**
  - **कार्बन पृथक्करण:** प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 13.7 से 27.2 टन CO_2 का पृथक्करण।
  - **मृदा स्वास्थ्य:** यह **मृदा की जैविक कार्बन सामग्री (SOC) सांद्रता में सुधार करता है** और **मृदा लवणता को कम करता है** ।
  - **जलवायु स्मार्ट कृषि**: यह **चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकती है** ।
  - **पर्यावरण संबंधी:** यह **प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करती है और पारिस्थितिक तंत्र की** बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है ।
  - **वन के बाहर वृक्ष:** कृषि वानिकी वन के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

कृषि वानिकी के विकास की चुनौतियाँ

- **नीति में खामियां**: किसानों के लिए कृषि वानिकी ट्री मैनुअल के अभाव के कारण चयनित वृक्षों के बारे में **जानकारी का अभाव** है।
- **प्रतिबंधात्मक विनियम**: परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल है।

भारत में कृषि-वानिकी प्रणालियां

- **कृषि वानिकी (Agrisilviculture):** फसलों को वृक्ष फसलों के साथ जोड़ना।
- **कृषि-बागवानी (Agri-horticulture):** फलदार वृक्षों को फसलों के साथ जोड़ना।
- **कृषि-वानिकी-बागवानी (Agri-silvi-horticulture):** वृक्षों, फलदार वृक्षों और फसलों का संयोजन।
- **कृषि-वानिकी-पशुचारण (Agri-silvi-pasture):** भूमि पर वृक्षों को पशुओं के साथ जोड़ना।
- **बागवानी-सब्जी उत्पादन (Horti-olericulture):** फलदार वृक्षों और सब्जियों का संयोजन।
- **वानिकी-पशुचारण (Silvi-pasture):** पशुधन, चारा और वृक्षों का एकीकरण।
- **जीवित बाड़ (Live fence):** झाड़ियां और वृक्ष जो सीमाएं बनाते हैं।
- **वानिकी या बागवानी-रेशम उत्पादन (Silvi or Horti-sericulture):** रेशम उत्पादन के साथ वृक्ष या फलदार वृक्ष।
- **वानिकी-सब्जी उत्पादन (Silvi-olericulture):** वृक्षों और सब्जियों का संयोजन।
- **बागवानी-पशुचारण (Horti-pasture):** फलदार वृक्षों को चरागाह या पशुधन के साथ जोड़ना।

- **भारत की नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) का अपर्याप्त उपयोग:** अब तक 82% आवेदन केवल तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं।
- **उच्च किस्म के बीजों की उपलब्धता**: **बेहतर पौध सामग्री की कमी है**।
- **पिछली नीतियों में बाधाएं: पॉप्लर, यूकेलिप्टस** जैसी **कुछ प्रजातियों पर अत्यधिक जोर दिया गया** जो भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

निष्कर्ष

लाभप्रदता, उत्पादन और पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन के लिए कानूनों को सरल बनाने, NTPS के बेहतर उपयोग और अगली पीढ़ी की प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है।

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 (International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI) में भारत के आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ICDRI 2025 द्वारा लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) में तटीय रेसिलिएंस के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया है।**
- इस वर्ष का सम्मेलन यूरोप में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन है। इसकी सह-मेजबानी ICDRI एवं फ्रांस सरकार द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन की थीम है: "शेपिंग अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजंस"।

तटीय क्षेत्रों से संबंधित सुभेद्यता

- **मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम**: दुनिया की 60% से अधिक आबादी और दो-तिहाई बड़े शहर तटीय क्षेत्रों में स्थित है;भारत में लगभग **25 करोड़ लोग समुद्र तट से 50 कि.मी. के दायरे** में रहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन**: **समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और तूफान** जैसे **खतरों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होने का अनुमान है**।
- **आर्थिक नुकसान**: **चक्रवात फेनी (2019) के कारण ओडिशा में विद्युत से संबंधित लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई थी।**
- **सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों पर प्रभाव:** तटीय आपदाओं से सामाजिक रूप से कमजोर आबादी के लिए **मौजूदा असमानताओं में और वृद्धि होने की संभावना है।**
- **पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरा**: चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति के कारण 2100 तक **दुनिया के आधे मैंग्रोव को गंभीर खतरे का** सामना करना पड़ सकता है।
- **तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरे:**
  - **सुनामी**: **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने 14 देशों** में **230,000** से अधिक लोगों की जान जान चली गई थी।
  - **चक्रवात**: **चक्रवात 'रिमल' (2024) ने भारत और बांग्लादेश को काफी प्रभावित किया।**
  - **तूफानी ज्वार:** 2023 में **2-2.5 मीटर ऊंची तूफानी ज्वारीय लहरें कच्छ और मोरबी जिलों को** जलमग्न कर दिया था ।
  - **तटीय अपरदन: भारत की 33.6% तटीय रेखा अपरदन के कारण खतरे में है।**

भारत के प्रधान मंत्री ने डिजास्टर रेजिलिएंस यानी आपदा-प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पांच वैश्विक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया

शिक्षा में आपदा-प्रतिरोध का एकीकरण
शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से जागरूकता और तैयारी का निर्माण।

एक वैश्विक डिजिटल कोष का निर्माण
आपदा-प्रतिरोध के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और सबकों का दस्तावेजीकरण करना।

अभिनव वित्त-पोषण को बढ़ावा देना
विकासशील देशों के लिए धन तक पहुंच सुनिश्चित करना।

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) को बड़े महासागरीय देशों के रूप में भारत की मान्यता की पुष्टि
उनकी सुभेद्यताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देना।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना
आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के बारे में

- **शुरुआत:** 2019 में भारत द्वारा **संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में।**
- **परिचय: यह** राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्रक की एक **वैश्विक साझेदारी है।**
- **उद्देश्य:** सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने में सक्षम (रेसिलिएंस) अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- **सदस्य**: **56 सदस्य**, सचिवालय **नई दिल्ली में** ।
- **प्रमुख पहलें**:
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आईलैंड स्टेटस (IRIS):** लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में रेसिलिएंट अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस एक्सलेरेटर फंड:** UNDP और UNDRR के सहयोग से स्थापित।

भारत द्वार तटीय सुभेद्यता के शमन हेतु शुरू की गयी पहलें

- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (2019)**: इसका उद्देश्य **तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना** और मछुआरा समुदायों के लिए **आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।**
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)**: तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए **ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई।**
- **तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI): तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का** आकलन करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र** द्वारा विकसित।
- **बहु-आपदा सुभेद्यता मानचित्र**: **INCOIS ने तटीय खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों** की पहचान करने के लिए मानचित्र विकसित किए हैं ।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)**: इसमें तटीय रेसिलिएंस को समर्थन देने वाला **राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है।**

निष्कर्ष

तटीय क्षेत्रों को जलवायु संबंधी खतरों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, और **CDRI के माध्यम से भारत रेसिलिएंस अवसंरचना निर्माण** और **तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों का** नेतृत्व कर रहा है ।

5.2.1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्तपोषण {DISASTER RISK REDUCTION (DRR) FINANCING}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ने "रेसिलिएंस पे: फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फ्यूचर" शीर्षक से **वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट (GAR)** जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, हाल ही में भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (GP2025) की 8वीं बैठक में विश्व की सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय प्रणाली का प्रदर्शन किया है।
- GPDRR की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का मूल्यांकन और उस पर चर्चा करना है।

DRR के लिए मौजूदा वित्त-पोषण तंत्र

संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कोष	बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)	राष्ट्रीय स्तर	द्विपक्षीय सहायता और साझेदारियां	अन्य
• उदाहरण के लिए- हरित जलवायु कोष (GCF) DRR को समर्थन प्रदान करता है।	• उदाहरण के लिए- विश्व बैंक का आपदा जोखिम वित्त-पोषण और बीमा (DRFI) कार्यक्रम।	• राष्ट्रीय और स्थानीय बजटों में DRR को शामिल करना। • **जलवायु वित्त-पोषण:** उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं (NAPs) आदि।	• उदाहरण के लिए- USAID विविध DRR कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है।	• निजी क्षेत्रक और मिश्रित वित्त-पोषण (उदाहरण के लिए- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) क्या है?

यह ऐसे कदमों को दर्शाता है जो **नई आपदाओं की आशंका को रोकने**, **मौजूदा जोखिम को कम करने** और **बचे हुए जोखिम** का प्रबंधन करने के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य **लचीलापन** और **सतत विकास** को मजबूत करना होता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है? (GAR 2025)

- **सीमित सहायता**: **विकास सहायता का केवल 2% ही** DRR पर खर्च होता है।
- **बढ़ता आर्थिक बोझ**: **पिछले दो दशकों में आपदाओं से होने वाली वित्तीय हानि दोगुनी** हो गई है।
- **विकासशील देशों की उच्च सुभेद्यता:** केवल **49% अल्प विकसित देशों के** पास **मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम**।
- **3 नकारात्मक चक्रों को तोड़ना**:
  - **आय में गिरावट, कर्ज में वृद्धि का चक्र**: **2050 तक** जलवायु संबंधी खतरों के कारण वैश्विक आय में **19% की गिरावट आ सकती है।**
  - **असंधारणीय जोखिम हस्तांतरण चक्र:** भारत में **बीमा कवरेज 1% से भी कम है**।
  - **रिस्पांड-रिपीट चक्र:** DRR में निवेश किया गया प्रत्येक 1 डॉलर भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई में 15 डॉलर की बचत करता है।

DRR हेतु पर्याप्त वित्त-पोषण जुटाने में प्रमुख चुनौतियां?

- DRR वित्त-पोषण प्रणालियों को समर्थन देने के लिए **समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र का अभाव ।**
- वित्तीय निर्णयों में DRR का सीमित एकीकरण।
- राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण मानना।

भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणाली

- **DRR वित्त-पोषण तंत्र:** भारत राष्ट्रीय से जिला स्तर तक **पूर्व-निर्धारित, नियम-आधारित आवंटन का पालन करता है, यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा समर्थित है।**
- **वर्तमान आवंटन**: **15वें वित्त आयोग के अंतर्गत** आवंटन **2.32 ट्रिलियन रुपये (लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक किया गया है।**
- **चार प्रमुख सिद्धांत** :
  - तैयारी, शमन, राहत और पुनर्बहाली के लिए डेडिकेटेड फाइनेंशियल विंडो।
  - **सुभेद्य समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना।**
  - **सरकारी के सभी स्तरों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।**
  - **जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों का मापन।**

आगे की राह

- **विनियामक फ्रेमवर्क में सुधार:** आपदा-रोधी निवेश के लिए **मानक और वर्गीकरण तैयार करना।**
- **वित्त पर नज़र रखना**: **जोखिम निवारण** और राजकोषीय आंकड़ों में वित्त-पोषण प्रवाह पर नज़र रखना।
- **अभिनव वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना**: **मिश्रित वित्त, ग्रीन बॉण्ड, आपदा बॉण्ड,** आदि।
- **विभिन्न स्तरों पर वित्त-पोषण को बढ़ावा देना:** कम लागत वाली, बार-बार आने वाली आपदाओं को राष्ट्रीय कोष या आकस्मिक क्रेडिट लाइन्स के माध्यम से कवर करना।

निष्कर्ष

DRR वित्त-पोषण एक **रणनीतिक निवेश है। इसके लिए** वैश्विक समुदाय को प्रतिक्रियात्मक खर्च से हटकर जोखिम आधारित पूर्व नियोजन को अपनाना होगा, ताकि लचीलापन को वित्तीय और नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रखा जा सके।

5.3. समुद्री आपदाएं (MARITIME DISASTERS)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) से हाल की समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा करने का आग्रह किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के तट के पास जहाजों के डूबने और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण, भारत ने IMO की मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी (MSC) में कंटेनर की सुरक्षा और कार्गो के सही प्रकटीकरण से जुड़े नियमों को मजबूत करने का अनुरोध किया है।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु (IMDG) संहिता** के तहत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग, घोषणा, निगरानी के वैश्विक मानकों में सुधार की ओर IMO का ध्यान आकर्षित किया है।

समुद्री आपदाएं

- **जहाज का डूबना, टक्कर, फंस जाना, आग लगना, विस्फोट और तेल का रिसाव, आदि**।
- **हाल की समुद्री घटनाएं**:
  - **कोच्चि के** निकट **MSC एल्सा 3 का डूबना**: **प्लास्टिक के नर्डल्स (छोटे प्लास्टिक के कण)** से तटों और खाद्य श्रृंखलाओं को दूषित करना।
  - **केरल के** तट पर **MV वान हाई 503 पर आग लगना**: इसमें **कैल्शियम कार्बाइड** जैसी **खतरनाक वस्तुएं शामिल थी**, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गईं।

परिणाम:

- **पर्यावरण**: **समुद्री प्रदूषण**, **जैव विविधता की हानि** और **प्लास्टिक नर्डल्स।**
- **स्वास्थ्य**: **विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने** से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
- **आर्थिक हानि**: **तटीय क्षेत्रों का क्षरण**, **आजीविका हानि**, और **सफाई में अत्यधिक खर्च।**

समुद्री घटनाओं/आपदाओं से निपटने में चुनौतियां

- **कार्गो की जानकारी में पारदर्शिता का अभाव:** शिपर्स वस्तुओं की प्रकृति का **उचित रूप से खुलासा नहीं करते हैं** या **गलत जानकारी देते हैं।**
- **संवेदनशील वस्तुओं को अकुशल तरीके से संभालना: लापरवाही से संभालने से आग और पर्यावरणीय जोखिम** बढ़ जाता है।
- **जहाजों के स्वामित्व और प्रबंधन की जटिल संरचना:** ज़िम्मेदारी तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।
- **वैश्विक प्रतिक्रिया में देरी:** ऐसी घटनाओं की जांच करने और सुरक्षा नियमों को अपडेट करने के लिए कोई त्वरित वैश्विक व्यवस्था नहीं है।
- **बीमा संबंधी दावे:** समुद्री बीमा नीतियां जटिल होती हैं, और कवरेज, जिम्मेदारी व खर्च के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में IMO की भूमिका

- **IMDG कन्वेंशन**: **खतरनाक वस्तुओं की हैंडलिंग को विनियमित करता है।**
- **SOLAS, 1974**: **जहाज सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानक निर्धारित करता है।**
- **OPRC-HNS प्रोटोकॉल:** तेल रिसाव के लिए **आकस्मिक योजना** बनाने अनिवार्य है।

- **बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन**: **आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकता है।**
- **AFS कन्वेंशन**: **हानिकारक एंटी-फाउलिंग प्रणालियों को नियंत्रित करता है।**
- **हांगकांग कन्वेंशन**: **सुरक्षित जहाज रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करता है।**

भारत में समुद्री आपदाओं से संबंधित कानूनी तंत्र

- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958**: **समुद्री सुरक्षा, जहाज पंजीकरण, प्रदूषण रोकथाम के लिए।**
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986**: **समुद्री प्रदूषण** के विरुद्ध **पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करना।**
- **राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (NOS-DCP): तेल और खतरनाक रसायनों के रिसाव से निपटने के लिए** के लिए **भारतीय तटरक्षक** द्वारा प्रशासित।
- **एडमिरल्टी (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान) अधिनियम, 2017:** मुद्री दुर्घटनाओं और टकरावों से जुड़े **समुद्री दावों** के निपटान के लिए एक **कानूनी ढांचा** प्रदान करता है और ऐसे मामलों में **न्यायालयों की अधिकारिता** को परिभाषित करता है।

आगे की राह

- **रोकथाम रणनीतियाँ** :
  - **SOLAS** और **MARPOL विनियमों को** लागू करना।
  - **संवेदनशील क्षेत्रों की** सुरक्षा के लिए **जोखिम मानचित्रण।**
  - **रीयल-टाइम निगरानी और ब्लॉकचेन** जैसी **तकनीक** का उपयोग करना।
- **IMO विनियमों में सुधार करना**: **स्वामित्व प्रकटीकरण सुनिश्चित करना** और संबंधित **देश की जिम्मेदारी को चिह्नित करना।**
- **शीघ्र पता लगाना**: **तटीय रडार**, **AIS** और **ड्रोन तैनात करना।**
- **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत**: जहाज मालिकों पर **दायित्व लागू करना।**
- **मध्यस्थता के जरिए** और **कोर्ट के बाहर समाधान को** बढ़ावा देना।
- **बंदरगाह प्राधिकारियों** और **मछुआरों** के लिए **प्रशिक्षण** आयोजित करना।

5.4. भीड़ आपदा प्रबंधन (CROWD DISASTER MANAGEMENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RCB की IPL जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

भगदड़ क्या है?

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोग किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ भागने लगते हैं।

भीड़ प्रबंधन में असफलता और उसके कारण

- **भीड़ नियंत्रण में असफलता:**
  - **अत्यधिक भीड़**: उदाहरण के लिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम की मौजूदा क्षमता 34,600 लोगों की थी जबकि वहां 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे (2025)।
  - **संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी:** उदाहरण के लिए, RCB के सोशल मीडिया हैंडल ने पुलिस के साथ ठीक से समन्वय किए बिना स्टेडियम के गेट्स पर निशुल्क पास देने की घोषणा कर दी।
- **भीड़ के व्यवहार को उकसाने वाले कारण:**
  - **घबराहट और संरचनात्मक समस्याएं:** 2017 में मुंबई के एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान एक संकरी और फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की अफवाह से घबराहट फैल गई थी, जिससे भगदड़ मच गई।
  - **आग/बिजली से संबंधित घटनाएं:** उदाहरणार्थ, 995 में हरियाणा की डबवाली फायर ट्रेजेडी में, एक टेंट वाले कार्यक्रम स्थल में आग लगने और बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई थी।
  - **सेलिब्रिटी की झलक पाने के लिए होड़: उदाहरण के लिए, हैदराबाद में** "पुष्पा 2" के प्रीमियर पर भगदड़ (2024)।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश

तैयारी करना

- **जोखिम मूल्यांकन और योजना**: **फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस (FMEA)** जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरे का आकलन करना चाहिए। इसमें खतरे की गंभीरता, उसके होने की संभावना और उसे पहचानने में होने वाली कठिनाई को मापा जाता है।
- **भीड़ की संख्या से संबंधित नियम:** यह तय किया जाना चाहिए कि प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, और किस स्थिति में (जैसे बैरिकेड टूटने पर) लोगों को निकालना शुरू करना है। **आदर्श उदाहरण**: न्यूयॉर्क में 1,000 से ज़्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित भीड़ नियंत्रण प्रबंधकों को रखना अनिवार्य है।
- **अवसंरचना का विकास:** स्टेडियमों, घाटों , मंदिरों को **कई चौड़े प्रवेश/निकास बिंदुओं** के साथ पुनः डिजाइन किया जाना चाहिए; **बहुभाषी संकेतक और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली।**

- **सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं**: उदाहरणार्थ, महाकुंभ 2025 में **आर्टिकुलेटिंग वॉटर टावर्स (AWT), वॉटर एम्बुलेंस और बहु-आपदा प्रतिक्रिया वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं।**

प्रतिक्रिया

- **सूचना प्रणाली:** भीड़ को सही दिशा देने और उन्हें देरी, रास्ते में बदलाव या किसी खतरे के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए मोबाइल अपडेट, लाउडस्पीकर, साइनेज और डिजिटल बोर्ड।
- **सुरक्षा और संरक्षा उपाय:** सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पर **वायरलेस संचार नेटवर्क**, **CCTV निगरानी के साथ वॉच टावर।**

भारत में भगदड़ रोकने के लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- **RFID और IoT से भीड़ की ट्रैकिंग:** ये तकनीकें लोगों की आवाजाही पर नज़र रख सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जगह पर क्षमता से ज़्यादा भीड़ न हो। उदाहरण के लिए, **कुंभ मेला और वैष्णो देवी तीर्थयात्राओं** ने RFID टैगिंग का परीक्षण किया जा चुका है।
- **निगरानी और रियल-टाइम में भीड़ की मॉनिटरिंग:** AI-आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन्स: AI- आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन्स भीड़ के घनत्व का विश्लेषण कर सकते हैं। ये संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों और घबराहट में होने वाली हरकतों का पता लगाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, **हज यात्रा में भगदड़ को रोकने के लिए AI-आधारित भीड़ निगरानी का उपयोग किया जाता है**, थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन ऊपर से बड़ी भीड़ पर नजर रख सकते हैं।
- **AI मॉडल का उपयोग: भीड़ के पैटर्न** और **निकासी व्यवस्था** की पहचान के लिए सभी बड़ी घटनाओं के डेटा को रिकॉर्ड करके AI मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके अधिक भीड़ भाड़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और संकट आने से पहले ही अधिकारियों को सचेत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए **बहुआयामी योजना**, **अंतर-एजेंसी समन्वय** और **आधुनिक प्रौद्योगिकी एकीकरण की आवश्यकता होती है।** भारत में बढ़ती सार्वजनिक सहरोहों की भीड़ के लिए **NDMA के दिशा-निर्देशों** का सख्ती से पालन आवश्यक हो जाता है।

5.5. भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BHARAT FORECAST SYSTEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **भारत पूर्वानुमान प्रणाली** का अनावरण किया है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है।

भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में

- **विकासकर्ता:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान।
- **भूमिका:** यह भारत में मौसम के पूर्वानुमान का रिज़ॉल्यूशन 12 कि.मी. से बढ़ाकर 6 कि.मी. करती है, जिससे देश के हर गांव को अधिक सटीक और विशिष्ट पूर्वानुमान मिल पाएगा।
- **डेटा स्रोत:** यह 40 **डॉपलर वेदर रडार** से रियल टाइम का डेटा लेती है, जिससे स्थानीय स्तर पर और तात्कालिक पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ती है।
  - **डॉपलर रडार:** यह एक खास तरह का रडार है जो **डॉप्लर प्रभाव** का इस्तेमाल करके कणों की गति का डेटा इकट्ठा करता है। डॉप्लर प्रभाव वह है जिसमें प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है।

BFS का महत्त्व

- **बेहतर सटीकता और गति**: यह प्रणाली जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% अधिक सटीकता देती है और भारी बारिश तथा चक्रवात जैसी चरम घटनाओं के लिए 4-6 घंटे में पूर्वानुमान प्रदान करती है।
  - पहले के मॉडलों में पूर्वानुमान देने में **12 से 14 घंटे लगते थे**।
- **वैश्विक नेतृत्व**: 6 कि.मी. के रिज़ॉल्यूशन के साथ, यह प्रणाली अमेरिका, UK और यूरोपीय संघ जैसे देशों से आगे है, जिनके मॉडल 9-14 कि.मी. के रिज़ॉल्यूशन पर काम करते हैं।
- **आपदा प्रबंधन और कृषि हेतु सहायता**: **गांव** और **ब्लॉक स्तर** पर **अल्पकालिक** और **तात्कालिक पूर्वानुमान संभव। किसानों**, **तटीय समुदायों** और **आपदा प्रबंधन एजेंसियों को फसल नियोजन** और **अग्रिम चेतावनी** में सहायता।
- **आर्थिक लाभ**: यह कृषि, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जलवायु-संबंधी नुकसान को कम करने में मदद करता है।
  - यह **हाई-परफोर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC)** प्रणाली **'अर्का'** (IITM पुणे) और **'अरुणिका'** (NCMRWF, दिल्ली) द्वारा संचालित है, जो तेज़ी से सिमुलेशन (अनुकरण) प्रदान करते हैं।
- **क्षेत्रीय पूर्वानुमान**: **मानसून**, **चक्रवात** और **अत्यधिक वर्षा की घटनाओं** सहित **उष्णकटिबंधीय मौसम संबंधी विक्षोभ के पूर्वानुमान में सुधार करता है**।

निष्कर्ष

भारत पूर्वानुमान प्रणाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसंरचना में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। जैसे-जैसे जलवायु संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं, इस तरह की प्रगति रेसिलिएंस और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में विज्ञान की भूमिका को उजागर करती है।

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

5.6.1. रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई (INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PANEL ON CHEMICALS, WASTE AND POLLUTION ESTABLISHED)

इसकी स्थापना का निर्माण **2022 में** एक **अंतर-सरकारी निकाय की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया है।**

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा आयोजित, जो **पैनल का मुख्यालय भी होगा।**
- यह राष्ट्रों को **रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह** भी प्रदान करेगा।
- यह पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति मंच (IPBES) के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहाकारी मंच है।

पैनल की आवश्यकता क्यों है?

- **त्रिग्रही पृथ्वी संकट को कम करना**: **जलवायु परिवर्तन; प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व अपशिष्ट का संकट।**
  - **प्रतिदिन उपयोग किये जाने वाले रसायनों के अनपेक्षित नकारात्मक प्रभाव** होते हैं।
  - **नगरीय ठोस अपशिष्ट 2.1 बिलियन टन (2023)** से बढ़कर **2050 तक 3.8 बिलियन टन हो जाने की संभावना है।**
  - **पिछले दो दशकों में नए तरह के प्रदूषण करीब 66% बढ़ गए हैं।**

5.6.2. जैविक खतरों पर ILO कन्वेंशन (ILO CONVENTION ON BIOLOGICAL HAZARDS)

ILO के सदस्य देशों ने कार्य-परिवेश में जैविक खतरों से निपटने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया।

कन्वेंशन (ILO कन्वेंशन 192) के बारे में

- सदस्य देशों से **जैविक खतरों से बचाव और सुरक्षा** तथा **तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय नीतियां बनाने का आह्वान किया गया।**
- **भारत की चिंताएं: सभी क्षेत्रकों के आकार पर समान रूप से यह नियम लागू करना, MSMEs और अनौपचारिक उद्यमों पर बोझ बढ़ा** सकता है ।
- **परिभाषाएं बहुत व्यापक हैं**, जिससे **अत्यधिक विनियमन हो रहा है।**

जैविक खतरों (बायोहजार्ड) के बारे में

- **जैविक खतरे जैविक मूल के होते हैं जिनमें रोगजनक सूक्ष्मजीव**, **विषाक्त पदार्थ और बायोएक्टिव पदार्थ** शामिल हैं। **स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारी** सबसे अधिक जोखिम में हैं।
- **प्रेरक कारक**: **वायुमंडलीय परिस्थितियाँ**, **रोगाणुरोधी दवाओं का अत्यधिक उपयोग।**
- **उपाय**: ILO कन्वेंशन, भारत की 2020 संहिता।

कन्वेंशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **उबर, अमेज़न जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के मूलभूत सिद्धांतों एवं अधिकारों और उचित पारिश्रमिक पर केंद्रित पहला प्लेटफ़ॉर्म।**
- अनौपचारिक कार्य को कम करने और औपचारिक कार्य को अपनाने को समर्थन देने के लिए एक संकल्प।
- सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन में संशोधन जहाज पर होने वाली हिंसा और अपने जहाज से बाहर समय व्यतीत करने के अधिकारों से संबंधित हैं। भारत ने 2015 में इसकी अभिपुष्टि की।

5.6.3. स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025 (STATE AND TRENDS OF CARBON PRICING 2025)

विश्व बैंक समूह द्वारा "स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025" रिपोर्ट जारी की गई।

- रिपोर्ट के अनुसार, **ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग (CP)** साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या **2005 में 5** थी, जो **वर्तमान में बढ़कर 80** हो गई है। **भारत, ब्राजील और तुर्की** इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कवरेज:** CP **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां (ETSs) शामिल हैं।**
- **राजस्व सृजन:** वे वैश्विक स्तर पर, 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से ज्यादा की कमाई हुई थी।
- **क्षेत्रवार कवरेज: विद्युत क्षेत्रक के बाद उद्योग क्षेत्रक में सबसे अधिक कवरेज है।**
  - **कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है।**
- **कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग: वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज़्यादा रही, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट (unretired credits) मौजूद थे।**

कार्बन प्राइसिंग (CP) के संबंध में प्रमुख प्रावधान

वैश्विक

- **पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6:** सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक** बनाने के लिए आधार प्रदान करता है।
- **COP29 ने अनुच्छेद 6.2** और **अनुच्छेद 6.4** के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था।
- **CBAM: आयातित वस्तुओं** पर **कार्बन मूल्य** लागू करता है।

भारत

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (2023): बाध्य संस्थाओं** के लिए **अनुपालन तंत्र**, **गैर-बाध्य संस्थाओं** के लिए **ऑफसेट तंत्र**।

कार्बन मूल्य निर्धारण और उसके साधन

- **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली:** सरकार **चिन्हित संस्थाओं** द्वारा उत्पन्न GHG उत्सर्जन की मात्रा/ तीव्रता पर एक सीमा निर्धारित करती है।
- **कार्बन कर:** सरकार चिन्हित की गई संस्थाओं पर उनके GHG उत्सर्जन के लिए **शुल्क लगाती** है।
- **कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म:** ऐसे क्रेडिट सृजित किए जाते हैं, जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये **स्वैच्छिक गतिविधियों** के ज़रिए उत्सर्जन घटाने पर मिलते हैं।

5.6.4. 'एशिया में जलवायु की स्थिति 2024' रिपोर्ट (State of The Climate In Asia 2024)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की।

- WMO, **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।**

मुख्य निष्कर्ष

- **2024 एशिया का सबसे गर्म वर्ष था**, तापमान **औसत से 1.04°C अधिक था।**
- एशिया की तापवृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी है।
- **मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं।**
- **समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर, तापमान में दशकीय वृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी।**

5.6.5. ग्रीन इंडिया मिशन (NATIONAL MISSION FOR A GREEN INDIA)

ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन {या ग्रीन इंडिया मिशन (GIM)} के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए।

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस** के अवसर पर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए।

ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में

- **शुरुआत:** 2011 में। यह **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के आठ मिशनों में शामिल** है।
- **उद्देश्य: वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार,** 2030 तक **2.5-3.0 बिलियन टन CO_2** का **कार्बन सिंक का निर्माण करना।**
- **तीन उप-मिशन**: **वन गुणवत्ता में सुधार**, **वन आवरण में** वृद्धि, **वन-आश्रित समुदायों की आय को बढ़ाना।**
- **क्रियान्वयन अवधि: 10 वर्ष (2021-2030)**
- **संयुक्त वन प्रबंधन समितियों** के माध्यम से कार्यान्वयन।

ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां {ये रणनीतियां भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रतिबद्धता से जुड़ी हैं}

सूक्ष्म पारिस्थितिकी-तंत्र पद्धति को अपनाना: यह मिशन **अरावली, पश्चिमी घाट, उत्तर-पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव, भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR)** जैसे अति-नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी: जैसे- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** निधियों का उपयोग पारिस्थितिक क्षेत्रों की पुनर्बहाली में या ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा।

कार्बन मार्केट का लाभ उठाना: वानिकी और कृषि-वानिकी वृक्षारोपण से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स की स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्रीन इंडिया फोर्स: प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा। यह कैडर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव एवं परिसंपत्तियों की निगरानी में सहयोग करेगा।

5.6.6. ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया (GLOBAL DROUGHT OUTLOOK, 2025 RELEASED)

यह रिपोर्ट **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** ने जारी की है।

मुख्य निष्कर्ष

- **सूखे की गंभीरता में वृद्धि:** दुनिया का **लगभग 40%** भूमि क्षेत्र सूखे की बार-बार और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। उदाहरणों में- **यूरोप (2022)**, **कैलिफोर्निया (2021)**, **हॉर्न ऑफ अफ्रीका शामिल हैं**।
- **आर्थिक प्रभाव:** सूखे की औसत अवधि से आर्थिक हानि में हर साल 3% से 7.5% तक वृद्धि**, फसल की पैदावार में 22% की गिरावट।**
- **पारिस्थितिक:** 1980 के बाद से **वैश्विक भूमि के 37% भाग में मृदा नमी में कमी आई है**, **तथा 62% जलभृतों में** लगातार गिरावट दर्ज की गई है।
- **अन्य:** आपदाओं से होने वाली मौतों में से 34% मौतें सूखे की वजह से होती हैं, **गरीबी** और **विस्थापन बढ़ता है**।

5.6.7. ओशन डार्कनिंग से वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को गंभीर खतरा (GLOBAL OCEAN DARKENING THREATENS UNDERWATER ECOSYSTEMS)

यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि **2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित** हो गया है। यह खासकर **आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों** में हुआ है।

ओशन डार्कनिंग क्या है?

- वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक ज़ोन सिकुड़ता जा रहा है।
  - **फोटिक ज़ोन सूर्यप्रकाशित परत (200 मीटर गहराई) होती** है, जहां **90% समुद्री जीवन** पाया जाता है।
- यह फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन की अधिकता के कारण पारिस्थितिकीय बदलाव की वजह से हो सकता है।

ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक

- **तटीय महासागरों में:** कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट के जमाव से।
- **खुले महासागरों में: समुद्री सतह का गर्म होना और महासागरीय परिसंचरण पैटर्न** में जलवायु-संचालित परिवर्तन।

ओशन डार्कनिंग का प्रभाव

- **समुद्री पारिस्थितिकी:** प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास आदि को प्रभावित करता है, जिससे समुद्री उत्पादकता में भी गिरावट आती है।
- **मत्स्य उद्योग: मछलियों का पर्यावास सिकुड़** रहा है, जिससे मछलियों की संख्या घटती है।
- **जलवायु का विनियमन: कार्बन अवशोषण** और **ऑक्सीजन उत्पादन में** बाधा डालता है।

5.6.8. ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) चैलेंज {BLUE NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (NDC) CHALLENGE}

ब्राज़ील और फ्रांस ने **NDCs चैलेंज** लॉन्च किया।

- आठ देश **ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स** इस पहल में शामिल हो गए हैं।

ब्लू NDCs चैलेंज के बारे में

- देशों से COP-30 से पहले **महासागर को अपने NDCs के केंद्र में रखने** का आह्वान करता है।
- **समर्थन: ओशन कन्ज़र्वेंसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट थ्रू द ओशन रेसिलिएंस एंड क्लाइमेट अलायन्स** द्वारा समर्थन प्राप्त।

जलवायु संकट से निपटने में महासागर की भूमिका

- **कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण**: महासागर **वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का 30% अवशोषित करते हैं।**
  - **तटीय पर्यावास** स्थलीय वनों की तुलना में **चार गुना अधिक** कार्बन अवशोषित करते हैं ।
- **ताप विनियमन**: यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% हिस्सा अवशोषित करते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा**: अपतटीय पवन ऊर्जा में **वैश्विक विद्युत की एक तिहाई से अधिक आवश्यकताओं को पूरा** करने की क्षमता है।

महासागरीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुरक्षा के लिए वैश्विक पहलें

समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs): ये संरक्षण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं। यहां समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक (2021-2030): इसका उद्देश्य महासागरीय पारिस्थितिकी-तंत्र में आ रही गिरावट को रोकने के लिए महासागर विज्ञान को प्रोत्साहित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

भारतीय पहलें: मिष्टी/ MISHTI (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम), डीप ओशन मिशन आदि।

5.6.9. तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन' (UNOC-3) (THIRD UNITED NATIONS OCEAN CONFERENCE: UNOC3)

तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' **'नीस ओशन एक्शन प्लान' अपनाने के साथ संपन्न** हुआ।

- **UNOC-3 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया**, जिसकी सह-मेजबानी **फ्रांस और कोस्टा रिका ने की।**

एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु

- **SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन देना हेतु वैश्विक रोडमैप - महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का** संरक्षण और संधारणीय उपयोग। **SDG 14 सबसे कम वित्त पोषित** SDG है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते** तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- महासागरों पर **जलवायु परिवर्तन और अम्लीकरण के प्रभाव को कम करने** के लिए **समन्वित वैश्विक कार्रवाई** का आह्वान किया गया।

5.6.10. राजस्थान में नए रामसर स्थल (NEW RAMSAR SITES IN RAJASTHAN)

भारत की दो आर्द्रभूमियों को "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची" में शामिल किया गया।

- राजस्थान की खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया,जिससे भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है।
- **विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून** को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के **विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है; 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन'।**
- इन साइट्स के जुड़ने से **राजस्थान में अब चार रामसर स्थल हो गए हैं**, जिनमें **सांभर साल्ट लेक** और **केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं**।

नई रामसर साइट्स के बारे में

- **खीचन आर्द्रभूमि**: **उत्तरी थार रेगिस्तान, फलोदी जिले में स्थित है**। इसमें दो जल निकाय, रातड़ी नदी और विजयसागर तालाब, नदी-तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। **यहाँ प्रवासी डेमोइसेल क्रेन (एंथ्रोपोइड्स वर्ग) आते हैं।**
- **मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स: मेनार और खेरोदा गांव, उदयपुर जिला। तीन तालाबों** से निर्मित **मीठे पानी की मानसूनी वेटलैंड।** उल्लेखनीय प्रजातियों में **क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध** और **लॉन्ग बिल्ड वल्चर शामिल हैं।** यहाँ **70 से अधिक पादप प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें आम के पेड़ (मैंगीफेरा इंडिका) शामिल हैं। इसपर बड़ी संख्या में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (टेरोपस जाइगेंटस) प्रजाति रहती है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

उत्पत्ति: यह अभिसमय **1971 में ईरान के रामसर शहर** में अपनाया गया और **1975 में लागू** हुआ था।

परिचय: यह एक **अंतर-सरकारी संधि** है, जो **आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग के लिए फ्रेमवर्क** प्रदान करती है।

मानदंड: किसी आर्द्रभूमि को **"अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि" के रूप में नामित** करने के लिए उसे निर्धारित **9 मानदंडों में से कम-से-कम एक मानदंड** को पूरा करना होता है।

सचिवालय: ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड (IUCN के मुख्यालय में स्थित)

भारत: भारत **1 फ़रवरी, 1982 को रामसर अभिसमय का पक्षकार** बना था। **एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स भारत में** हैं। **भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91** हो गई है।

5.6.11. ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य (GREATER FLAMINGO SANCTUARY)

तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोजेस) के बारे में

- **IUCN स्थिति: लीस्ट कंसर्न**
- **वितरण: अफ्रीका, पश्चिमी एशिया (भारत), और दक्षिणी यूरोप**
- **पर्यावास: यह प्रजाति उथली लवणीय या क्षारीय आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है**
- **विशेषताएं:** यह पक्षी दूर तक यात्रा करता है। हालांकि, यह फिलोपेट्रिक है, यानी बार-बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आस-पास ही रहता है जहां इसे प्रजनन करना होता है।
- **कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण एशिया में** ग्रेटर फ्लेमिंगो के एकमात्र प्रजनन स्थल है, **जिसे "फ्लेमिंगो सिटी" के रूप में जाना जाता है**।

5.6.12. IBAT एलायंस (IBAT ALLIANCE)

IBAT एलायंस ने **2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना** कर दिया है।

- **यह संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व डाटाबेस, IUCN रेड लिस्ट,** और **प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों पर विश्व डाटाबेस को** समर्थन करेगा।

IBAT एलायंस के बारे में

- **मुख्यालय: यू.के.** (**2008 में स्थापित**)
- **चार** संरक्षण संगठनों का गठबंधन: **बर्डलाइफ इंटरनेशनल**, **कंजर्वेशन इंटरनेशनल**, **IUCN** , **UNEP-WCMC।**
- **मिशन:** संगठनों को **जैव विविधता से संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद** करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना।

5.6.13. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (INTERNATIONAL BIG CAT ALLIANCE: IBCA)

नई दिल्ली में आयोजित **IBCA की पहली बैठक** में केंद्रीय **मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष** नियुक्त किया गया।

- यह सभा IBCA की सर्वोच्च निर्णय-निर्माणकारी संस्था है। इसकी प्रत्येक दो वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित होती है।

IBCA के बारे में

- **बड़ी बिल्लियों के संरक्षण** के लिए यह कई देशों और कई एजेंसियों का एक समूह (गठबंधन) है। इसमें 95 ऐसे देश शामिल हैं- जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं।
  - **इन बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं।**
- **उत्पत्ति: अप्रैल 2023 में लॉन्च (भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर)।**
- **मुख्य लक्ष्य:** बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** के लिए मंच स्थापित करके **सहयोग को बढ़ावा देना।**
- **संस्थापक सदस्य (16): अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, केन्या, नेपाल,** आदि।
- **भारत** IBCA का **मेजबान देश** और यहां इसका **सचिवालय** है।

बिग कैट्स की सातों प्रजातियों की संरक्षण स्थिति

बिग कैट्स प्रजातियां	IUCN स्थिति	CITES दर्जा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)	एंडेंजर्ड	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
शेर (पैंथेरा लियो)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
हिम तेंदुआ (पैंथेरा अन्सिया)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
जगुआर (पैंथेरा ओंका)	नियर थ्रेटेन्ड	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती
प्यूमा (प्यूमा कॉनकलर)	लीस्ट कंसर्न	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती

5.6.14. राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत संशोधित दिशा-निर्देश (REVISED GUIDELINES ON NATIONAL BIOENERGY PROGRAMME)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 'वेस्ट टू एनर्जी' तथा 'बायोमास'** घटकों से जुड़े दिशा-निर्देशों को अपडेट किया है।

- **जैव ऊर्जा:** फसल अवशेषों, फसलों और जैविक अपशिष्ट जैसे **जैविक पदार्थ** आधारित **बायोमास ईंधन से** उत्पन्न **नवीकरणीय ऊर्जा।**

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- **लॉन्च: 2022**
- **1715 करोड़ रुपये के बजट** के साथ **दो चरण**; **चरण-1 (2021-22 से 2025-26)।**
- **उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय** प्रदान करते हुए **बिजली उत्पादन** के लिए **अधिशेष बायोमास का** उपयोग करना।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA):** परियोजना विकासकर्ताओं को प्रदान की जाएगी। **विशेष वर्गों को 20% अधिक CFA** मिलेगा।

तीन घटक:

- **वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम: बायोगैस, बायो-CNG, बिजली या सिनगैस** बनाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देना।
- **बायोमास कार्यक्रम: बायोमास ब्रिकेट/ पैलेट बनाने वाले संयंत्रों और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं** को सहयोग देना।
- **बायोगैस कार्यक्रम: स्वच्छ ईंधन (कुकिंग गैस), स्वच्छता में सुधार** के लिए बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देना। **बायोगैस में 95% मीथेन और CO_2 होती है।**

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम

- **सरलीकृत प्रक्रियाएं: MSMEs** के लिए आसान अनुमोदन ।
- **CFA (आर्थिक सहायता) वितरण में सुधार: दो चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी**- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के बाद **50% CFA**, **80% क्षमता प्राप्ति के बाद शेष**।

बायोमास कार्यक्रम

- **सरलीकृत प्रक्रियाएँ: ब्रिकेट/पेलेट संयंत्रों के लिए किसी मंजूरी दस्तावेज की** आवश्यकता नहीं है।
- **तकनीकी एकीकरण: IoT- आधारित निगरानी समाधान को** सक्षम करना ।
- **पराली जलाने से संबंधित सहायता: NCR में पेलेट उत्पादक MNRE या CPCB योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं।**

5.6.15. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI), 2025 {ENERGY TRANSITION INDEX (ETI), 2025}

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया।

मुख्य तथ्य

- **स्वीडन पहले स्थान पर है,** उसके बाद **फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे हैं।**
- **भारत की रैंक 2024 में 63वें स्थान** से गिरकर 2025 में 71वें स्थान पर आ गयी है।

ETI के बारे में

- यह इंडेक्स दिखाता है कि कोई देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है।
- **दो मुख्य पहलू: सिस्टम प्रदर्शन** (ऊर्जा सुरक्षा, समानता और संधारणीयता) और **ट्रांजिशन के लिए तैयारी** (विनियमन, बुनियादी ढांचा, निवेश)।
- **सूचकांक 43 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है** और **देशों को 0 से 100 के अंकों के बीच स्कोर दिया जाता है।**

5.6.16. थर्स्टवेव (THIRSTWAVE)

शोधकर्ताओं ने **एटमोस्फियरिक थर्स्ट की दीर्घावधि का वर्णन** करने के लिए एक नया शब्द **"थर्स्टवेव्स"** गढ़ा है।

थर्स्टवेव क्या है?

- कम-से-कम **लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग** उस अवधि के लिए **अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक** हो।
  - वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि **वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता** मौजूद है।
- इसका अध्ययन करने से **किसानों को जल संसाधनों का प्रबंधन करने** और **फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद मिलती है।**

5.6.17. सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया (SALKHAN FOSSIL PARK ADDED TO UNESCO TENTATIVE LIST FOR WORLD HERITAGE SITES)

इसका आधिकारिक नाम **सोनभद्र फॉसिल्स पार्क** है और यह **उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले** में स्थित है।

- IUCN के 2020 के "जीवन के विकास (Evolution of Life)" से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार यह पार्क जियो-हेरिटेज साइट की श्रेणी में आता है और **यूनेस्को के 2021 फ्रेमवर्क के अनुरूप है।**

सलखान फॉसिल पार्क के बारे में

- यह कैमूर पहाड़ियों (जो विन्ध्य पर्वतमाला का हिस्सा हैं) में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास है।
- यह दुनिया के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। यहां के जीवाश्म करीब 1.4 बिलियन (140 करोड़) साल पुराने हैं।
  - **साइट के जीवाश्म संग्रह में साइनोबैक्टीरिया के समूहों** द्वारा निर्मित **स्ट्रोमेटोलाइट्स शामिल हैं।**
  - ये जीवाश्मी सूक्ष्म संरचनाएं उस महान ऑक्सीकरण घटना का रिकॉर्ड रखती हैं।

सलखान फॉसिल पार्क का महत्त्व

- **प्राचीन वातावरण को समझने में सहायक: विभिन्न स्ट्रोमेटोलाइट रूपों की** विशेषताएं **प्राचीन समय में जल की गहराई और अवसादन** में परिवर्तन का संकेत देती हैं।
- **प्री-कैम्ब्रियन काल की जानकारी देना:** यह **पृथ्वी के इतिहास के 85% भाग को** कवर करने वाले **प्रीकैम्ब्रियन युग को** प्रदर्शित करके **लर्ड हेरिटेज फॉसिल्स रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरता है।**

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

- **विश्व धरोहर स्थल** वे स्थान होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके **"अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य"** के लिए मान्यता दी जाती है।
  - **विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण अभिसमय (विश्व धरोहर अभिसमय)** द्वारा निर्देशित है ।
- **तीन श्रेणियाँ:** सांस्कृतिक धरोहर; प्राकृतिक धरोहर; तथा मिश्रित धरोहर।
- **पक्षकार देश:** 196 देशों ने अभिसमय की अभिपुष्टि की है।

5.6.18. हाल के ज्वालामुखी विस्फोट (RECENT VOLCANIC ERUPTIONS)

ज्वालामुखी	विशेषताएँ
माउंट एटना	**अवस्थिति:** सिसिली द्वीप, इटली यह **भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊँचा पर्वत** है। यह दुनिया का **सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो** है। **यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी** भी है। यह **यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल** है।
माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी	**अवस्थिति:** फ्लोरेस द्वीप, इंडोनेशिया। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा।
किलाउआ ज्वालामुखी	**अवस्थिति:** हवाई द्वीप का दक्षिण-पूर्वी भाग, अमेरिका शील्ड ज्वालामुखी

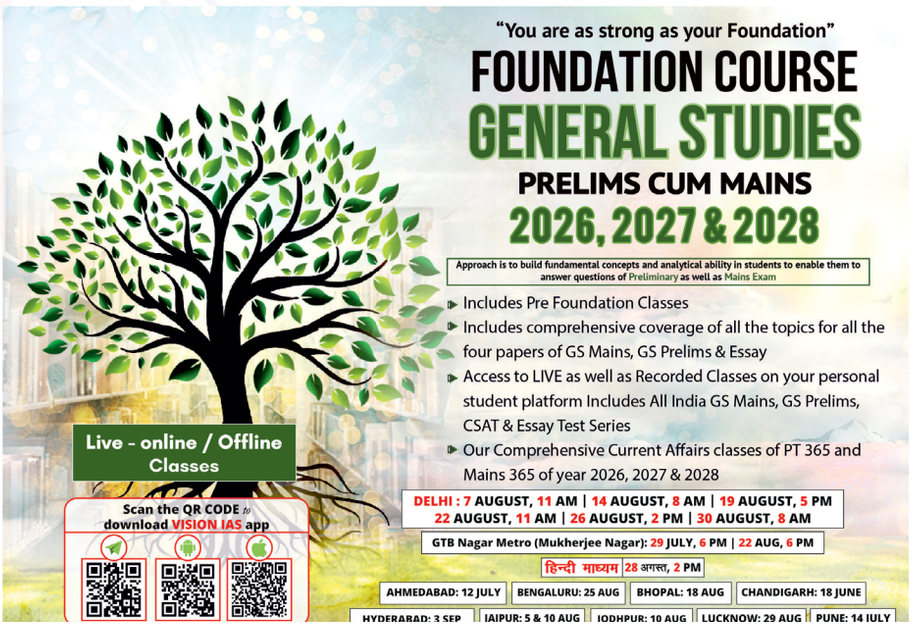

सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. सांस्कृतिक विनियोग (Cultural Appropriation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इतालवी लक्जरी ब्रांड प्राडा पर भारत की पारंपरिक भौगोलिक संकेतक (GI) टैग वाली **कोल्हापुरी चप्पलों** से मिलती-जुलती फ्लैट लेदर सैंडल बेचने के लिए सांस्कृतिक विनियोग का आरोप लगाया गया।

सांस्कृतिक विनियोग क्या है?

- जब कोई **प्रभावशाली समूह किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं** को ऐसे तरीके से अपनाता है, जिसे **अनादरपूर्ण या शोषणकारी** माना जाता है।
  - इसमें बिना सहमति के किसी अन्य **संस्कृति से आर्थिक या सामाजिक रूप से लाभ कमाना** शामिल होता है।
- **अन्य उदाहरण:**
  - **अमेरिकी ब्रांड स्टारबक्स का** "गोल्डन लाटे" या गोल्डन मिल्क **भारतीय आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हल्दी दूध (टरमरिक मिल्क)** के समान है।
  - **इतालवी ब्रांड गुच्ची** द्वारा फूलों की कढ़ाई वाला जैविक लिनन **कफ्तान** बेचना, जो **भारतीय कुर्ते** जैसा दिखाई देता है।

कोल्हापुरी चप्पल के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **12वीं शताब्दी में बीदर के राजा बिज्जल और उनके प्रधान मंत्री बसवन्ना** के शासनकाल से मानी जाती है।
- ये **महाराष्ट्र और कर्नाटक** के स्थानीय समुदाय द्वारा बैग-टैन्ड वेजिटेबल लैदर से निर्मित किया जाता है।
- ये सैंडल अपनी **विशिष्ट गुंथी हुई चमड़े की पट्टियों, जटिल कटवर्क, टिकाऊ बनावट** के लिए जानी जाती हैं।
- इसे **2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** प्रदान किया गया था।

सांस्कृतिक विनियोग के लिए जिम्मेदार कारक

- **IP संरक्षण तंत्र का अभाव।**
- GI अधिकार मुख्य रूप से **'क्षेत्रीय प्रकृति'** के होते हैं। ये **'वैश्विक' या 'अंतरराष्ट्रीय' स्तर पर सीमित** होते हैं, जिससे विदेशों में कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है (उदाहरण के लिए, इटली में कोल्हापुरी चप्पल)।
- **डिजिटल मार्केटप्लेस** पुनर्विक्रय बाजार और डिजिटल पुनरुत्पादन जैसी **खामियां** बड़े पैमाने पर अनियंत्रित बने हुए हैं।
- **प्रवर्तन और जागरूकता का अभाव:** महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक परिवार पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, लेकिन **GI फ्रेमवर्क** के तहत केवल **95 व्यक्ति ही आधिकारिक तौर पर अधिकृत GI उपयोगकर्ता** के रूप में पंजीकृत हैं।

सांस्कृतिक विनियोग में शामिल नैतिक आयाम

- सांस्कृतिक तत्वों को **केवल साध्य (लाभ) के एक साधन के रूप में** मानता है, तथा **समुदायों का सम्मान नहीं करता है, जो कांट के नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन है।**
- **उपयोगितावाद:** कंपनियों के लिए अल्पकालिक लाभ, हाशिए पर मौजूद समुदायों की **सांस्कृतिक गरिमा और कारीगरों की आजीविका को दीर्घकालिक नुकसान** पहुंचाते हैं।
- **अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण'** (Capability Approach) के अनुसार यह कारीगरों की आजीविका को नष्ट करता है, और सांस्कृतिक समुदायों को स्वतंत्रता एवं आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है।

वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रभावित किया है?

सकारात्मक प्रभाव:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे सितार और तबले का पश्चिमी संगीत में उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक पहचान: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत** दुनिया भर में लोकप्रिय है।

नकारात्मक प्रभाव:

- **समांगीकरण (Homogenisation):** वैश्विक मनोरंजन प्लेटफॉर्म युवा संस्कृति को आकार दे रहे हैं। इनसे स्थानीय कलाओं को नुकसान होता है।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** पश्चिमी परिधान तेजी से पारंपरिक भारतीय परिधानों की जगह ले रहे हैं।

निष्कर्ष

हाशिए पर मौजूद समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए मजबूत वैश्विक बौद्धिक संपदा सुरक्षा एवं नैतिक प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

6.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं (Tier-2 Influencers redefining Cultural Capital in Digital India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

टियर-2 और टियर-3 शहरों के **डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स** यानी छोटे कस्बों और क्षेत्रीय शहरों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का उदय हुआ है। इनका भारत में **डिजिटल प्रभाव और सांस्कृतिक पूंजी की गतिशीलता पर गहरा प्रभाव** पड़ा है।

सांस्कृतिक पूंजी क्या है?

- शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान जैसी गैर-आर्थिक परिसंपत्तियां सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाते हैं। (पियरे बोरदियू)
- पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक पूंजी महानगर-केंद्रित है, जिसमें अंग्रेजी, कुलीन संस्थाओं और शहरी सौंदर्यशास्त्र का प्रभुत्व होता है।

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स का उदय

- पटना, सूरत और गुवाहाटी जैसे शहरों के क्रिएटर्स, जिनकी पहचान मूल रूप से क्षेत्रीय है और उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं।
- सोशल मीडिया ने कंटेंट निर्माण और प्लेटफार्म तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है।

चुनौतियां

- डिजिटल विभाजन
- रूढ़िवादिता और प्रतीकात्मकता
- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह
- संस्कृति का वस्तुकरण

ये कैसे सांस्कृतिक पूंजी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं?

- **रुचि का विकेंद्रीकरण**: क्षेत्रीय संस्कृतियों से जुड़ी नई पहचान अब शहरी जीवनशैली की परिष्कृत पहचान से प्रतिस्पर्धा करने लगे है।
- **स्थानीय भाषा शक्ति:** 50% से अधिक शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट का उपयोग करना पसंद करते हैं। शेयरचैट (भारत-फर्स्ट ऐप) पर 180 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
- **लोक परंपराओं का पुनरुद्धार: लोक संगीत** और परम्पराएं डिजिटल कंटेंट में अपनी उपस्थिति को एकीकृत करते हैं। (उदाहरण के लिए- विलेज कुकिंग चैनल)
- **आकांक्षा का लोकतंत्रीकरण:** संबंधित गतिविधियों के इन्फ्लुएंसर्स सफलता को प्रामाणिकता के रूप में पुनः परिभाषित करते हैं।
- **निम्न-वर्गीय अभिव्यक्तियों के लिए मंच:** दलित, आदिवासी और OBCs क्रिएटर्स के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए मंच प्राप्त करते हैं। (उदाहरण के लिए- खबर लहरिया)

निहितार्थ

- **सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण:** ये स्थानीय रिवाजों और प्रथाओं को वैधता प्रदान करते हैं, जिन्हें कभी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना जाता था।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** ShareChat और Moj जैसे मुद्रीकरण मॉडल का उपयोग करके टियर-2 व टियर-3 शहरों के क्रिएटर्स को सशक्त बनाता है।
- **डिजिटल राजनीतिक प्रभाव:** स्थानीय प्रभावशाली लोग जनमत और चुनावी आख्यानों को आकार देते हैं।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करना:** क्षेत्रीय पहचान को समायोजित करते हुए एकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण रूढ़िवादिता को तोड़ना।

निष्कर्ष

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स एक अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक सांस्कृतिक अंतर्क्रिया का सूत्रपात कर रहे हैं, जो अभिजात्यवाद पर प्रामाणिकता और एकरूपता पर विविधता को महत्व देती है।

6.3. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सुधार (IMPROVEMENT IN QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षण संस्थानों की संख्या और रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में

- **जारीकर्ता: लंदन** स्थित **क्वाक्वारेल्ली साइमंड्स (QS)** द्वारा प्रतिवर्ष जारी।
- **पांच मूल्यांकन मापदंड (अलग-अलग भारांश):** शोध एवं नवाचार, रोजगारपरकता व आउटकम, वैश्विक सहभागिता, लर्निंग अनुभव और सततता।

मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- 54 विश्वविद्यालयों के साथ भारत विश्व में चौथे स्थान पर हैं। (2015 की रैंकिंग में 11 से बढ़ोतरी)
- **8 भारतीय विश्वविद्यालय** इस सूची में शामिल किए गए, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं।
- **6 भारतीय संस्थान** वैश्विक स्तर पर **शीर्ष 250 संस्थानों** में शामिल हैं।
- इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं।
- इसमें **12 IITs** शामिल हुए हैं, जिनमें **IIT दिल्ली 123वें** स्थान पर भारतीय संस्थानों में **सबसे ऊपर** है।

- इन मापदंडों को आगे **10 संकेतकों** में बांटा गया है, **'अंतर्राष्ट्रीय छात्र विविधता'** नामक **एक नया संकेतक** शामिल किया गया है।

रैंकिंग में सुधार क्यों हुआ है?

- **शैक्षणिक प्रदर्शन प्रतिष्ठा में सतत प्रगति,** प्रति फैकल्टी साइटेशन मानदंड में 8 भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।
- **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन।**
- **PM-USHA** जैसी पहलों के माध्यम से **अवसंरचना का विकास।**
- **पीएम इंटर्नशिप योजना, NATS 2.0 पोर्टल** जैसी पहलों के माध्यम से **रोजगार क्षमता में सुधार करना।**
- **मजबूत सततता और ज्ञान विनिमय प्रभाव।**
- **NEP 2020 के तहत** उच्च गुणवत्ता और समावेशन वाली उच्चतर शिक्षा में सुधार को बढ़ावा देना।

उच्चतर शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां

- **कम प्रत्यायन दर (Accreditation Rate):** उच्च लागत के कारण देश भर के 39% से भी कम विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त है।
- **कम GER:** वर्तमान GER 28.4% (2021-22) 2035 के 50% के लक्ष्य से बहुत दूर है।
- **अपर्याप्त अनुसंधान वित्त-पोषण:** अनुसंधान और विकास (R&D) पर सरकारी खर्च GDP का लगभग 0.7%है। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों (में कमजोर नवाचार परिणाम मिलते हैं।
- **उद्यमिता और नवाचार कौशल में कमी:** शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच संबंध न होने तथा सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद है।
- **अप्रचलित पाठ्यक्रम:** AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अपडेशन कम होता है।
- **खंडित विनियामक फ्रेमवर्क:** MERUs के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति का मुख्य कारण विविध विनियामक निकायों का मौजूद होना है।

आगे की राह

- **उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत बनाना।** (उदाहरण के लिए, TASK)
- **आवश्यकता-आधारित शिक्षा** को बढ़ावा देना। (उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की कौशल आधारित जनगणना)
- अंतर्विषयक डिग्रियों में निवेश को बढ़ाना चाहिए।
- **विनियामक समेकन (**राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित एकल विनियामक निकाय)।
- **संकाय को स्वायत्तता प्रदान करना।**
- **वित्त-पोषण में वृद्धि।**

6.4. मैनोस्फीयर (Manosphere)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यू.एन. वीमेन ने चेतावनी दी है कि **'मैनोस्फीयर'** के नाम से ज्ञात ऑनलाइन समुदायों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क लैंगिक समानता के समक्ष एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है।

मैनोस्फीयर क्या है?

- **परिभाषा: ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क, जो पुरुषत्व (Masculinity) की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा** देता है **और नारीवाद विरोधी विचारों** पर आधारित है।
  - इनकी सोच में पुरुष का मूल्य उसके भावनात्मक नियंत्रण, आर्थिक सामर्थ्य और महिलाओं पर नियंत्रण की क्षमता से आंका जाता है।
- **लक्ष्य:** 'मैनोस्फीयर' डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने, महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण सोच फैलाने और लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने के लिए करता है।

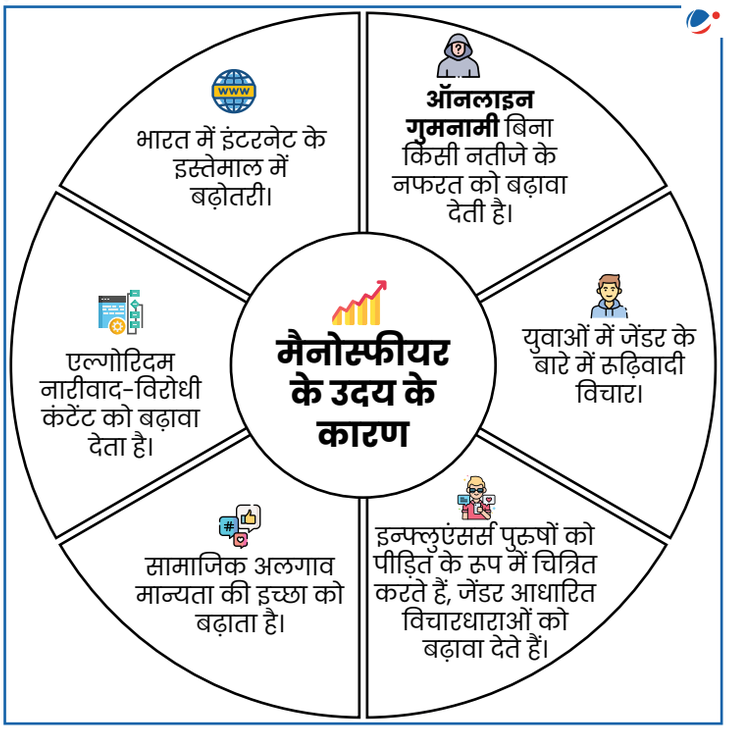

मैनोस्फीयर के नकारात्मक प्रभाव

- बढ़ता हुआ स्त्री द्वेष(Misogyny) और हिंसा का सामान्यीकरण (उदाहरण के लिए, *गेमरगेट*)।
- पुरुषों के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य में कमी, और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- लैंगिक समानता की प्रक्रिया को उलटना।
- महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा का जोखिम (16-58%)।

शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें**
  - बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995)

- 'मेकिंग ऑल स्पेसेस सेफ' पहल (UNFPA)
- EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट

- **भारत में आरंभ की गई पहलें**
  - स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
  - आई.टी. नियम, 2021
  - NCW की डिजिटल शक्ति पहल
  - सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 78 और 79

आगे की राह

- **कानूनी उपाय:** जैसे यूनाइटेड किंगडम का **ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम।** इस कानून के तहत साइट्स और ऐप्स को बच्चों एवं महिलाओं को उनके प्रति घृणा फैलाने वाले व अपमानजनक स्त्री-द्वेष कंटेंट सहित हानिकारक कंटेंट से भी बचाना होगा।
- **रोकथाम के रूप में शिक्षा:** मीडिया **साक्षरता को बढ़ावा देना** और उस पर शोध करना चाहिए। इसमें यह समझना शामिल है कि लोग अपनी ऑनलाइन दुनिया में कैसे नेविगेट करते हैं और संभावित हानिकारक कंटेंट के साथ उनकी अंतर्क्रिया कैसी होती है।
- **यूएन वीमेन द्वारा सुझाई गई अधिकार-आधारित प्रतिक्रिया:** इसमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार के **पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जुटाने** तथा डिजिटल लचीलापन बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **युवा-केंद्रित कार्यक्रम** जैसे कदम शामिल हैं।
- **मैनोस्फीयर-विरोधी कंटेंट निर्माताओं को बढ़ावा देना:** Reddit फ़ोरम और 'HeForShe' जैसे क्रिएटर्स मैनोस्फीयर छोड़ने वाले पुरुषों का समर्थन करते हैं।

6.5. सशस्त्र बलों में महिलाएं (WOMEN IN ARMED FORCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से महिला कैडेट्स का **पहला बैच** सफलतापूर्वक पास आउट हुआ। इनमें **17 महिला कैडेट्स** शामिल थीं।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने का महत्व

- **समानता के संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति:** यह कदम **अनुच्छेद 14**, **अनुच्छेद 15** और **अनुच्छेद 16** को बनाए रखता है। साथ ही, यह अधिक समावेशी रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- **सैन्य अभियानों को बल प्रदान करना:** यह टीम के प्रदर्शन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करना; महिलाओं द्वारा युद्ध और सहायक, दोनों ही भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। (उदाहरण के लिए, ऑपरेशन सिंदूर)
- **मानवीय भूमिका:** नागरिक मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

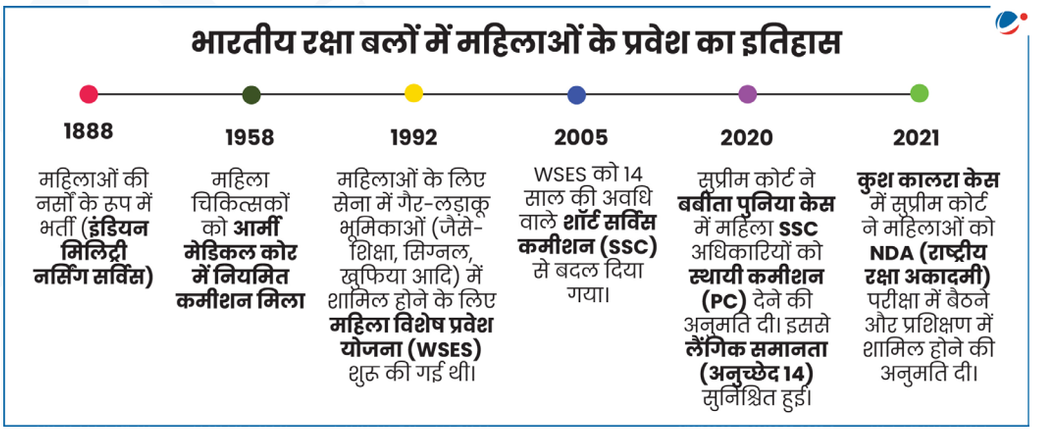

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **नीतिगत उपाय:** 11 सर्विसेज में स्थायी कमीशन (PC) प्रदान करना; अग्निवीर के रूप में महिलाओं को पुरुषों के समान प्रशिक्षण और चयन मानकों से गुजरना।
- **संरचनात्मक सुधार:** महिलाओं की पायलट के रूप में नियुक्ति (आर्मी एविएशन कोर्प्स); युद्धपोतों पर महिलाओं की तैनाती।
- **आउटरीच: IAF का 'दिशा'** सेल जागरूकता को बढ़ावा देता है।

चुनौतियां

- लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक सोच
- अवसंरचना की कमी
- अधिक शारीरिक श्रम की जरूरत और प्रशिक्षण की कमी
- सैन्य दायित्व और दैनिक घरेलू कार्यों के बीच संतुलन में कमी

निष्कर्ष

जैसे-जैसे युद्ध का स्वरूप बदल रहा है तथा शारीरिक बल की तुलना में प्रौद्योगिकी, इंटेलिजेंस और स्थिति के अनुसार ढलने की महत्ता बढ़ रही है, वैसे-वैसे भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता है।

6.6. वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 (Global Tobacco Epidemic 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025** पर दसवीं रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **WHO MPOWER उपाय:** 2007 से अब तक 155 देशों ने इसे लागू किया है, जिससे 6.1 बिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। MPOWER पहल के छह घटकों में शामिल हैं- निगरानी (Monitor), सुरक्षा (Protect), चेतावनी (Warning), मदद प्रस्ताव (Offer help), लागू करना (Enforce) और टैक्स दर बढ़ाना (Raise taxes)।
- **प्रगति:** ग्राफिक में स्वास्थ्य चेतावनी को दर्शाना सबसे अधिक व्यापक रूप से लागू; तंबाकू के प्रचार पर अंकुश लगाने में भारत दुनिया का पहला देश; डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को शामिल करना।
- **चुनौतियां: तंबाकू उत्पादों पर सबसे कम टैक्स अपनाया गया**; भारत में **प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में सिगरेट खरीदने की लागत 2014 से घटती जा रही है**, यानी सिगरेट खरीदना सस्ता होता गया है।
- **धूम्रपान से होने वाली मौतें:** तंबाकू जनित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष 7 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं।

तंबाकू के बारे में

- **प्रजातियाँ:** तंबाकू की **60 से अधिक प्रजातियां** पाई जाती हैं, जिनमें **एन. टैबेकम और एन. रस्टिका** बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। यह **दक्षिण अमेरिका** मूल का पौधा है।
- **जलवायु: 90-120 दिनों का पाला-रहित मौसम** आवश्यक होता है। औसत दैनिक तापमान **20-30°C** के बीच होना चाहिए और कटाई के समय **शुष्क मौसम** उपयुक्त होता है।
- **मृदा/वर्षा:** अच्छी तरह से हवादार, अच्छी जल-निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है; 500-1200 मिमी वर्षा उपयुक्त होती है।
- **उत्पादन:** भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक तथा निर्यातक देश है।
  - भारत में गुजरात 45% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है।
- तंबाकू बोर्ड (गुंटूर, आंध्र प्रदेश) तंबाकू उत्पादकों को समर्थन प्रदान करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है।

तम्बाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम

- **वैश्विक स्तर पर (MPOWER के अलावा):**
  - **WHO FCTC:** 80 से अधिक देशों ने अभिपुष्टि की है; भारत 2005 में पक्षकार बना।
  - **3 बाय 35 पहल (WHO):** वर्ष 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों को कम से कम 50% तक बढ़ाना।
- **भारत में कदम**
  - **COTPA, 2003:** सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध; नाबालिगों द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, आदि।
  - **पैकेजिंग नियम, 2022:** पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी से युक्त चित्रों को प्रदर्शित करने का प्रावधान।
  - **NTCP:** तंबाकू उत्पादों के उपयोग और आपूर्ति को कम करना।
  - **इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 कानून** लागू किया गया।

निष्कर्ष

मजबूत निगरानी प्रणाली लागू करना, **तंबाकू पर कर और कीमतों में वृद्धि करना,** कड़े कानून बनाना और उनका सख्ती से पालन कराना, जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करना तथा तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप का समाधान करना **तंबाकू महामारी से निपटने में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।**

6.7. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 (Global Gender Gap 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल **जेंडर गैप रिपोर्ट 2025** जारी की गई।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी।
- यह सूचकांक चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्रगति को मापता है; आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और राजनीतिक नेतृत्व।
- इस सूचकांक में 1 का स्कोर पूर्ण समानता (Parity) की स्थिति को, जबकि 0 का स्कोर पूर्ण असमानता (Inequality) की स्थिति को दर्शाता है।

भारत का समग्र प्रदर्शन (2025)

- **आर्थिक भागीदारी और अवसर:** प्रदर्शन में सुधार; आर्थिक भागीदारी 0.9% बढ़कर 40.7% हो गई।
- **शैक्षिक उपलब्धि:** भारत ने 97.1% अंक प्राप्त किए, जिससे महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में वृद्धि देखी गई।
- **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा:** जीवन प्रत्याशा में समग्र गिरावट के बावजूद, बेहतर लिंगानुपात और जीवन प्रत्याशा के कारण उच्च समानता।
- **राजनीतिक सशक्तीकरण: समानता में मामूली गिरावट (-0.6 अंक)** दर्ज की गई है। महिला सांसदों की संख्या 14.7% से घटकर 13.8% हो गई; महिला मंत्रियों की संख्या 6.5% से घटकर 5.6% हो गई।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत:** भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में यह 129वें स्थान पर था। हालांकि, भारत का स्कोर सुधरकर 0.644 (2025) हो गया।
- **दक्षिण एशिया:** सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बांग्लादेश, जो वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया। नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें और भूटान 119वें स्थान पर हैं, जो भारत से बेहतर हैं।
- **वैश्विक:** आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर है, अभी भी औसत 30% से अधिक का संयुक्त जेंडर गैप मौजूद है; पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे।

लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

- **सामाजिक:**
  - महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, जो पुरुषों की 82.14% से कम है।
  - बाल विवाह के 23.3% मामले सामने आए; बढ़ती महिला आत्महत्याएं; 2019 से 2021 के बीच तीन वर्षों में देश में 13.13 लाख से अधिक महिलाएं लापता हुईं।
  - पितृसत्तात्मक मानदंड, जातिगत असमानताएं, डिजिटल डिवाइड – भारत में केवल 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं।(NFHS-5)
- **आर्थिक:** महिलाओं द्वारा किया गया **अवैतनिक देखभाल-कार्य GDP का 3.1%** है; लगभग **97% महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्रों** में कार्यरत हैं।
  - **एनीमिया की व्यापकता:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग 57% भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनकी सीखने, कार्य करने या सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है।
  - **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** 2018-20 में यह 97 था, जबकि WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 70 से कम करने का है।
  - **प्रजनन स्वास्थ्य:** भारत में लगभग 50 मिलियन महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** राजनीतिक भागीदारी में गिरावट।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम
- पोषण अभियान
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- वन स्टॉप सेंटर (OSC)
- महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण

निष्कर्ष

महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना, नेतृत्व के अवसरों को मजबूत करना, कौशल प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति में रूपांतरण को बेहतर बनाना, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और वैश्विक व्यापार में समावेशी परिणाम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लैंगिक समानता में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

6.8.1. WHO की सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट (WHO REPORT ON SOCIAL CONNECTION)

WHO रिपोर्ट: 'अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक'

- यह रिपोर्ट **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन** ने जारी की है। यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य, और समाज पर सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव** पर प्रकाश डालती है।

परिभाषा

- **सामाजिक जुड़ाव:** परिवार, मित्र, सहपाठी और सहकर्मी आदि से जुड़ना और आपस में संबंध स्थापित करना।
- **सामाजिक विलगाव:** इसमें **अकेलेपन** (किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर) और **सामाजिक अलगाव** (कम या बहुत कम मिलते-जुलते रिश्ते)।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- प्रत्येक 6 में से 1 व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। इनमें युवा (13-29 वर्ष) सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं।
- **प्रत्येक 3 में से 1 वृद्ध वयस्क** तथा प्रत्येक **4 में से 1 किशोर** सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति में है।
- लगभग **871,000 मौतें** अकेलेपन से हुई थीं; **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव; खराब** शैक्षणिक प्रदर्शन और उत्पादकता की हानि शामिल हैं।

6.8.2. परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (PGI) 2.0 {PERFORMANCE GRADE INDEX (PGI) 2.0}

PGI के बारे में

- **उत्पत्ति:** PGI की **शुरुआत 2017** में की गई, और बाद में इसे **2021 में PGI 2.0 के रूप में नया स्वरूप** दिया गया।
- **जारीकर्ता:** शिक्षा मंत्रालय
- **डेटा के स्रोत:** UDISE+, नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS), पी.एम.-पोषण पोर्टल, प्रबंध/PRABAND पोर्टल और विद्यांजली पोर्टल।
- इसमें कुल 1000 अंकों का भारांक होता है, जिन्हें 73 संकेतकों (indicators) को 6 क्षेत्रों (डोमेन) में बाँटा गया है।

इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष चार ग्रेड (दक्ष, उत्कर्ष, अति-उत्तम व उत्तम) प्राप्त नहीं** कर सका।
- **शीर्ष प्रदर्शन** में केवल **चंडीगढ़ ने प्रचेस्टा-1 (Prachesta-1)** ग्रेड हासिल किया; **सबसे कमजोर प्रदर्शन में मेघालय (आकांक्षी-3/ Akanshi-3)** है।
- **समग्र रुझान:**
  - **24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** के स्कोर **बेहतर** रहे हैं, जबकि **12** में **गिरावट** दर्ज की गई है।
  - **अंतरराज्यीय असमानता में कमी आई है।**

6.8.3. UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2025 (STATE OF WORLD POPULATION REPORT 2025)

रिपोर्ट के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने *'द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस'* से अपनी विश्व जनसंख्या की स्थिति (SWP), 2025 रिपोर्ट जारी की है, जो रिप्रोडक्टिव एजेंसी संकट को वास्तविक वैश्विक प्रजनन चुनौती के रूप में रेखांकित करती है।
- यह रिपोर्ट कई अधूरी प्रजनन इच्छाओं को भी उजागर करती है, जैसे कि अनचाहा गर्भधारण आदि।
- यह रिपोर्ट **लोगों के अधिकार-आधारित, विकल्पों को प्राथमिकता** देने के लिए जनसंख्या से संबंधित नीतियों में बदलाव का समर्थन करती है, जिससे लोगों को वैसा परिवार बनाने के लिए सक्षम किया जाए जैसा वे चाहते हैं।

6.8.4. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट, 2024 (Global Education Monitoring 2024 Report)

यूनेस्को के 'एजुकेशन 2030 इंचियोन डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' के तहत यह रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। यह रिपोर्ट SDG-4 और अन्य SDGs की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए जारी की जाती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कम और मध्य-आय वाले देशों में कम से कम 75% चरम मौसमी घटनाओं के दौरान स्कूल बंद रहे थे। इससे 5 मिलियन या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए थे।
- **भारत में किया गया एक अध्ययन:** वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण नए शब्द सीखने से गणित एवं गैर-संज्ञानात्मक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- प्राथमिक स्तर के बच्चों की स्कूल न जाने की दर में तेजी से सुधार, निम्न माध्यमिक स्तर के स्कूलों में धीमी प्रगति और लैंगिक अंतराल।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका में इतना महत्त्व नहीं दिया गया है; **SDG-4** को 72 जलवायु पहलों में से **केवल 2 में ही शामिल** किया गया है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें: जलवायु परिवर्तन संबंधी शिक्षा, शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सहायता, शिक्षा संबंधी अवसंरचना को जलवायु-अनुकूल बनाना, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा में निवेश करना और विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए।

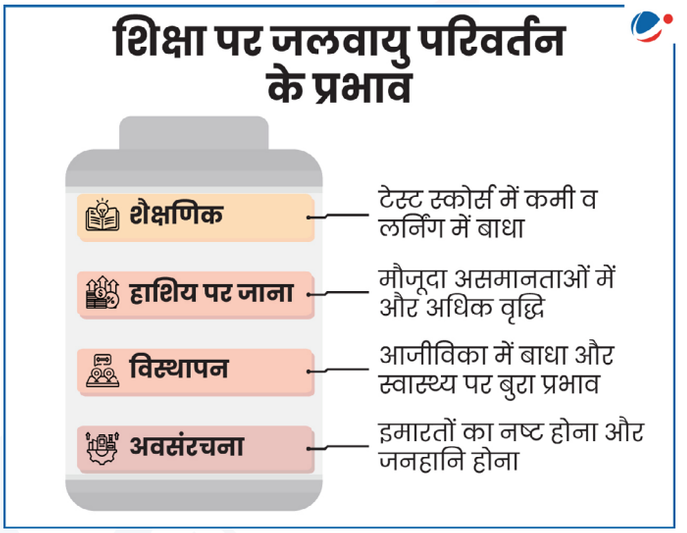

6.8.5. जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल (Gender Budgeting Knowledge Hub Portal)

पोर्टल लॉन्च: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान **'जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल** लॉन्च किया।

जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल के बारे में

- यह एक **केंद्रीकृत पोर्टल** है। इस पर कई तरह की उपयोगी सामग्री जैसे **पॉलिसी ब्रीफिंग, सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं, जेंडर-आधारित आंकड़े** आदि उपलब्ध हैं।
- इसका उपयोग **केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों** और अन्य हितधारकों द्वारा किया जा सकता है।
- इसमें जेंडर बजटिंग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।

जेंडर बजटिंग (GB) क्या है?

- योजना और बजट में लैंगिक समानता को एकीकृत किया गया है।
- जेंडर बजटिंग में महिलाओं/ पुरुषों पर प्रभाव, प्राथमिकता और बजट आवंटन का गहन विश्लेषण किया जाता है।

भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता: जेंडर-संवेदनशील नीतियां, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सहभागी बजटिंग और कानूनी ढांचे को मजबूत करने को सुनिश्चित करता है।

जेंडर बजटिंग की टाइमलाइन

- **2005-06: भारत सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग अपनाना**
- **2008-09: सरकार द्वारा चाइल्ड बजटिंग अपनाना**
- **2024-25: GBS की समीक्षा**

7.1. एक्सिओम-4 मिशन (AXIOM-4 MISSION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक्सिओम-4 मिशन के सदस्य 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए।

एक्सिओम-4 (एक्स-4) मिशन के बारे में

- यह **एक्सिओम स्पेस द्वारा NASA और SpaceX के सहयोग से ISS (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** है।
- यह **14-दिन** का मिशन था, जिसे NASA के **कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए फाल्कन 9 रॉकेट** से लॉन्च किया गया था।
  - **फाल्कन 9** एक पुन: प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल है और **ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट** अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पुन: प्रयोज्य क्रू मॉड्यूल है।
- **अंतरिक्ष यात्री:** शुभांशु शुक्ला (भारत), पेगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोस्ज़ उज़्नांस्की (पोलैंड), और टिबोर कापू (हंगरी)।
  - शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं और राकेश शर्मा (1984) के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं।
- **उद्देश्य: भारत, पोलैंड और हंगरी** के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी को साकार करना।
- **इसरो (ISRO) के नेतृत्व वाले अध्ययनों में शामिल हैं:** अंतरिक्ष में फ़सल उगाना, जीवन समर्थन के लिए साइनोबैक्टीरिया, भोजन/ ईंधन के रूप में अंतरिक्ष माइक्रोएल्गी, मायोजेनेसिस और मांसपेशियों का नुकसान, टार्डिग्रेड्स का लचीलापन, और स्क्रीन के उपयोग का संज्ञानात्मक प्रभाव; STEM आउटरीच, आदि।

भारत के लिए इसका महत्त्व

- यह गगनयान मिशन का समर्थन करता है (शुक्ला चार चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं)।
- यह वैश्विक साझेदारी और अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा देता है।
- यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- यह STEM क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित करता है।

चुनौतियां

- **तकनीकी:** जीवन समर्थन प्रणाली, विकिरण से बचाव, पुनः प्रवेश के दौरान सुरक्षा और लॉन्च सुरक्षा।
- **लॉजिस्टिक:** उच्च लागत और कठोर अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण की आवश्यकताएं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में

- यह पृथ्वी की निचली कक्षा (370-460 किमी) में स्थित एक **रहने योग्य उपग्रह** है, जो लगभग 28,000 किमी/घंटा की गति से **हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर** लगाता है।
- **साझेदार:** NASA (अमेरिका), Roscosmos (रूस), ESA (यूरोप), JAXA (जापान), और CSA (कनाडा)।
- यह **सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला** है, जो पृथ्वी की 90% आबादी वाले हिस्से को कवर करती है।
- इसे पहली बार **1998** में लॉन्च किया गया था और यह कम-से-कम **2030** तक चालू रहेगा।

गगनयान कार्यक्रम के बारे में

- यह भारत का **पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन** है, जिसे **2018** में मंज़ूरी मिली थी।
- **उद्देश्य:** एक क्रू को लॉन्च करके **मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता** का प्रदर्शन करना।
- **घटक:** LVM-3 लॉन्च व्हीकल, ऑर्बिटल मॉड्यूल (क्रू + सर्विस मॉड्यूल)।
- इसका विस्तार करके इसमें **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन** को भी शामिल किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के बारे में

- यह पांच मॉड्यूल वाला एक **प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है** (400-450 किमी की ऊंचाई पर)।
- बेस मॉड्यूल को **2028** में लॉन्च करने की योजना है, और पूरा स्टेशन **2035** तक चालू हो जाएगा।

निष्कर्ष

प्रस्तावित गगनयान मिशन से पहले तकनीक सीखने की प्रक्रिया को गति मिलेगी और भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों के लिए महत्त्वपूर्ण मानव पूंजी और बुनियादी ढाँचा भी तैयार होगा।

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

7.2.1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल {Science And Technology (S&T) Clusters Initiatives}

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025" में **Kalaanubhav.in** सहित विविध पहलों को रेखांकित किया गया।

'विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल' के बारे में

- **शुरुआत:** 2020 में **"PM-STIAC"** की सिफारिशों के आधार पर।
- **उद्देश्य:** विविध हितधारकों को एक साथ लाना, ताकि **नवाचारी विचारों के माध्यम से मांग-आधारित समाधान** प्रदान किए जा सकें।
- **कार्यप्रणाली:**
  - **परिचालन:** कंसोर्टियम-आधारित अप्रोच।
  - **फोकस:** यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर विविध क्षेत्रकों की समस्या के समाधान पर केंद्रित है।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय।
  - PSA **कैबिनेट सचिव के तहत** कार्य करता है।

7.2.2. क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स (Critical And Emerging Technologies Index)

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स का अनावरण किया गया है। यह सूचकांक **25 देशों** के **पांच प्रौद्योगिकी क्षेत्रों** यथा- **AI, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष और क्वांटम** में प्रदर्शन का आकलन करता है।

- इसे **हार्वर्ड कैनेडी स्कूल** ने प्रकाशित किया है।
- इसमें **6 मापदंडों** के आधार पर प्रत्येक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहचान की गई है: **भू-राजनीतिक महत्त्व, प्रणालीगत प्रभाव, GDP में योगदान, दोहरे उपयोग की क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, और परिपक्व होने में लगने वाला समय।**

प्रमुख निष्कर्ष

- **भारत** इन तकनीकी क्षेत्रों में **शीर्ष तीन (अमेरिका, चीन और यूरोप)** की तुलना में **काफी पीछे** है।
- भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से **सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी** में पिछड़ा हुआ है।

7.2.3. क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित कम्युनिकेशन में सफलता प्राप्त हुई (Quantum Entanglement-Based Communication Achieved)

DRDO और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री-स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई।

- **फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन** प्रदर्शन किया गया।
- **इसरो ने 2021** में प्रदर्शन किया था।

प्रयोग के बारे में

- यह DRDO के **'फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के लिए फोटॉनिक तकनीकों के डिजाइन और विकास'** प्रोजेक्ट का हिस्सा था।
- इस प्रयोग में **क्वांटम बिट त्रुटि दर (QBER) 7% से भी कम** रही।
  - QBER यह दर्शाता है कि भेजी गई और प्राप्त जानकारी में कितना अंतर है यानी जानकारी को कोई तीसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से तो प्राप्त नहीं कर रहा है।
- यह **क्वांटम साइबर सुरक्षा, लंबी दूरी की QKD और भविष्य के क्वांटम इंटरनेट में रियल टाइम अनुप्रयोगों** के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

एंटेंगलमेंट-आधारित QKD के लाभ

- **कार्यक्षमता:** यह **सुरक्षित तरीके से कुंजी (key) साझा** करने में सक्षम है, **भले ही डिवाइस पूरी तरह सुरक्षित हो न हो।**
- **जासूसी का पता लगाना:** अवरोधन से **क्वांटम अवस्था** बदल जाती है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि जासूसी हो रही है।
- **फ्री-स्पेस QKD:** इस तकनीक में **महंगे फाइबर-ऑप्टिक केबल** की जरूरत नहीं होती। इसलिए, यह **पहाड़ी इलाकों या घनी आबादी वाले शहरों** में भी आसानी से काम कर सकती है।

QKD क्या है?

- **संचार प्रौद्योगिकी:** यह एक **क्वांटम संचार तकनीक** है, जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात् **क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्रिप्टोग्राफी** पर आधारित है।
  - **क्वांटम मैकेनिक्स** विज्ञान की एक नई शाखा है जो यह बताती है कि अत्यंत **सूक्ष्म कण एक ही समय में कण और तरंग (एक हलचल या भिन्नता जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है) दोनों जैसा व्यवहार** करते हैं।
    - भौतिक विज्ञानी इसे **"वेव-पार्टिकल डुअलिटी यानी तरंग-कण द्वैत"** कहते हैं।
- **मुख्य सिद्धांत:**
  - **क्वांटम एंटेंगलमेंट:** इस प्रक्रिया में, कई क्वांटम कण एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
  - **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:** एक ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक है, जो डेटा को इतनी सुरक्षा देती है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता।

7.2.4. फाइबर ऑप्टिक ड्रोन (Fiber Optic Drones)

हाल ही में, **रूस-यूक्रेन संघर्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW)** के प्रति प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग किया गया।

फाइबर ऑप्टिक्स फर्स्ट-पर्सन-व्यू (FPV) ड्रोन्स के बारे में

- ये **नेविगेशन** के लिए **रेडियो वेव्स** की बजाय **फाइबर ऑप्टिक तकनीक (20 कि.मी. तक)** का उपयोग करते हैं।
  - **फाइबर ऑप्टिक्स में** बहुत **पतले कांच या प्लास्टिक के** तार का उपयोग होता है।
  - वे **तेज गति, लंबी दूरी और समकालिक संचार** को सक्षम कर सकते हैं।
  - वायर्ड केबल के विपरीत, **फाइबर केबल एक समय में एक ही आवृत्ति पर केवल एक ही संचार** को सक्षम करती है।
  - **रेडियो लिंक न होने** का अर्थ है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) प्रणालियों द्वारा **जाम या इंटरसेप्ट नहीं** किया जा सकता।

फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन्स के अन्य उपयोग

- **लाइव प्रसारण:** मीडिया इवेंट्स के लिए HD और कम विलंबता वाले वीडियो का सीधा प्रसारण।
- **औद्योगिक निरीक्षण:** बिजली संयंत्रों जैसे जटिल प्रतिष्ठानों में डेटा संग्रह।
- **पर्यावरण निगरानी:** दूरस्थ या दुर्गम इलाकों में भी विश्वसनीय संचालन।
- **विश्वसनीय डेटा हस्तांतरण:** घने शहरी या जंगली इलाकों में भी उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले वास्तविक समय के वीडियो का प्रसारण।

7.2.5. डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address: DHRUVA)

डाक विभाग ने DHRUVA का **सम्पूर्ण फ्रेमवर्क बताने वाला एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज** जारी किया है। **DHRUVA** राष्ट्रीय स्तर की **डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** है।

DHRUVA के बारे में

- DHRUVA को **भारत के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट डिजिटल एड्रेस** प्रदान करने के लिए **डाक विभाग द्वारा विकसित** किया जा रहा है। इसमें यूजर्स **जियो-कोडेड फ्रेमवर्क** का उपयोग करेंगे।
- **उद्देश्य:** प्रभावी शासन, समावेशी तरीके से सेवा वितरण और यूजर्स को बेहतर सेवा अनुभव के लिए एड्रेस की जानकारी के प्रबंधन को **मूलभूत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** का दर्जा देना।
- **एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS)** को सक्षम करता है।
- **दो प्रमुख लेयर्स हैं:**
  - **DIGIPIN:** 4x4 मीटर के समान ग्रिड पर **10-अंकीय अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड** है।
    - DIGIPIN **भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा** के आधार पर स्थानों की सटीक तरीके से पहचान करता है।
  - **डिजिटल एड्रेस लेयर:** सहमति-आधारित प्रणाली है। उपयोगकर्ता-अनुकूल एड्रेस लेबल।
- **मुख्य विशेषताएं:** गोपनीयता, खुलापन, मापनीयता, पारदर्शिता, नवाचार, आदि।

7.2.6. तियानवेन-2 प्रोब (TIANWEN-2 PROBE)

इसे **चीन** ने मंगल ग्रह के निकट एक क्षुद्रग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए **प्रक्षेपित** किया है।

- **तियानवेन-1 प्रोब 2021** में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।
- **तियानवेन-3** का प्रक्षेपण 2028 के आस-पास होना है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर लाना है।
- **तियानवेन-4 का लक्ष्य** 2030 के आस-पास **बृहस्पति ग्रह का** अन्वेषण करना है।

तियानवेन-2 प्रोब के बारे में

- **प्रक्षेपण यान:** लॉन्ग मार्च 3-B रॉकेट।
- **उद्देश्य: क्षुद्रग्रह 2016HO3** से सैंपल एकत्र करना तथा **मेन बेल्ट में मौजूद धूमकेतु 311P का अन्वेषण करना,** जो मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से और अधिक दूर स्थित है।

7.2.7. भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ तैयार की गई (INDIA'S FIRST GENE-EDITED SHEEP PRODUCED)

CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके **कश्मीर विश्वविद्यालय ने ICAR के सहयोग से भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़** तैयार की।

CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में

- यह **DNA स्ट्रैंड्स के लिए कट-एंड-पेस्ट विधि** पर कार्य करती है।
- **2020 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार।**

शोध के बारे में

- एक **मेमने में मायोस्टेटिन जीन को एडिट** किया गया, जिससे **मांसपेशियों की वृद्धि में 30% की बढ़ोतरी** हुई।
- इस प्रक्रिया में **किसी बाहरी DNA को प्रवेश नहीं** कराया गया। इस तरह यह कोई **ट्रांसजेनिक जानवर नहीं** है। इस प्रकार, यह **पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित** बनाती है।
- **NDRI ने एक जीन-एडिटेड भैंस का भ्रूण विकसित** किया था।

जानवरों में जीन एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएं

- **"डिजाइनर बेबी"** के निर्माण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे **असमानता और बढ़** सकती है।
- **जोखिम:** यूजीनिक्स, ऑफ-टारगेट प्रभाव, मोज़ेइकिज़्म और जानवरों के कल्याण से जुड़ी चिंताएं।

गौरतलब है कि **यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बायो-एथिक्स समिति** जीनोम एडिटिंग के नैतिक प्रभावों की पड़ताल कर रही है।

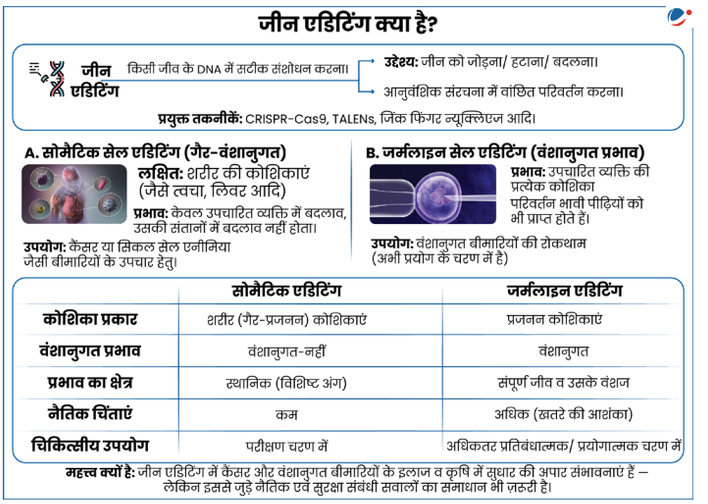

7.2.8. HIV की रोकथाम के लिए नई दवा को मंजूरी (HIV PREVENTION DRUG APPROVED)

US-FDA ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा **लेनाकैपाविर** को मंजूरी प्रदान की।

- मंजूरी से अब यह दवा **WHO प्रीक्वालिफिकेशन के लिए पात्र** हो गई है। इससे **अलग-अलग देशों में इसे जल्दी स्वीकृति** मिल सकती है।
- **WHO प्रीक्वालिफिकेशन ऑफ़ मेडिसिन्स प्रोग्राम (PQP)** यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा खरीद एजेंसियां जो दवाएं सप्लाई करती हैं, वे **गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के स्वीकार्य मानकों** को पूरा करती हैं।

लेनाकैपाविर के बारे में

- लेनाकैपाविर एक **एंटीरेट्रोवायरल दवा** है। इसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए **प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP)** के रूप में किया जाता है। यह उन **HIV नेगेटिव व्यक्तियों में HIV संक्रमण के जोखिम को कम** कर सकती है, जिन्हें वायरस से संक्रमित होने का खतरा है।
- WHO वर्तमान में **ओरल PrEP, डैपिविरिन वैजाइनल रिंग, और लॉन्ग-एक्टिंग इंजेक्टेबल कैबोटिग्रैविर (CAB-LA)** की सिफारिश करता है।

HIV के बारे में

- **HIV** CD4 कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
- **प्रसार:** रक्त, स्तन का दूध, सीमन और योनि स्राव से फैलता है।
  - यह माता से बच्चे में भी फैल सकता है।
- **उपचार: एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से रोका** जा सकता है।
  - बिना इलाज के HIV आगे चलकर **AIDS** में बदल सकता है।
- भारत में **2.5 मिलियन से अधिक लोग** HIV संक्रमण से पीड़ित हैं।

भारत की पहलें

- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-V (2021-26):** इसका लक्ष्य नए संक्रमणों में 80% की कमी लाना है।
- **HIV और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017:** यह अधिनियम HIV-पॉजिटिव लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है।
- भारत ने **2030 तक HIV/ एड्स को लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त** करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत के शैक्षणिक संस्थानों में **रेड रिबन क्लब** जैसी युवा-केंद्रित पहलें भी चलाई जा रही हैं।

7.2.9. वजन कम करने वाली दवाएं (WEIGHT LOSS DRUG)

डेनमार्क की दवा कंपनी **नोवो नोर्डिस्क** ने भारत में अपनी वजन कम करने वाली दवा **वेगोवी** लॉन्च की।

- इस दवा का सक्रिय घटक **सेमाग्लूटाइड** है और इसे **वेगोवी** ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। यह इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी और इसे सप्ताह में एक बार लेना होगा।
  - **सेमाग्लूटाइड** भूख को कम करने का काम करता है। यह शरीर में मौजूद **GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1)** नामक हार्मोन की कॉपी करता है।
    - **GLP-1** आंतों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो खाना खाने के बाद शरीर में रिलीज़ होता है और व्यक्ति को अधिक देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है।
- वजन घटाने की अन्य दवाओं में **माउंजारो** भी शामिल है, जो **टिर्जेपटाइड** से बनी है। यह GLP-1 और GIP दोनों हार्मोन की तरह काम करता है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
2026 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त
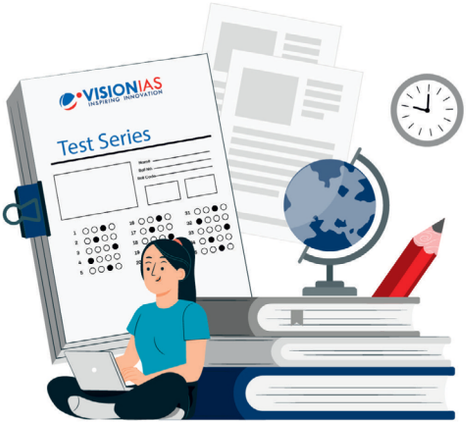

8.1. आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि (INS KAUNDINYA AND TANKAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय नौसेना द्वारा औपचारिक रूप से **प्राचीन टंकाई वाले जहाज** को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम **INSV कौंडिन्य** रखा गया है, जिसे **टंकाई पद्धति** का उपयोग करके बनाया गया था।

INS कौंडिन्य के बारे में

- यह **अजंता की गुफाओं के चित्रों** में दर्शाए गए **5वीं शताब्दी** के जहाज पर आधारित है।
- यह परियोजना **संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होदी इनोवेशन्स** के बीच **त्रिपक्षीय समझौते** के जरिए शुरू की गई थी।

टंकाई विधि के बारे में

- यह जहाज निर्माण की **2000 वर्ष पुरानी** तकनीक है, जिसे **'टंकाई जहाज निर्माण विधि'** के नाम से जाना जाता है।
- इसमें **कीलों का उपयोग करने की बजाय लकड़ी के तख्तों को जोड़ने** के लिए सिलाई विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक लचीलापन एवं स्थायित्व मिलता है।

भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत

व्यापार और वाणिज्य	**मेसोपोटामिया** में हड़प्पाकालीन मुहरों की खोज तथा **लोथल** में जहाजों की खोज प्राचीन समुद्री व्यापार संबंधों को दर्शाती हैं। **ऋग्वेद** में विदेशों से समुद्र पार व्यापार का उल्लेख मिलता है। **चोल, चेर व पांड्य शासकों ने रोमन साम्राज्य** के साथ समृद्ध समुद्री व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। **विजयनगर और बहमनी साम्राज्य** गोवा बंदरगाह का उपयोग करके **ईरान एवं इराक से घोड़ों का आयात** करते थे।
सांस्कृतिक प्रसार	अशोक के पुत्र **महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सीलोन तक समुद्री यात्रा** पर गए थे। **भारतीय धर्म, स्थापत्य कला एवं भाषाओं का प्रसार** हुआ था। उदाहरण के लिए- **जावा में बोरोबुदुर मंदिर, कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर आदि।**
नौसैन्य कौशल और समुद्री ज्ञान	**मगध साम्राज्य की नौसेना** को पांडुलिपियों में दर्ज विश्व की पहली नौसेना माना जाता है और **चाणक्य के अर्थशास्त्र में नौसैनिक युद्ध विभाग** का उल्लेख भी मिलता है। राजेंद्र चोल-I ने श्रीलंका और श्री विजय साम्राज्य तक सफल नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। **छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग** जैसे तटीय किलों का निर्माण कराया था।
समुद्री कूटनीति	**श्रीलंका** के शासक **मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर** बनाने की अनुमति के लिए **समुद्रगुप्त** के पास एक दूत मंडल भेजा था। **शैलेन्द्र शासक** ने **पाल शासकों** के दरबार में दूतमंडल भेजा था और नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी।

समुद्री विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकारी पहलें

- **लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर:** यह पहल देश की ऐतिहासिक समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए है।
- **प्रोजेक्ट मौसम:** इसका उद्देश्य समुद्री अंतर्क्रियाओं के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाना है।
- **सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य वैश्विक समुद्री क्षेत्रक में भारत की उत्कृष्ट स्थिति को पुनर्जीवित करना और बहाल करना है।

अजंता की अन्य प्रसिद्ध चित्रकारियां

- अलग-अलग **बोधिसत्वों** के चित्र: **वज्रपाणि (बुद्ध की शक्ति का प्रतीक), मंजुश्री (बुद्ध की बुद्धिमत्ता का प्रतीक) और पद्मपाणि (बुद्ध की करुणा का प्रतीक)।**
- **चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय** द्वारा फ़ारसी राजदूत का स्वागत करने का चित्र।
- **शिबी जातक** (राजा शिबी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर से मांस का टुकड़ा अर्पित किया था), **मातृपोषक जातक** (हाथी द्वारा बचाया गया एक कृतघ्न व्यक्ति उसके रहने के स्थान का खुलासा करता है) का चित्रण आदि।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

8.2.1. प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 {EMBLEMS AND NAMES (PREVENTION OF IMPROPER USE) ACT, 1950}

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **'प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950'** के तहत **एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का सम्मान करने के संबंध में दायर एक याचिका खारिज** कर दी।

प्रतीक अधिनियम (Emblems Act) के बारे में:

- **उद्देश्य:** व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों या ट्रेडमार्क या पेटेंट के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना **राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के नाम या सचित्र प्रस्तुति के अनुचित उपयोग** को रोकना है।
- **प्रतीक की परिभाषा**: "प्रतीक" का अर्थ है ऐसा कोई भी **प्रतीक, मुहर, ध्वज, चिन्ह, कोट-ऑफ-आर्म्स (राज्य चिह्न) या चित्रात्मक प्रस्तुति, जो इस अधिनियम में उल्लेखित** हो।
- **लागू होना**: यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। साथ ही, यह **भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर भी लागू** होता है।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत संरक्षण

नाम	विवरण
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	संयुक्त राष्ट्र (UN), WHO, FIFA, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)
धार्मिक संगठन	रामकृष्ण मिशन, साईं बाबा ट्रस्ट
महत्वपूर्ण संस्थान एवं इमारतें	संसद व राज्य विधान-मंडल जैसे भवन
राष्ट्रीय प्रतीक	पदक, आदि
सरकारी प्रतीक	नाम, मुहरें, प्रतीक चिन्ह, राजकीय चिन्ह
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व	महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराजा, भारत का प्रधान मंत्री; शब्द: "गांधी", "नेहरू" व "शिवाजी"

8.2.2. कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोवलाई माणिक्का मालाई (KUMBAKONAM VETRILAI AND THOVALAI MAANIKKA MAALAI)

कुंभकोणम वेत्रिलाई को भारत सरकार द्वारा **भौगोलिक संकेत (GI) टैग** दिया गया है, जो इसकी क्षेत्रीय विशेषता और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है।

कुंभकोणम वेत्रिलाई के बारे में

- यह एक **पान (pan) का पत्ता** होता है।
- यह मुख्य रूप से तंजावुर के उपजाऊ **कावेरी नदी बेसिन** में उगाया जाता है।
- इनमें **चेविकोल** नामक तत्व पाया जाता है, जो अपनी उच्च **एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी विशेषताओं** के लिए जाना जाता है।

थोवलई माणिक्का मालाई के बारे में

- यह एक खास तरह की माला है, जो केवल **थोवलई** में बनाई जाती है।
- इसमें **फूलों को सावधानी से मोड़ा** जाता है और उन्हें सटीक **ज्यामितीय** (geometrical) पैटर्न में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे **रत्नों (खासकर माणिक/रूबी)** जैसे दिखें।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के बारे में

- GI एक ऐसा चिह्न है, जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है। साथ ही, इन उत्पादों की अपनी उत्पत्ति के कारण **गुण या प्रतिष्ठा** भी होती है।
- यह **वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत विनियमित है।
- इसे **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स/TRIPS) समझौते** के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)** के रूप में मान्यता दी गई है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** GIs प्रदान करता है।
- GI टैग का पंजीकरण **10 वर्षों** के लिए होगा। **(इसे नवीनीकृत भी किया जा सकता है)**
- सबसे अधिक GI टैग **उत्तर प्रदेश** के पास हैं।

8.2.3. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship: WTC)

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका ने **विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25)** में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीत लिया है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के बारे में

- **शुरुआत:** WTC की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी।
- **पात्रता:** ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में **शीर्ष नौ रैंक वाली टीमें** WTC के लिए क्वालीफाई करती हैं।
- **फॉर्मेट:** प्रत्येक टीम **तीन घरेलू और तीन बाहरी श्रृंखलाएं** खेलती है।
  - **द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला** का प्रत्येक **मैच दो साल के चक्र** में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में अंकों का **योगदान** करता है।
  - प्रत्येक टीम **कम-से-कम 2 टेस्ट** और **अधिकतम 5 टेस्ट** की 6 श्रृंखलाएँ खेलती है।
  - शीर्ष दो टीमें (**पॉइंट प्रतिशत प्रणाली के अनुसार, न कि जीते गए मैचों के आधार पर**) विजेता बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती हैं।

9.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य (VALUES OF MAHATMA GANDHI AND SREE NARAYANA GURU)

परिचय

श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में **श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी** के बीच **1925** में हुए ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी मनाई गई, जो केरल यात्रा के दौरान **केरल के शिवगिरी मठ** में आयोजित हुआ था। यह संवाद **वायकोम सत्याग्रह**, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, दमितों के उत्थान, आदि विषयों पर केंद्रित था।

श्री नारायण गुरु के बारे में (1856-1928)

- उनका जन्म **केरल के चेंबाज़ंती गाँव में** हुआ था।
- उन्होंने हाशिए पर पड़े अन्य समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP)** की स्थापना की।
- उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने **अरुविप्पुरम में एक शिवलिंग की प्रतिस्थापना** की थी।

विभिन्न पहलुओं पर श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के विचार

पहलू	श्री नारायण गुरु	महात्मा गांधी
सामाजिक सुधार	उन्होंने जाति को अप्राकृतिक मानकर उसका विरोध किया और इस प्रकार, उन्होंने "एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर" का उद्घोष किया। उन्होंने धीमी, शिक्षाप्रद प्रक्रिया को अपनाने की वकालत करते हुए जाति उन्मूलन का आग्रह किया।	गांधीजी अस्पृश्यता के विरोधी थे। फिर भी, वे वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करते थे।उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्णों (लोगों के वर्ग) को स्वाभाविक रूप से व्यवसायों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
धार्मिक विचार	उनका मानना था कि सभी धर्म आध्यात्मिक विकास के लिए मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं।	गांधीजी ने सभी धर्मों को सत्य तक पहुंचने के समान मार्ग माना और उन्होंने ऐसी राजनीति का विरोध किया जो धर्म, आध्यात्मिक मूल्यों से अलग हो।
मंदिरों में प्रवेश एवं सामाजिक समानता	उन्होंने सभी जातियों के लिए **मंदिरों के द्वार खोलने** का कार्य किया।	**उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलनों** और दमितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।
शिक्षा	उन्होंने शिक्षा को मानवीय प्रगति और समृद्धि का एकमात्र साधन माना। साथ ही, सभी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और महिलाओं को समान अवसर देने की वकालत की।	उन्होंने **नई तालीम** की वकालत की, जिसमें शारीरिक श्रम और कारीगरी को बौद्धिक विकास के साथ जोड़ा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया और अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा में शिक्षा को अधिक उपयुक्त माना।

9.2. एकात्म मानववाद (INTEGRAL HUMANISM)

परिचय

1960 के दशक में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के समग्र विकास के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे **एकात्म मानववाद** कहा गया, जिसने मानवीय गरिमा, सद्भाव और एकजुटता के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया।

एकात्म मानववाद दर्शन के बारे में

- 1960 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित इस दर्शन का **लक्ष्य** व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।

- **एकात्म मानववाद** आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं **के पुरुषार्थ की अवधारणा में** निहित है। ये **धर्म** (धार्मिकता), **अर्थ** (धन/ समृद्धि), **काम** (सुख/ इच्छा) और **मोक्ष** (मुक्ति) को केंद्र में रखते है।
- यह पूंजीवादी व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद जैसी **पश्चिमी विचारधाराओं** की बजाय **भारत की अपनी परंपराओं और मूल्यों** पर आधारित स्वदेशी विकास मॉडल का लक्ष्य रखता है।
- यह निम्नलिखित **तीन सिद्धांतों पर आधारित** है:
  - समष्टि की प्रधानता, न कि उसके किसी भाग की;
  - धर्म की सर्वोच्चता; और
  - समाज की स्वायत्तता।

समकालीन समय में एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांत

- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद** परंपराओं के साथ आधुनिक प्रगति को भी आत्मसात करता है।
- **सामाजिक एकीकरण और** जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करना।
- **अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान):** समाज के सबसे गरीब वर्गों का उत्थान करना।
  - **'सभी के लिए शिक्षा'** और **'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'** जैसे विचार उनके आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा में समाहित थे।
- नैतिक, पारदर्शी शासन(धर्म राज्य) की अवधारणा।
- **विकेंद्रीकरण,** एक आत्मनिर्भर ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करना।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में (1916-1968)

- वे मथुरा के एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, और राजनीतिक कार्यकर्ता थे।
- **पुस्तकें:** सम्राट चंद्रगुप्त, जगद्गुरु शंकराचार्य, आदि।
  - वे साप्ताहिक **पांचजन्य** और दैनिक पत्रिका **स्वदेश** के संपादक भी थे।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन गांधीजी के सर्वोदय (सभी का कल्याण), ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय के विरोध जैसे विचारों से मेल खाते हैं।

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़

✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र
✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2025 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

2026 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

10.1 भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF ELECTRIC PASSENGER CARS IN INDIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा योजना के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए।

मुख्य विशेषताएं

- **मंत्रालय और कार्यान्वयन:** भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries: MHI) द्वारा संचालित; परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा कार्यान्वित।
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष या अधिसूचित अवधि अनुसार।
- **पात्र निवेश:** नए संयंत्र, मशीनरी, चार्जिंग अवसंरचना, और संबंधित उपकरण की गुणवत्ता पर किया गया व्यय; सेकेंड हैंड/ नवीनीकृत संयंत्र, आदि पर किया गया व्यय इस हेतु **पात्र नहीं** होगा।
- **पात्रता:**
  - 10,000 करोड़ रुपये का वैश्विक ऑटो राजस्व होना चाहिए।
  - 3,000 करोड़ रुपये की वैश्विक अचल परिसंपत्ति निवेश।
  - भारत में 3 वर्षों में कम-से-कम 4,150 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता।
  - 3 वर्षों में 25% DVA; 5 वर्षों में 50% DVA
  - बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना अनिवार्य।
- **प्रदर्शन मानदंड:** सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) ऑटो योजना** के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे।
- **प्रमुख लाभ:**
  - 15% की सीमा शुल्क पर आयात की जाने वाली इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स (e-4W) की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष 8,000 तक सीमित होगी।
  - सीमा शुल्क दर में रियायत कुल 5 वर्षों के लिए लागू होगी।

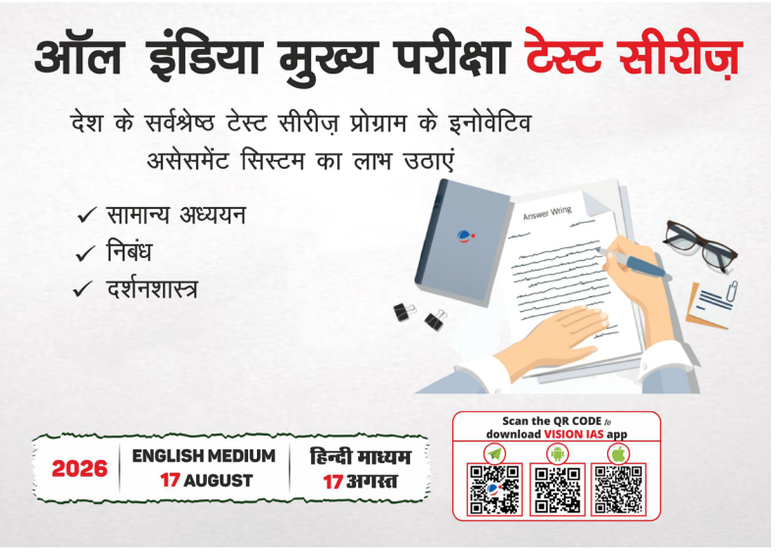

टॉपिक	मुख्य आंकड़े एवं तथ्य
आपातकाल के 50 साल	➲ **आपातकाल के दौरान प्रमुख संवैधानिक संशोधन** ➲ **38वां संशोधन (1975):** आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। ➲ **39वां संशोधन (1975):** इसने **चुनाव विवादों** को तय करने के तरीके में बदलाव किया। ➲ **42वां संशोधन (1976):** अनुच्छेद 31C के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई; **सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की शक्तियों को कई तरह से कम किया गया।** ➲ **लोक सभा** का कार्यकाल **5 साल से बढ़ाकर 6 साल** कर दिया गया था।
व्यक्तित्व अधिकार (PERSONALITY RIGHTS)	**भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएं** ➲ **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामला, 2011 (दिल्ली हाई कोर्ट):** इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। ➲ **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस (मद्रास हाईकोर्ट, 2015):** उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।
आदि कर्मयोगी कार्यक्रम (ADI KARMYOGI PROGRAMME)	➲ **केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि कर्मयोगी' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।** ➲ इसमें नागरिक-केंद्रित सोच और सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
भारत और शंघाई सहयोग संगठन (SCO)	**SCO के बारे में** ➲ **उत्पत्ति:**यह संगठन 1996 में **"शंघाई फाइव"** व्यवस्था से शुरू हुआ था। इसे औपचारिक रूप से **2001 में** शंघाई शिखर सम्मेलन में **रूस,** चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा **स्थापित किया गया था।** ➲ **मुख्य उद्देश्य:** ➜ सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और मित्रता को मजबूत करना। ➜ क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना। ➜ एक नवीन लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	**WTO के बारे में** ➲ **उत्पत्ति:** ➜ 1995 में मारकेश समझौते के बाद स्थापित। ➜ इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) का स्थान लिया है। ➜ 1986 से 1994 तक चली उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामस्वरूप WTO का गठन हुआ। ➲ **कार्य:** व्यापार समझौतों का प्रशासन, व्यापार वार्ता के लिए मंच, व्यापार विवादों का निपटारा, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना।

ग्रुप ऑफ सेवन (G-7)	**ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के बारे में** ➲ **उत्पत्ति:** 1975 में **ऊर्जा संकट** के चलते में आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित। ➲ **विकसित लोकतांत्रिक देशों** का एक अनौपचारिक समूह: फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा। ➲ **रूस** 1998-2014 तक इसका सदस्य था (तब इसे **G8 कहा जाता है**), **क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण** इसे समूह से निलंबित कर दिया गया था। ➲ **उद्देश्य: आर्थिक गवर्नेंस**, **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** और **ऊर्जा नीति** जैसे वैश्विक मुद्दों पर वार्षिक बैठकें।
जंगेजुर कॉरिडोर (ZANGEZUR CORRIDOR)	**ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर के बारे में** ➲ **अवस्थिति:** यह आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित 43 किलोमीटर लंबा परिवहन मार्ग है। ➲ **उद्देश्य: कैस्पियन सागर में अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नखचिवन** स्वायत्त **क्षेत्र** और आगे **तुर्किये से** जोड़ना। ➲ **भारत की चिंताएं: यह प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करके **चाबहार बंदरगाह** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण कॉरिडोर (INSTC)** में भारत के निवेश को प्रभावित कर सकता है, तथा भारत के **क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर सकता है।**
क्विक कॉमर्स (QUICK COMMERCE)	➲ भारत में क्विक कॉमर्स के **साल-दर-साल 75-100% तक बढ़ने की उम्मीद** है। ➲ **"डार्क स्टोर"** से तात्पर्य ऐसे खुदरा दुकान या गोदाम से है जिसका उपयोग केवल ऑनलाइन ऑर्डर के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है और जो आम जनता के लिए सुलभ नहीं है।
विमानन सुरक्षा (AVIATION SAFETY)	➲ यात्री यातायात (350 मिलियन से अधिक यात्री) के मामले में भारत **विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा** विमानन बाजार है। ➲ वैश्विक औसत के 5% की तुलना में **भारत में 15% पायलट महिलाएं** है। ➲ **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)** नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय है। ➲ 2250 किलोग्राम से अधिक कुल भार वाले विमान या टर्बोजेट की दुर्घटनाओं की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) करता है।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण (ASSET MONETIZATION)	➲ यह पूरी तरह उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक (सरकारी) परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के द्वारा **राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की नई या वैकल्पिक प्रक्रिया** है। ➲ **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)** शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका गठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) की गैर-प्रमुख (नॉन-कोर) परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया है।
सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (FINANCING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)	➲ सेविले प्रतिबद्धता विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए आवश्यक निवेश को उत्प्रेरित करने, ऋण संकट का समाधान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार लाने पर केंद्रित है। ➲ नए वित्तपोषण तंत्रों में विकास के लिए ऋण-विनिमय कार्यक्रम और **डेट "पॉज क्लॉज़" अलायन्स** शामिल हैं।
सतत विकास रिपोर्ट (2025) {SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT (2025)}	➲ सतत विकास रिपोर्ट (2025) में पहली बार **भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर आकर SDG सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल** हो गया है। ➲ भारत का स्कोर **100 में से 67 है।** ➲ SDG सूचकांक **2016** से हर साल सतत विकास रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN)** द्वारा जारी किया जा रहा है। ➲ 2030 तक 17 में से कोई भी वैश्विक लक्ष्य (SDG) पूरी तरह से हासिल होने की राह पर नहीं है।
डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP)	➲ DPIP को **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** की निगरानी और मार्गदर्शन में **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के रूप में विकसित किया जाएगा। ➲ इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बैंकों के बीच **वास्तविक इंटेलिजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत** करना है।
सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL)	➲ सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड (SMFCL), **सामुद्रिक क्षेत्रक में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** है। ➲ इसे पहले **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड** के नाम से जाना जाता था।
पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA	➲ **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन** जैसे कई देशों ने **छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों** के विकास की घोषणा की है। ➲ इनमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताएं, मानवरहित क्षमताएं** आदि तकनीकों के उपयोग होने की उम्मीद है।

सिल्वर नोटिस (SILVER NOTICE)	➲ सिल्वर नोटिस, **इंटरपोल की कलर-कोडेड नोटिस प्रणाली में एक नया नोटिस है।** ➲ इंटरपोल के **कलर कोडेड नोटिस, सदस्य देशों के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध** होते हैं।
ओशन डार्कनिंग (DARKENING OF THE OCEAN)	➲ वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक ज़ोन सिकुड़ता जा रहा है। ➲ **फोटिक ज़ोन सूर्यप्रकाशित परत (200 मीटर गहराई) होती** है, जहां **90% समुद्री जीवन** पाया जाता है।
ILO कन्वेंशन 192	➲ सदस्य देशों से **जैविक खतरों से बचाव और सुरक्षा** तथा **तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों** को शामिल करते हुए राष्ट्रीय नीतियां बनाने का आह्वान किया गया।
इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)	➲ यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए 95 बड़ी बिल्ली श्रेणी के **कई देशों और कई एजेंसियों का एक समूह (गठबंधन)** है। ➲ **इन बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं।** ➲ **उत्पत्ति: अप्रैल 2023 में लॉन्च** (भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर)। ➲ **संस्थापक सदस्य (16): अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, केन्या, नेपाल,** आदि। ➲ **भारत** IBCA का **मेजबान देश** और यहां इसका **सचिवालय** है।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI), 2025	➲ **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI), 2025 जारी किया। **मुख्य तथ्य** ➲ **स्वीडन पहले स्थान पर है,** उसके बाद **फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे हैं**। ➲ **भारत की रैंक 2024 में 63वें स्थान** से गिरकर 2025 में 71वें स्थान पर आ गयी है।
थर्स्टवेव (THIRSTWAVE)	➲ कम-से-कम **लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग** उस अवधि के लिए **अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक** हो। ➲ वाष्पीकरण मांग **तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप** सहित कई कारकों द्वारा संयोजित वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को मापती है।
सांस्कृतिक विनियोग (CULTURAL APPROPRIATION)	➲ जब कोई प्रभावशाली समूह किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं को ऐसे तरीके से अपनाता है, जिसे अनादरपूर्ण या शोषणकारी माना जाता है। **उदाहरण के लिए,** प्राडा पर भारत की पारंपरिक GI टैग वाली कोल्हापुरी चप्पलों से मिलती-जुलती सैंडल बेचने का आरोप लगाया गया
टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स	➲ छोटे शहरों (उदाहरण के लिए, जयपुर, पटना) के कंटेंट क्रिएटर्स जो भारत की "सांस्कृतिक पूंजी" (भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान जैसी गैर-आर्थिक परिसंपत्तियां जो सामाजिक गतिशीलता प्रदान करती हैं, पियरे बोरदियू की एक अवधारणा) को नया रूप दे रहे हैं।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026	➲ भारत के अब **54 विश्वविद्यालय** इस रैंकिंग में शामिल हैं (2015 में 11 विश्वविद्यालय थे), जिससे यह चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। **शीर्ष-स्तरीय प्रदर्शन: IIT दिल्ली 123वें** स्थान पर भारतीय संस्थानों में **सबसे ऊपर** है।
मैनोस्फीयर (MANOSPHERE)	➲ ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क, जो **पुरुषत्व (Masculinity) की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा** देता है **और नारीवाद विरोधी विचारों** पर आधारित है।
एक्सिओम-4 (एक्स-4) मिशन	➲ यह एक्सिओम स्पेस द्वारा NASA और SpaceX के बीच सहयोग से ISS (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) के लिए **चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** है।
DHRUVA (डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस)	➲ भारत के प्रत्येक परिवार को **एक विशिष्ट डिजिटल एड्रेस** प्रदान करने के लिए **डाक विभाग** द्वारा एक पहल विकसित की गयी है, जिसे DIGIPIN नामक 10-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक कोड का उपयोग करके बनाया गया है।
जीन-एडिटेड भेड़	➲ CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से **मांसपेशियों की वृद्धि करने के लिए एक मेमने में मायोस्टेटिन जीन को एडिट** किया और भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ तैयार की।
वजन कम करने वाली दवाएं (WEIGHT LOSS DRUG)	➲ भारत ने अपनी वजन कम करने वाली दवा **वेगोवी (सेमाग्लूटाइड)** लॉन्च की। इसका काम भूख को कम करना है और यह शरीर में मौजूद GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) नामक हार्मोन की कॉपी करता है।

आईएनएस कौंडिन्य और टंकाई विधि	**INS कौंडिन्य के बारे में** ➲ यह **अजंता की गुफाओं के चित्रों** में दर्शाए गए **5वीं शताब्दी** के जहाज पर आधारित है। ➲ यह परियोजना **संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होदी इनोवेशन्स** के बीच **त्रिपक्षीय समझौते** के जरिए शुरू की गई थी। **टंकाई विधि के बारे में** ➲ यह जहाज निर्माण की **2000 वर्ष पुरानी** तकनीक है, जिसे **'टंकाई जहाज निर्माण विधि'** के नाम से जाना जाता है।
कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोवलाई माणिक्का मालाई (KUMBAKONAM VETRILAI AND THOVALAI MAANIKKA MAALAI)	**कुंभकोणम वेत्रिलाई के बारे में** ➲ यह एक **पान (pan) का पत्ता** होता है। ➲ यह मुख्य रूप से तंजावुर के उपजाऊ **कावेरी नदी बेसिन** में उगाया जाता है। ➲ इनमें **चेविकोल** नामक तत्व पाया जाता है, जो अपनी उच्च **एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी विशेषताओं** के लिए जाना जाता है। **थोवलई माणिक्का मालाई के बारे में** ➲ यह एक खास तरह की माला है, जो केवल **थोवलई** में बनाई जाती है। ➲ इसमें **फूलों को सावधानी से मोड़ा** जाता है और उन्हें सटीक **ज्यामितीय** (geometrical) पैटर्न में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे **रत्नों (खासकर माणिक/रूबी)** जैसे दिखें।

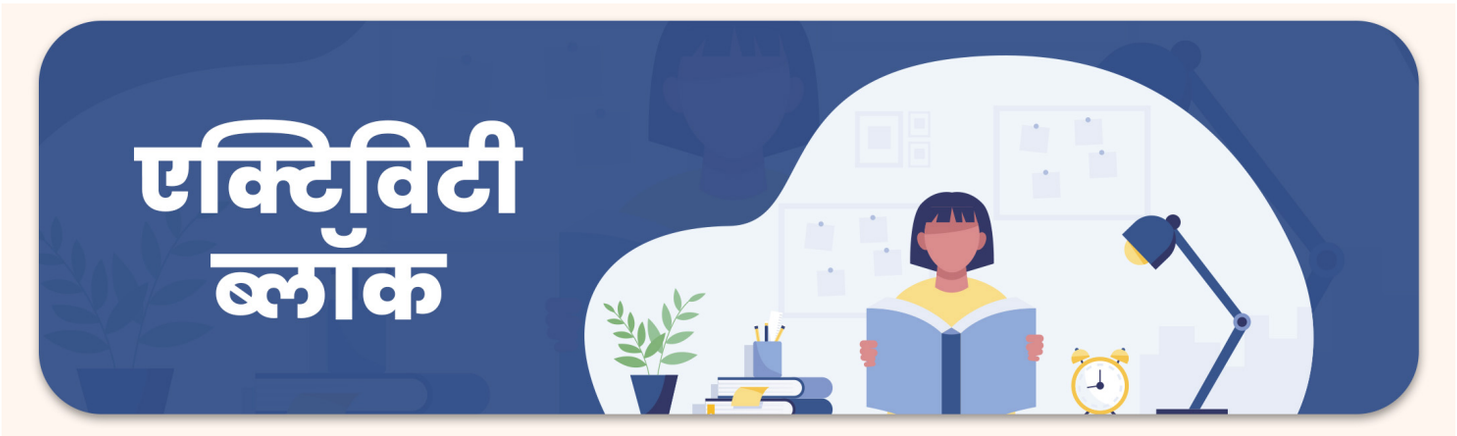

12.1. MCQS

1. भारत में नार्को-एनालिसिस टेस्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनैच्छिक नार्को-टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन करते हैं।
2. स्वैच्छिक नार्को-टेस्ट किसी आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वैच्छिक रूप से किए गए नार्को-टेस्ट का भी साक्ष्य मूल्य सीमित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
2. इसकी स्थापना एसोचैम, CII, और फिक्की की सिफारिशों पर की गई थी।
3. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

3. ECINET ऐप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह चुनावों के दौरान मतदाता के मतदान पर रियल टाइम डेटा प्रदान करता है।
2. यह निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत फॉर्म 17C का स्थान लेता है।
3. यह इंडेक्स कार्ड प्रकाशित करने में मदद करता है, जिसमें चुनाव के बाद का विस्तृत डेटा होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना।
2. SCO में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, और कोई भी आपत्ति जताने से स्वीकृति में बाधा उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत G7 का स्थायी सदस्य है।
2. भारत ने कनाडा द्वारा 2025 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

6. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य WTO का नहीं है?
(a) व्यापार समझौतों का प्रशासन करना
(b) आर्थिक प्रतिबंध लगाना
(c) व्यापार विवादों का निपटारा करना
(d) व्यापार क्षमता का निर्माण करना

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत SCO फ्रेमवर्क के अंतर्गत BRI का समर्थन करता है।
2. जंगेजुर कॉरिडोर चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश को दरकिनार कर उसे प्रभावित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

8. ग्रामीण भारत के उपभोग पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है/ हैं?
1. 2023-24 में ग्रामीण भारत में अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) शहरी क्षेत्रों की तुलना में

अधिक दर से बढ़ा।
2. MPCE में शहरी-ग्रामीण अंतराल पिछले दो वर्षों से बढ़ रहा है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-खाद्य मदें औसत मासिक खर्च को तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं।

सही कूट का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

9. भारत में क्विक कॉमर्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्विक कॉमर्स आमतौर पर 3-4 दिनों के भीतर डिलीवरी की गारंटी देता है।
2. "डार्क स्टोर्स" क्विक पिक-अप के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ खुदरा दुकानें हैं।
3. COVID-19 महामारी के कारण क्विक कॉमर्स को अपनाने में तेजी लाई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

10. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पिछले दो वित्तीय वर्षों में भारत में निवल FDI अंतर्वाह में लगातार वृद्धि हुई है।
2. भारत में FDI हेतु स्वचालित मार्ग के लिए RBI या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
3. लॉटरी व्यवसाय उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

11. भारत में विमानन सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत फ्रेमवर्क शिकागो कन्वेंशन के परिशिष्ट 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक तय करता है?

(a) नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA)
(b) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)
(c) नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)
(d) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)

12. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. सिल्वर नोटिस का उपयोग भगोड़े अपराधियों की संपत्ति का पता लगाने और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है।
2. रेड नोटिस प्रत्यर्पण पर किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है।
3. इंटरपोल के नोटिस सदस्य देशों द्वारा लागू किए जाने वाले बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

13. रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की जाती है।
2. यह IPCC और IPBES के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहाकारी मंच है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

14. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CDRI का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
2. CDRI की स्थापना भारत द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

15. ओशन डार्कनिंग से महासागर की कौन सी परत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है?

(a) अफोटिक ज़ोन
(b) बेन्थिक ज़ोन
(c) फोटिक ज़ोन
(d) नेरिटिक ज़ोन

16. थर्स्टवेव क्या है?

(a) तीन या अधिक दिनों की अत्यधिक वर्षा की अवधि जिसके कारण फसलें जलमग्न हो जाती हैं
(b) तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक आर्द्रता का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एक शब्द
(c) जब कम से कम तीन लगातार दिनों की अवधि के लिए दैनिक वाष्पीकरण की मांग अपने ऐतिहासिक 90वें प्रतिशत मान से अधिक हो जाती है
(d) एक मौसम पैटर्न जहाँ शुष्क हवाएँ एक सप्ताह से अधिक समय तक लगातार चलती हैं

17. वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर MPOWER का कौन सा नीतिगत उपाय सबसे कम अपनाया गया है?

(a) लोगों को तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना।
(b) तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और स्पोंसरशिप पर प्रतिबंध लगाना।
(c) तंबाकू पर कर बढ़ाना।
(d) तंबाकू का सेवन छोड़ने में मदद की पेशकश करना।

18. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत इस रैंकिंग में अमेरिका और ब्रिटेन से आगे निकलकर सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है।
2. IIT दिल्ली सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान है।
3. यह रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

19. एक्सिओम-4 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
(b) इस मिशन में भारत, रूस, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे।
(c) इस मिशन के तहत फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था।
(d) इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नया मॉड्यूल तैनात करना था।

20. प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कुछ विशेष प्रतीकों और नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
2. यह अधिनियम केवल पूरे भारत क्षेत्र में ही लागू होता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर नहीं।
3. इसमें "प्रतीक" की परिभाषा के अंतर्गत मुहर, ध्वज और चित्रात्मक प्रस्तुति शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) कोई नहीं

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements)

1. युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। **(T/F)**
2. आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और चेंजमेकर्स का एक समूह तैयार करना है। **(T/F)**
3. भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। **(T/F)**
4. भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का संस्थापक सदस्य है। **(T/F)**
5. वर्तमान में WTO का विवाद निपटान तंत्र निष्क्रिय है। **(T/F)**
6. जंगेजुर कॉरिडोर भारत को सीधे मध्य एशिया से जोड़ेगा। **(T/F)**
7. परिसंपत्ति मुद्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य हमेशा सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विनिवेश करना होता है। **(T/F)**
8. सतत विकास रिपोर्ट (2025) के अनुसार, 2030 तक 17 में से कोई भी वैश्विक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल होने की राह पर नहीं है। **(T/F)**
9. लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए नए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों ने PSL क्षेत्रों के लिए अनिवार्य आवंटन को ANBC के 75% तक बढ़ा दिया है। **(T/F)**
10. अभ्यास खान क्वेस्ट एक बहुपक्षीय अभ्यास है। **(T/F)**
11. PASSEX भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। **(T/F)**
12. विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI) जारी किया। **(T/F)**
13. हाल ही में, घोषित रामसर स्थल, खीचन और मेनार उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। **(T/F)**
14. ग्रीन इंडिया मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है। **(T/F)**
15. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन की सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है। **(T/F)**
16. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। **(T/F)**
17. "मैनोस्फीयर" एक ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क है, जो लैंगिक समानता की वकालत करता है और नारीवादी सिद्धांतों का समर्थन करता है। **(T/F)**
18. हाल ही में, भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से महिला कैडेटों का पहला बैच स्नातक हुआ है। **(T/F)**
19. टंकाई विधि जहाज निर्माण की 2000 वर्ष पुरानी तकनीक है जिसे टंकाई/ सिलाई जहाज निर्माण विधि के नाम से जाना जाता है। **(T/F)**
20. **तमिलनाडु** के कुंभकोणम वेत्रिलाई और थोवलई माणिक्का मालाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया। **(T/F)**

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. AI-जनित डीपफेक और वॉयस क्लोनिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के दायरे और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
2. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के अंतर्गत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाने के भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
3. भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों पर इजरायल-संयुक्त राज्य अमेरिका-ईरान संघर्ष के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
4. भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है, फिर भी विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने में कई संस्थागत, अवसंरचनात्मक और नियामक चुनौतियां बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
5. सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में वृद्धि के बावजूद, भारत में वित्त वर्ष 2025 में नेट FDI में भारी गिरावट देखी गई। इस प्रवृत्ति के कारणों का परीक्षण कीजिए और नेट FDI प्रवाह को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
6. "तटीय क्षेत्र आर्थिक जीवनरेखा होने के साथ-साथ पारिस्थितिक जोखिम वाले क्षेत्र भी हैं।" जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के तटीय क्षेत्रों की कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए। भारत राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों के माध्यम से इन जोखिमों का समाधान कैसे कर रहा है? (150 शब्द, 10 अंक)
7. तेज़ी से शहरीकृत हो रहे भारत में आपदाओं को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित भीड़ प्रबंधन आवश्यक है। हाल की घटनाओं और NDMA दिशानिर्देशों के संदर्भ में भीड़ आपदा प्रबंधन के प्रति भारत के वर्तमान दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
8. हालांकि सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं का प्रवेश लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी गहरी संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और एक अधिक समावेशी और प्रभावी रक्षा बल बनाने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
9. तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत ने तम्बाकू नियंत्रण में वैश्विक नेतृत्व दिखाया है। भारत में तम्बाकू महामारी से निपटने के लिए चुनौतियों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
10. "अजंता की चित्रकारी न केवल प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, बल्कि ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आख्यानों के मूल्यवान स्रोत भी हैं।" उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
11. "अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान संघवाद और मौलिक अधिकारों की कीमत पर संघ को मजबूत करते हैं।" संवैधानिक प्रावधानों और उनके निहितार्थों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
12. विश्व व्यापार संगठन में सुधार लंबे समय से लंबित हैं। वैश्विक व्यापार प्रणाली के संदर्भ में, भारत की स्थिति और सुधार प्राथमिकताओं का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

13. "भारत में ग्रामीण उपभोक्ता बाजार का उदय समावेशी विकास का प्रमाण है, फिर भी यह चुनौतियों से रहित नहीं है। इस विकास में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए और इससे जुड़ी चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस ग्रामीण उपभोक्ता-आधारित विकास की स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।" (250 शब्द, 15 अंक)
14. "परिसंपत्ति मुद्रीकरण को भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। इसके आलोक में, परिसंपत्ति मुद्रीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और भारतीय संदर्भ में इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। इसके सफल कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप सुझाइए?" (250 शब्द, 15 अंक)
15. "AMCA जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास भारत की तकनीकी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता की खोज को दर्शाता है।" इस संदर्भ में, AMCA की विशेषताओं और महत्व पर चर्चा कीजिए और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)
16. कृषि वानिकी केवल एक कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि जलवायु लचीलापन और ग्रामीण स्थिरता के लिए एक रणनीतिक उपकरण है।" भारत के सतत विकास लक्ष्यों में कृषि वानिकी के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से चुनौतियों और हाल के सुधारों पर भी प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)
17. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स का उदय भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो प्रभाव को लोकतांत्रिक बनाता है लेकिन नई चुनौतियां भी पेश करता है। भारतीय समाज और इसकी अर्थव्यवस्था पर इस घटना के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
18. एक्सिओम-4 मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गगनयान प्रोग्राम और भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक विकास के लिए इस मिशन के महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत के अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्रक्षेपित करने में आने वाली प्रमुख तकनीकी बाधाओं का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
19. CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन-एडिटेड भेड़ के हालिया विकास के साथ, पशुओं में जीन संपादन को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत के कृषि और पशुधन क्षेत्रकों के लिए इस तकनीक के संभावित लाभों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी प्रमुख नैतिक चिंताओं का भी समाधान कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
20. "भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं ने न केवल उसके व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया, बल्कि उसकी आधुनिक नौसैनिक और कूटनीतिक पहलों की नींव भी रखी।" भारत की समुद्री विरासत को पुनः प्राप्त करने के हालिया प्रयासों के आलोक में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

2026 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

13.1. MCQ के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion)

1. उत्तर: B.
व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनैच्छिक नार्को-परीक्षण अनुच्छेद 20(3) (किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।
- **कथन 2 सही नहीं है:** स्वैच्छिक नार्को-परीक्षण दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
- **कथन 3 सही है:** स्वेच्छा से किए जाने पर भी, इसका साक्ष्य मूल्य सीमित होता है; केवल प्राप्त नई जानकारी ही स्वीकार्य हो सकती है।

2. उत्तर: B.
व्याख्या:

- **कथन 1 सही नहीं है:** QCI एक गैर-लाभकारी संगठन (वैधानिक नहीं) है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
- **कथन 2 सही है:** इसका गठन उद्योग संघों—ASSOCHAM, CII और FICCI—के साथ साझेदारी में किया गया था।
- **कथन 3 सही है:** अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा उद्योग जगत की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

3. उत्तर: B.
व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** ECINET मतदाता मतदान पर लगभग वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** फॉर्म 17C, 1961 के नियमों के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है; ECINET इसका स्थान नहीं लेता है।
- **कथन 3 सही है:** यह ऐप इंडेक्स कार्ड, विस्तृत डेटा वाला एक चुनाव-पश्चात दस्तावेज़, के प्रकाशन में सहायता करता है।

4. उत्तर: C
व्याख्या:

- भारत, पाकिस्तान के साथ, 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना। इसलिए, **कथन 1 सही है।**
- SCO में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। किसी एक देश की आपत्ति इसके निर्णय लेने में बाधा डालती है। इसलिए, **कथन 2 सही है।**

5. उत्तर: B
व्याख्या:

- भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अक्सर आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। **कथन 1 सही नहीं है।**
- भारत ने कनाडा में आयोजित 2025 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। **कथन 2 सही है।**

6. उत्तर B
व्याख्या:

- **WTO प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:**
- व्यापार समझौतों का प्रशासन।
- वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।
- व्यापार विवादों का निपटारा।
- राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना
- व्यापार क्षमता का निर्माण।

7. उत्तर B
व्याख्या:

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से संबंधित संप्रभुता के मुद्दों के कारण भारत BRI का समर्थन नहीं करता है। इसलिए, **कथन 1 सही नहीं है।**
- ज़ंगेज़ुर गलियारा अज़रबैजान को आर्मेनिया को दरकिनार करते हुए सीधे अपने एक्सक्लेव नखचिवन से जुड़ने की अनुमति देगा और ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के रणनीतिक निवेश के लिए खतरा पैदा करेगा। इसलिए, **कथन 2 सही है।**

8. उत्तर: B
व्याख्या:

- **कथन 1 सही है** क्योंकि ग्रामीण MPCE में शहरी क्षेत्रों के 8.3% की तुलना में 9.2% की वृद्धि हुई।
- **कथन 2 सही नहीं है** क्योंकि MPCE में शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ।
- **कथन 3 सही है** क्योंकि गैर-खाद्य वस्तुएं शहरी उपभोग पैटर्न

की नकल करते हुए औसत मासिक खर्च पर हावी हो रही हैं।

9. उत्तर: C
व्याख्या:
- **कथन 1 सही नहीं है:** क्विक कॉमर्स आमतौर पर एक घंटे या उससे कम समय में डिलीवरी करता है, जबकि ई-कॉमर्स में आमतौर पर 3-4 दिन लगते हैं।
- **कथन 2 सही नहीं है:** डार्क स्टोर केवल ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए हैं और जनता के लिए सुलभ नहीं हैं।
- **कथन 3 सही है:** COVID-19 महामारी ने संपर्क रहित डिलीवरी की मांग को बढ़ावा दिया, जिससे क्विक कॉमर्स अपनाने में तेजी आई।

10. उत्तर: B
व्याख्या:
- **कथन 1 सही नहीं है:** वित्त वर्ष 2025 में भारत का नेट FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 96% कम हो गया।
- **कथन 2 सही है:** स्वचालित मार्ग के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** लॉटरी व्यवसाय भारत में एक FDI निषिद्ध क्षेत्र है।

11. उत्तर: C
- **व्याख्या:** नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), ICAO के शिकागो कन्वेंशन के परिशिष्ट 17 के अनुसार विमानन सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।

12. उत्तर: A
व्याख्या:
- **कथन 1 - सही:** हाल ही में, शुरू किया गया सिल्वर नोटिस विशेष रूप से भगोड़ों या आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति का पता लगाने और जानकारी एकत्र करने के लिए है।
- **कथन 2 - सही:** रेड नोटिस एक प्रसिद्ध इंटरपोल नोटिस है जो प्रत्यर्पण लंबित व्यक्ति के स्थान और अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध करता है।
- **कथन 3 – सही नहीं:** इंटरपोल नोटिस बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं हैं। ये सहयोग के लिए अनुरोध होते हैं, और सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उन पर कार्रवाई करनी होती है।

13. उत्तर: B
व्याख्या:
- रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति पैनल का संचालन UNEP द्वारा किया जाता है, न कि WHO द्वारा।
- यह IPCC और IPBES सहित एक वैज्ञानिक तिकड़ी का हिस्सा है।

14. उत्तर: B
व्याख्या:
- CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिनेवा में नहीं।
- CDRI की शुरुआत भारत द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी।

15. उत्तर C
व्याख्या:
- महासागर के अंधकारमय होने से फोटिक जोन (ऊपरी 200 मीटर) प्रभावित होता है, जहां अधिकांश समुद्री जीवन मौजूद है।

16. उत्तर C
व्याख्या:
- थर्स्टवेव वह स्थिति होती है जब कम-से-कम लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक हो जाती है।

17. उत्तर: C.
- **व्याख्या:** तंबाकू पर कर बढ़ाना।

18. उत्तर: B.

19. उत्तर: C
व्याख्या
- यह मिशन एक्सिओम स्पेस, नासा और स्पेसएक्स के बीच एक सहयोग था, और इसे फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर प्रक्षेपित किया गया था।

20. उत्तर: B.
व्याख्या:
- **कथन 1 सही है:** यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वाणिज्यिक, व्यावसायिक या ट्रेडमार्क उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट प्रतीकों और नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** यह अधिनियम पूरे भारत में और विदेशों में भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है - इस संबंध में इसका अतिरिक्त-क्षेत्राधिकार है।
- **कथन 3 सही है:** यह अधिनियम में "प्रतीक" की परिभाषा के अंतर्गत प्रतीक, मुहर, ध्वज, प्रतीक चिन्ह, राज्यचिह्न या चित्रात्मक प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

13.2 ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

उत्तर:

1. T	**2. T**	**3. T**	**4. F**	**5. T**	**6. F**	**7. F**	**8. T**	**9. F**	**10. T**
11. T	**12. T**	**13. F**	**14. T**	**15. T**	**16. F**	**17. F**	**18. F**	**19. F**	**20. F**

13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण

1. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** व्यक्तित्व अधिकारों को परिभाषित कीजिए और उनके घटकों (प्रचार का अधिकार और निजता का अधिकार) की व्याख्या कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** व्यक्तित्व अधिकारों के लिए खतरों पर प्रकाश डालिए। न्यायिक मान्यता पर भी चर्चा कीजिए (जैसे पुट्टस्वामी निर्णय, रजनीकांत मामला)। वर्तमान कानूनी ढाँचे में सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** विशेष रूप से AI के दुरुपयोग के आलोक में, व्यापक कानून की आवश्यकता पर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

2. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** SCO और भारत की सदस्यता का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
   - **मुख्य भाग:** भारत के सिद्धांतों (आतंकवाद-विरोधी, BR-विरोधी रुख) को उदाहरणों के साथ समझाइए: पहलगाम हमला, BRI का समर्थन न करना। मध्य एशियाई पहुँच के एक साधन के रूप में SCO की व्याख्या कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** भारत की चुनिंदा भागीदारी और चुनौतियों (चीन-पाकिस्तान एक्सिस) का उल्लेख कीजिए और आगे की राह प्रस्तुत कीजिए। (सिद्धांत-आधारित कूटनीति)

3. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** हाल के संघर्ष की समयरेखा से शुरुआत कीजिए और संक्षेप में इसके पीछे के कारणों का वर्णन कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** व्यापार और संपर्क संबंधी व्यवधानों (चाबहार, IMEC), प्रवासियों और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच भारत के कूटनीतिक संतुलन की व्याख्या कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** भारत की संभावित मध्यस्थ भूमिका का सुझाव दीजिए।

4. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** विमानन क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति पर बल दीजिए।
   - **मुख्य भाग:** जनशक्ति की कमी, असंतुलित पूंजी आवंटन और पुराने बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर ध्यान दीजिए।
   - **निष्कर्ष:** ICAO मानकों के साथ संरेखण, AAIB की स्थापना और दिल्ली घोषणा जैसे प्रयासों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

5. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** उल्लेख कीजिए कि भारत लगातार महत्वपूर्ण सकल FDI प्रवाह को आकर्षित कर रहा है।
   - **मुख्य भाग:** प्रत्यावर्तन, भारत से बाहर जाने वाली FDI का बढ़ना, नीति उदारीकरण और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारण।
   - **निष्कर्ष:** जन विश्वास अधिनियम, PLI योजनाओं और क्षेत्रीय सीमा में वृद्धि जैसे सुधारों का उल्लेख कीजिए।

6. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** तटीय क्षेत्र कैसे जीवन रेखा हैं, इस पर चर्चा करके शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता का उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह सुझाइए।

7. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** भगदड़ की कुछ हालिया घटनाओं का संदर्भ देकर शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** भगदड़ को एक आपदा के रूप में परिभाषित कीजिए और इसके पीछे के कारण बताइए।
   - **निष्कर्ष:** भारत के हालिया दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरणों के साथ बताइए कि तकनीक कैसे मदद कर सकती है।

8. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** हाल के सकारात्मक सुधारों को स्वीकार करते हुए शुरुआत कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** महिलाओं की भागीदारी का महत्व, निरंतर चुनौतियां और आगे की राह/उपाय
   - **निष्कर्ष:** आधुनिक युद्ध अधिक तकनीक-केंद्रित होते जा रहे हैं और महिलाओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना केवल समानता का मुद्दा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है।

9. **दृष्टिकोण:**
   - **परिचय:** विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त, एक प्रमुख तंबाकू उत्पादक एवं निर्यातक, और तंबाकू नियंत्रण उपायों में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की दोहरी स्थिति पर प्रकाश डालिए।
   - **मुख्य भाग:** COTPA, 2003, NTCP और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन।
   - **निष्कर्ष:** आर्थिक और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में संतुलन बनाए रखने के लिए तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों में अधिक कठोर

कराधान, सख्त प्रवर्तन और वैकल्पिक आजीविका के लिए समर्थन का सुझाव दीजिए।

10. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** अजंता की गुफाओं के चित्रों की कलात्मक उत्कृष्टता और तकनीकों को समझाइए।
- **मुख्य भाग:** उनके धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक आख्यानों (मुख्यतः बौद्ध) की व्याख्या कीजिए। संक्षेप में उनके ऐतिहासिक मूल्य की सराहना कीजिए—जैसे कि वास्तविक घटनाओं या राजा पुलकेशिन द्वितीय जैसे व्यक्तियों के चित्रण में।
- **निष्कर्ष:** यह प्रदर्शित कीजिए कि ये चित्रकलाएँ विश्व के साथ भारत के जुड़ाव (जैसे, फारसी दूतावास) और मूल्यों (जैसे, करुणा, बलिदान) को कैसे प्रदर्शित करती हैं।

11. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के संवैधानिक ढांचे का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** संवैधानिक प्रावधानों, केंद्र-राज्य संबंधों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों पर इसके प्रयोग के प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन (जैसे विशेष बहुमत, निरसन प्रावधान) के बारे में संक्षेप में बताइए।

12. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** विश्व व्यापार संगठन और वर्तमान गतिरोध के बारे में संक्षेप में बात करके शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** विश्व व्यापार संगठन से जुड़ी भारत की मांगों और चिंताओं की व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष:** सुधार के लिए वैश्विक सहयोग तंत्र सुझाइए।

13. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** भारत के ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में हाल ही में हुई मजबूत वृद्धि और भारत की उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था के एक नए इंजन के रूप में इसके महत्व का संक्षेप में परिचय दीजिए।
- **मुख्य भाग:** विकास में योगदान देने वाले कारक, चिंताएँ/चुनौतियाँ और स्थिरता के उपाय।
- **निष्कर्ष:** ग्रामीण भारत, भारत के उपभोक्ता-आधारित विकास पथ का इंजन बनने के लिए तैयार है।

14. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण को परिभाषित कीजिए, संदर्भ प्रदान करने के लिए NHAI की रणनीति और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता, भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के मॉडल (संक्षेप में उल्लेख कीजिए), परिसंपत्ति मुद्रीकरण में प्रमुख बाधाएँ और आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेपों की व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण कैसे है।

15. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तकनीकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
- **मुख्य भाग:** AMCA परियोजना की प्रमुख विशेषताओं और रणनीतिक एवं भू-राजनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। विकास और उत्पादन में चुनौतियों का आकलन कीजिए।
- **निष्कर्ष:** इनसे निपटने के तरीकों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

16. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** कृषि वानिकी और इसकी 2014 की नीति को परिभाषित कीजिए।
- **मुख्य भाग:** समझाइए कि कृषि वानिकी जलवायु लचीलापन कैसे लाती है और यह सतत विकास में कैसे मदद कर सकती है।
- **निष्कर्ष:** चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाले सुधारों पर चर्चा कीजिए।

17. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** "सांस्कृतिक पूंजी" (बौर्डियू) को परिभाषित कीजिए और समझाइए कि कैसे टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स पारंपरिक, महानगर-केंद्रित मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं।
- **मुख्य भाग:** सकारात्मक प्रभाव, चुनौतियाँ और चिंताएँ।
- **निष्कर्ष:** संक्षेप में यह बताकर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए कि टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स एक अधिक समावेशी और विविध सांस्कृतिक विमर्श का सूत्रपात कर रहे हैं।

18. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** एक्सिओम-4 मिशन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और गगनयान मिशन के संदर्भ में इसके संदर्भ का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** गगनयान और भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्व और भारत के लिए प्रमुख तकनीकी बाधाएं।
- **निष्कर्ष:** बताइए कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किस प्रकार सहायता करेगा।

19. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** जीन एडिटिंग (विशेष रूप से CRISPR-Cas9) की परिभाषा और हालिया उपलब्धि का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** कृषि और पशुधन के लिए संभावित लाभ और प्रमुख नैतिक चिंताएँ।
- **निष्कर्ष:** यह बताते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए कि हालांकि जीन एडिटिंग भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए अपार संभावनाएं रखता है, फिर भी एक सुदृढ़ नियामक ढाँचा स्थापित करना अनिवार्य है।

20. दृष्टिकोण:
- **परिचय:** व्यापार, संस्कृति और नौसैनिक शक्ति में भारत की ऐतिहासिक समुद्री विरासत पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

- **मुख्य भाग:** समुद्री विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए इस विरासत को समकालीन पहलों (जैसे INSV कौंडिन्य, सागरमाला, आदि) से जोड़िए।
- **निष्कर्ष:** संक्षेप में बताइए कि कैसे इस विरासत को 21वीं सदी में सॉफ्ट पावर और समुद्री कूटनीति के लिए एक उपकरण के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

ऑप्शनल सब्जेक्ट
टेस्ट सीरीज़

✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र
✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

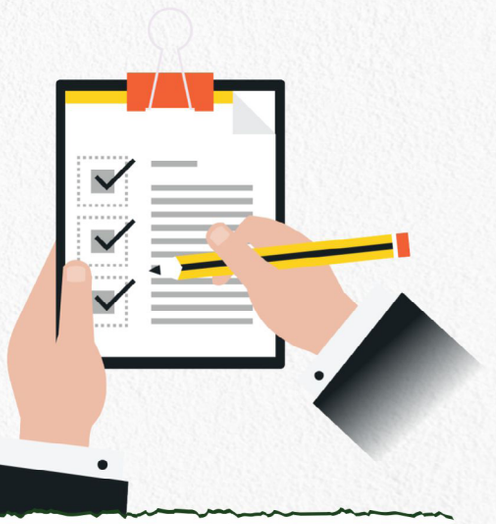

2025 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

2026 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

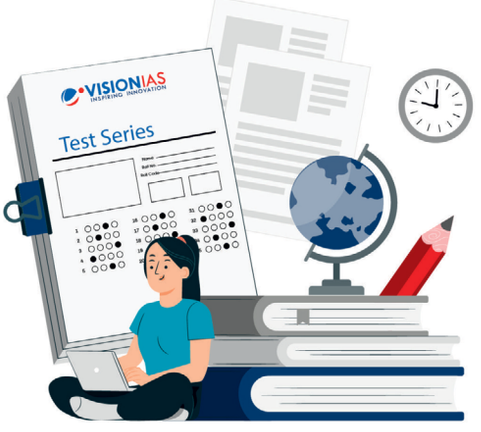

2026 | ENGLISH MEDIUM 17 AUGUST | हिन्दी माध्यम 17 अगस्त

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

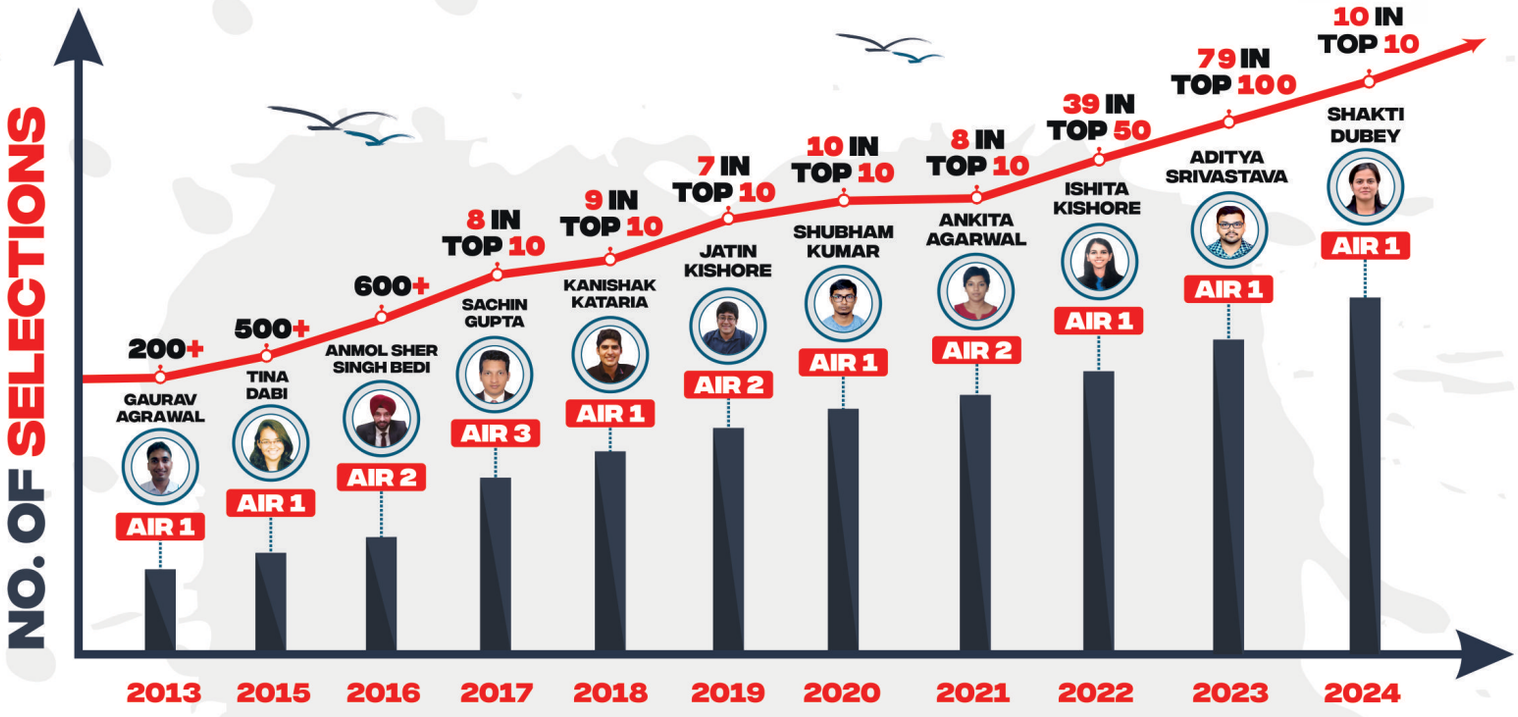

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 7 AUGUST, 11 AM | 14 AUGUST, 8 AM | 19 AUGUST, 5 PM
22 AUGUST, 11 AM | 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम | **28 अगस्त, 2 PM**

AHMEDABAD: 12 JULY | **BENGALURU: 25 AUG** | **BHOPAL: 18 AUG** | **CHANDIGARH: 18 JUNE**

HYDERABAD: 3 SEP | **JAIPUR: 5 & 10 AUG** | **JODHPUR: 10 AUG** | **LUCKNOW: 29 AUG** | **PUNE: 14 JULY**

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 28 अगस्त, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 10 अगस्त**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

Shakti Dubey

Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

Shah Margi Chirag

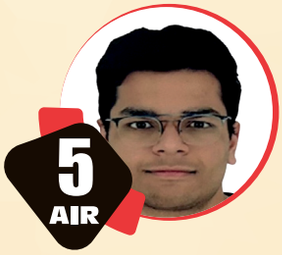

Aakash Garg

Komal Punia

Aayushi Bansal

Raj Krishna Jha

Aditya Vikram Agarwal

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

Ankita Kanti

Ravi Raaz

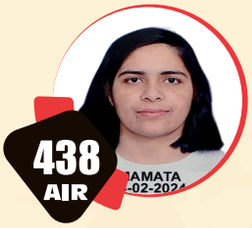

Mamata

Sukh Ram

Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची